



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 23, 2010/भाद्र 1, 1932

No. 243]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 23, 2010/BHADRA 1, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2010

अंतिम जाँच परिणाम

विषय : ओमान, सऊदी अरब और सिंगापुर के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पोलीप्रोपीलीन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच ।

सं. 14/5/2009-डीजीएडी.—यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण और क्षति निर्धारण), नियमावली, (जिसे एतदपश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ओमान, सऊदी अरब और सिंगापुर के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "पोलीप्रोपीलीन" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश की ।

क. मामले की पृष्ठभूमि:

2. अधिनियम, और पाटनरोधी नियमावली को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) को घरेलू उद्योग की ओर से मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. का एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें ओमान, सऊदी अरब तथा सिंगापुर (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की या वहाँ से निर्यातित "पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमोपोलीमर एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पोलीमर)" (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया था ।

3. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों की संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में जांच शुरू करने का निर्णय लिया । प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरू करने से पूर्व आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत स्थित संबद्ध देशों के उच्चायोग/दूतावासों को अधिसूचित किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति

का आरोप लगाया गया था । प्राधिकारी ने आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने जिसे यदि वसूल किया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए 24 फरवरी, 2009 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया ।

4. प्राधिकारी ने उप शीर्ष 39021000 तथा 39023000 के अंतर्गत आने वाली ओमान, सऊदी अरब तथा सिंगापुर के मूल की या वहां से निर्यातित "पोलीप्रोपीलीन" के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की । प्रारंभिक जांच परिणाम 15 जून, 2009 की अधिसूचना सं. 14/5/2009-डीजीएडी के तहत अधिसूचित किए गए थे ।

ख. प्रक्रिया

5. इस जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- i. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत के बारे में भारत स्थित संबद्ध देशों के उच्चायोग/दूतावासों को सूचित किया गया था ।
- ii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 24 फरवरी, 2009 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में स्थित संबद्ध देश के उच्चायोगों/दूतावासों, संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, उसके पास उपलब्ध पत्रों के अनुसार ज्ञात आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग को भेजी थीं । इस जांच के पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समयावधिक के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दायर करें और लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं । निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावलियों की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची के साथ संबद्ध देशों के उच्चायोग/दूतावासों को भी इस अनुरोध के साथ भेजी गईं थीं कि वे निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें ।
- iii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों और भारत में स्थित संबद्ध देशों के उच्चायोगों/दूतावासों को घरेलू उद्योग की ओर से दायर आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति उपलब्ध कराई गई थी ।
- iv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजी गईं थीं:

1. एडवांस्ड पोलीप्रोपीलीन कंपनी, सऊदी अरब
2. सेबिक बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन, सऊदी अरब
3. टासनी-नेशनल इंडस्ट्रलाइजेशन कंपनी, सऊदी अरब
4. एक्सोनमोबिल केमिकल कंपनी, सिंगापुर 098633
5. ओमान पोलीप्रोपीलीन एलएलसी, ओमान

i. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया है:

1. मै ओमान पोलीप्रोपीलीन एलएलसी, ओमान

2. मै. एडवांस्ड. पोलीप्रोपीलीन कंपनी, सऊदी अरब
3. मै. विनमार इंटरनेशनल लि.
4. मै. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन, सऊदी अरब (सेबिक)
5. मै. सऊदी यूरोपियन पेट्रोकेमिकल कंपनी (आई बी एन जहार), सऊदी अरब
6. मै. स. सऊदी यांबू पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट) सऊदी अरब
7. मै. सऊदी पोलीयोल्फिन्स कंपनी, सऊदी अरब
8. मै. नेशनल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रलाइजेशन मार्केटिंग कंपनी, सऊदी अरब
9. मै. बसेल इंटरनेशनल एफजैडई, सऊदी अरब
10. मै. एक्सोन मोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक, सऊदी अरब
11. मै. एक्सोन मोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक, सिंगापुर
12. मै. इटोचू प्लास्टिक्स पीटीई लि.
13. मै. मरुबेनी केमिकल एशिया पैसिफिक पीटीई लि., सिंगापुर
14. मै. सुमितोमो केमिकल एशिया पीटीई लि., सिंगापुर
15. मै. सुमितोमो कार्पोरेशन एशिया पीटीई लि., सिंगापुर
16. मै. दि. पोलीयोल्फिन कंपनी (सिंगापुर) पीटीई लि.
17. मै. टोयेटा सूशो (सिंगापुर) पीटीई लि., सिंगापुर
18. मै. इनाबाटा सिंगापुर प्रा. लि.
19. मै. मित्सुबिसी केमिकल (थाईलैंड) कं. लि.

ii. नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं से आवश्यक सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावली भेजी गई थी:

1. आर्गनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसर्स ऑफ इंडिया, मुंबई
2. ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, मुंबई
3. ऑल इंडिया प्लैट टेप मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
4. पी.पी. प्रोडक्ट्स प्रा.लि., कोलकाता
5. ताराज्योत पोलीमर्स लि., कोलकाता
6. आईटीसी लि., कोलकाता
7. पहाड़पुर कूलिंग टॉवर्स लि., कोलकाता
8. टाइम पैकेजिंग लि. मुंबई
9. पेट्रो प्लास्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चेन्नई
10. दि. सुप्रीम ग्रुप, मुंबई
11. विंग बैग (इंडिया) प्राइवेट लि., बेंगलूर
12. पैरामाउंट कम्युनिकेशन्स लि., नई दिल्ली
13. पैकेजिंग इंडिया प्रा.लि., चेन्नई
14. फ्लैक्स इंडस्ट्रीज लि., नोएडा
15. बिशन स्वरूप रामकिशन एग्रो, दिल्ली
16. ब्लो पैकेजिंग (इंडिया) लि. चेन्नई
17. चेन्नई पोलीपेक प्रा.लि., चेन्नई
18. हाइड्रो एस एंड एस इंडस्ट्रीज लि., चेन्नई
19. एक्साइड इंडस्ट्रीज लि., कोलकाता

20. पेंटादेईवाहा आटो पार्ट्स लि., चेन्नई
21. वीके पोलीकोट्स लि., नई दिल्ली
22. मेकेनो प्लास्टिक लि., गुडगांव
23. डौ कैमिकल इंटरनेशनल, लि. मुंबई
24. हिटच प्लास्ट लि., मुंबई
25. जनरल कोमोडीटीज प्रा.लि., बेंगलूर
26. बालमर लॉरी वैन लीर लि., मुंबई
27. बैक्स्टर इंडिया, प्रा.लि., गुडगांव

iii. इसके उत्तर में निम्नलिखित ने उत्तर दिया है:

1. त्रिच्ची एंड पुटोकोटाई डिस्ट्रिक्स प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एसो. (त्रिपम्मा)
2. मै. पीपी प्रोडक्ट्स प्रा.लि., बेंगलूर
3. मै. राजयोट पोलीमर्स लि., बेंगलूर
4. चेन्नई प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एंड मर्चेन्ट्स एसोसिएशन्स
5. कोयम्बटूर प्लास्टिक्स मैन्यू एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन्स, तमिलनाडु,
6. दि कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्स प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन्स
7. प्लाज्मा पॉडी प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एंड मर्चेन्ट एसोसिएशन्स
8. शिवाकाशी प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन्स (सिपमा)
9. तिरुपुर प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एसो (टिप्पा)
10. विकी पॉलीकोट्स लिमिटेड, गुडगांव/नई दिल्ली
11. नॉर्थ उड़ीसा चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज,
12. डिंडीगुल जिला पॉलीथीन बैग मैनुफैक्चरर्स
13. डीलर्स वेलफेयर एसो.
14. एक्साइड इंडस्ट्रीज लि. कोलकाता
15. सलेम प्लास्टिक सेलर्स एंड मैन्यू एसोसिएशन्स
16. ऑल पांडिचेरी प्लास्टिक्स ट्रेडर्स एंड मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन्स (एपीपीटीएमए)
17. मै. कानपुर प्लास्टिक्स, लि
18. मै. जॉली कंटेनर्स, दिल्ली
19. मै. दमन पॉलीफैब्स, इंडिया
20. मै. एस्सल प्रोपैक लि., चेन्नई
21. ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्यू एसोसिएशन (एआईपीएमए)-मुंबई
22. ऑल इंडिया फ्लैट टेप मैनुफैक्चरर्स एसो. (एआईएफटीएमए)-बेंगलूर
23. ऑल इंडिया सिरिंजेज एंड नीडल्स मैनुफैक्चरर्स एसो.
24. इंडियन प्लास्टिक्स फेडरेशन (आईपीएफ)-कोलकाता
25. आर्गनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसर्स ऑफ इंडिया (जीएसपीएमए)-मुंबई,
26. गुजरात स्टेट प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एसो. (जीएसपीएमए)-अहमदाबाद,
27. दि तमिलनाडु प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एसो. (टीएपीएमए)-चेन्नई
28. आंध्र प्रदेश प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एसो. (एपीपीएमए), हैदराबाद

29. मै. ब्लो पैकेजिंग (इंडिया) लि., इंडिया
30. मै. जम्बो बैग लि., चेन्नई
31. मै. हिटाची प्लास्ट लि., इंडिया
32. मै. पैराकोट प्रोडक्ट्स लि.

- iv वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी निदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के व्यौरों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है ।
- v प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अंगोपनीय अंश को हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु एक सार्वजनिक फाइल के रूप में खुला रखा था;
- vi सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत ज्ञात की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।
- vii यह जांच 1 अप्रैल, 2008 से शुरू होकर 31 दिसंबर, 2008 तक की अवधि (जिसे एतदपश्चात् जांच अवधि भी कहा गया है) के दौरान की गई थी । क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2005-मार्च, 2006, अप्रैल, 2006-मार्च, 2007, अप्रैल, 2007-मार्च, 2008 और जांच अवधि की समयावधि शामिल है ।
- viii प्राधिकारी ने अधिनियम तथा पाटनरोधी नियमावली को ध्यान में रखते हुए 15 जून, 2009 की अधिसूचना सं. 14/5/2009-डीजीएडी के तहत संबद्ध देशों की संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की । संबद्ध देशों की संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क 30 जुलाई, 2009 की सी.शु. अधिसूचना सं. 82/2009-सी.शु. के तहत लगाया गया था ।
- ix पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 10 दिसंबर, 2009 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में समस्त हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया । जिन पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था । हितबद्ध पक्षकारों को विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों पर उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था ।
- x हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों/उत्तरों में दिए गए तर्कों पर इन अंतिम जांच परिणामों में जहां संगत पाया गया है, विचार किया गया है ।
- xi घरेलू उद्योग तथा सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा आंकड़ों के संबंध में आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था ।
- xii पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा विचारित आवश्यक तथ्यों का प्रकटन ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष किया गया था और उस पर प्राप्त टिप्पणियों पर जहां संगत पाया गया है, इन अंतिम जांच परिणामों में विधिवत विचार किया गया है ।

- xiii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता के दावे स्वीकार किए थे और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
- xiv. जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- xv. इस अधिसूचना में *** चिन्ह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना और नियमों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को प्रदर्शित करता है।

ओमान से न्यूनतम आयातों के बारे में ओमान पी पी के अनुरोध

6. ओमान पी पी ने यह तर्क दिया है कि ओमान से हुए आयात की मात्रा नगण्य और आयातों के 3% से कम है। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने वर्ष 2008-09 तथा जांच अवधि के लिए मंत्रालय की वेबसाइट (<http://commerce.nic.in>) से डाउनलोड किए गए आयात के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और यह उल्लेख किया है कि इसकी गणना समूचे वित्त वर्ष 2008-09 के आंकड़ों 9 माह के लिए अनुपातिक रूप से की गई है। इसके अलावा, उन्होंने समूचे वित्त वर्ष 2008-09 के लिए इनफोइव से प्राप्त आयात के आंकड़े भी उपलब्ध कराए हैं। इन दोनों आंकड़ों के आधार पर यह दावा किया गया है कि ओमान से संबद्ध वस्तु के आयात न्यूनतम सीमा से कम हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि चूंकि विचाराधीन उत्पाद में एच एस कोड 39029000 (प्रारंभिक रूप में प्रोपीलीन के अन्य पॉलीमर) के अंतर्गत हुए आयातों के योगिक शामिल हैं इसलिए वे वर्तमान जांच के दायरे में आएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि एच एस कोड 39029000 के अंतर्गत किए गए आयातों को भी वर्तमान जांच में हिसाब में लेना अपेक्षित है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के कुल आयातों में न्यूनतम हिस्से के बारे में ओमान के निर्यातक के तर्क की सावधानीपूर्वक जांच की है। प्राधिकारी ने जांच अवधि अर्थात् अप्रैल, 2008 से दिसंबर, 2008 तक के लिए डी जी सी आई एंड एस से वास्तविक आयातों के सौदेवार ब्यौरे प्राप्त किए हैं और इस प्रकार यह मत व्यक्त किया है कि निर्यातक द्वारा वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए समूचे वित्त वर्ष से जांच अवधि के लिए हुए आयातों के समेकित आंकड़ों पर विचार करना अपेक्षित नहीं है।
8. संबद्ध वस्तु से संबंधित डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों की जांच से यह पता चलता है कि ओमान से विचाराधीन उत्पाद के हुए वास्तविक आयात न्यूनतम सीमा से काफी अधिक हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने इनफोइव से प्रतिवादी द्वारा लिए गए सौदेवार आयात

के आंकड़ों की जांच भी की। उपर्युक्त की जांच से यह पता चला कि अन्य बातों के साथ-साथ आयात के आंकड़े विचाराधीन उत्पाद से संबंधित हैं। आगे यह नोट किया गया था कि आयात के आंकड़ों में खासकर 3 प्रविष्टियों की गई थीं जिनमें प्रति मी.ट. कीमत असामान्य रूप से कम दर्शायी गई थी। इस मामले पर ओमान पी पी के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की गई थी। इन प्रविष्टियों की जांच से यह पता चला कि एक सौदे के लिए आयात की मात्रा लगभग 16000 मी.ट. थी और अन्य दो के लिए यह 32000 मी.ट. थी, जिसका एक बीजक पर पोटलदान करना संभव नहीं है। इसके अलावा, संबद्ध मूल्य से उन कीमतों का पता नहीं चलता था जिन कीमतों पर उस समय आयात किए जा रहे थे और ये मूल्य काफी कम थे। स्पष्ट तौर पर इन सौदों के बारे में त्रुटि आयात आंकड़ों की माप की इकाई के गलत उल्लेख के कारण हुई थी। अतः प्राधिकारी ने इन सौदों के लिए माप की इकाई मी.ट. से किग्रा. में बदलकर सुधार दी और सुधारे गए आंकड़ों का विश्लेषण किया। सुधारे गए परंतु छांटे न गए आंकड़ों के आधार पर भी यह नोट किया गया कि ओमान से हुए आयात न्यूनतम सीमा से काफी अधिक थे और यदि छांटे गए आयात के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो ओमान से हुए आयातों का हिस्सा अधिक होगा। जहां तक एच एस कोड 39029000 के अंतर्गत हुए आयातों पर विचार करने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि विश्लेषण करते समय इन पर भी विचार किया गया है।

9. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ओमान से हुए आयात न्यूनतम सीमा से अधिक हैं और ओमान को वर्तमान जांच की परिधि और दायरे से अलग रखना अपेक्षित नहीं है।

ग. जांच अवधि

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

10. यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में जांच अवधि काफी कम है और इसमें वे महीने शामिल हैं जिनके दौरान कच्ची सामग्री की आवाजाही और पोलीप्रोपलीन की कीमतें वैश्विक मंदी के कारण त्रुटिपूर्ण रही थीं। उचित और सही विश्लेषण के लिए जांच अवधि 18 महीने की अवधि निर्धारित की जानी चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के बारे में हितबद्ध पक्षकारों ने प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद कोई नया अनुरोध नहीं किया है। अतः प्राधिकारी इस प्रारंभिक जांच परिणाम की पुष्टि करते हैं कि वर्तमान मामले में चुनी गई जांच अवधि उचित ढंग से चुनी गई है जिसमें इस विषय के संबंध में सर्वाधिक संगत आंकड़े उपलब्ध हैं।

12. तथापि, जांच अवधि के दौरान कच्ची सामग्री और संबद्ध वस्तु की कीमत में अत्यधिक घट-बढ़ को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों का विश्लेषण व्यवहार्य सीमा तक माहवार आधार पर किया गया है।

घ. विचाराधीन उत्पाद और घरेलू समान वस्तु

13. विचाराधीन उत्पाद "पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमोपोलीमर्स और प्रोपीलीन तथा एथीलीन के कोपोलीमर्स)" संबद्ध वस्तु का उपयोग सीमेंट, खाद्यान्न, चीनी, उर्वरक के बुने हुए बोरे और फलों तथा सब्जियों के थैलों, टीक्यू और बीओपीपी फिल्मों, कंटेनरों आदि में किया जाता है।

14. संबद्ध वस्तुओं को सीमाशुल्क शीर्ष 39021000 और 39023000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

15. यह तर्क दिया गया है कि इस याचिका में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष 39021000 और 39023000 के अंतर्गत यथा वर्गीकृत दो उत्पाद अर्थात् प्रोपीलीन-होमोपोलीमर और प्रोपीलीन कोपोलीमर शामिल हैं और यह कि ये दोनों उत्पाद एक दूसरे से भिन्न-भिन्न हैं। प्रोपीलीन कोपोलीमर, पोलीप्रोपीलीन होमोपोलीमर से ***% महंगा होता है और तकनीकी दृष्टि से पोलीप्रोपीलीन से अच्छा होता है।

16. मै. टी पी सी ने यह बताया है कि कॉस्मोप्लीन ग्रेड एजैड564जी - जिसे विशेष रूप से औद्योगिक पुर्जों के लिए तैयार किया जाता है, बीआरए 61 453 बी, बीआरए 61 454बी तथा बीआरए 61 जिनका उपयोग ऑटोमोटिव मिश्रण अथवा आटोमोटिव की इंजेक्शन मोल्डिंग में किया जाता है, सीपीएस 188 454 बी-जिसका उपयोग ऑटोमोटिव आंतरिक पुर्जों के लिए किया जाता है और जिसके लिए बेहतर सतही दिखावट अपेक्षित होती है तथा एफएल 7540एल, एसएस 5611एल, एफ S6612एल, एफएल 7320एल, एफएल 7540एल, एफएल 7632एल, एफS5611एल, एफएस 6612एल तथा एफएल7641एल को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि टी पी सी द्वारा उत्पादित और निर्यातित पोलीप्रोपीलीन के इन ग्रेडों के समतुल्य ग्रेडों का घरेलू उद्योग उत्पादन नहीं करता है।

17. मै. एक्सोन मोबिल ने यह उल्लेख किया है कि ग्रेडों अर्थात् पीपी 7033एन, एपी 3एन, पीपी 7555केएनई1 तथा पीपी 7684 का विनिर्माण घरेलू उद्योग नहीं करता है। मै. एक्सोन मोबिल का यह विश्वास है कि एचीव 6936जी1, विस्टामैक्स 3000, विस्टामैक्स 3020एफएल, विस्टामैक्स 3980एफएल, विस्टामैक्स 6102, एक्सोन आई टी 0316, एक्सट्रल कंपाउंडिड तथा फिल्ड पोलीप्रोपीलीन जैसे विशिष्टीकृत उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आते हैं।

18. मै. टोयोटा सूसो इंडिया ने यह उल्लेख किया है कि समतुल्य घरेलू ग्रेड बी 400एमएम टी एस एम मानक के अनुरूप नहीं हैं और इसमें ए आर ए आई की जांच रिपोर्ट के आधार पर पी पी 2 या ए जैड 564 जी के ग्रेड के समान रासायनिक विशेषताएं नहीं हैं।

19. मै. पैराकोड प्रोडक्ट्स लि. ने यह उल्लेख किया है कि भारत में कोई भी ईपीपी बीड्स (एक्सपेंडेड पोलीप्रोपीलीन) का विनिर्माण नहीं कर रहा है और इस प्रकार ईपीपी बीड्स (एक्सपेंडेड पोलीप्रोपीलीन) को जांच के दायरे से अलग रखा जाना चाहिए और इस पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं किया जाना चाहिए । उन्होंने अपने दावे का समर्थन इस बारे में मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के साथ हुए ई-मेल पत्राचार को संलग्न कर किया है ।

20. कुछेक हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि होमोपॉलीमर और को-पॉलीमर दो अलग-अलग उत्पाद हैं और इसलिए क्षति विश्लेषण अलग-अलग करना अपेक्षित है ।

21. यह तर्क दिया गया है कि टर-पॉलीमर और यौगिक को जांच के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता और यह कि जांच शुरुआत में उत्पाद का क्षेत्र प्रोपीलीन के होमोपॉलीमर तथा एथीलीन और प्रोपीलीन के को-पॉलीमर तक सीमित था । इसमें अन्य पॉलीमर शामिल नहीं थे । टर पॉलीमर एक को-पॉलीमर है जिसमें प्रापीलीन, एथीलीन और ब्यूटेन का उपयोग करते हुए 3 विशिष्ट मोनोमर शामिल होते हैं । यह प्रोपीलीन तथा एथीलीन के कोपॉलीमरों से विशिष्ट तथा अलग होता है । कुछेक हितबद्ध पक्षकारों ने यह बताया है कि पॉलीप्रोपीलीन यौगिकों को भी जांच से अलग रखना अपेक्षित है ।

घरेलू उद्योग के अनुरोध

22. घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने मात्र कथनों के आधार पर कुछेक ग्रेडों को अलग रखने का दावा किया है और तकनीकी विनिर्देशनों, रासायनिक संरचना, वाणिज्यिक एवं तकनीकी प्रतिस्थापनीयता आदि के बारे में पर्याप्त ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए हैं । घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबंधित उत्पादों के बारे में ऐसे मूलभूत ब्यौरों के अभाव में किसी भी पक्षकार के लिए टिप्पणियां प्रस्तुत करना असंभव है ।

23. हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिया है कि उल्लिखित ग्रेड/प्रकार/नाम विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तुएं नहीं हैं । चूंकि अलग रखे जाने के तर्क को सिद्ध करने का दायित्व पूर्णतः इस प्रकार से अलग रखे जाने का दावा करने वाले पक्षकारों पर होता है, इसलिए जब तक ऐसे हितबद्ध पक्षकार साक्ष्य के साथ पर्याप्त विधिक तथा वास्तविक आधार प्रस्तुत न करें तब तक किसी ग्रेड अथवा प्रकार को अलग नहीं रखा जाना चाहिए ।

24. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि कुछेक ग्रेडों/प्रकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग रखे जाने पर विचार करने के लिए निम्नलिखित जांचों को अपनाकर निर्दिष्ट प्राधिकारी की सतत पद्धति रही है :

- क. कि घरेलू उद्योग उक्त उत्पाद का उत्पादन नहीं करता है और वह उसका उत्पादन करने में सक्षम भी नहीं है ।
- ख. जिन ग्रेडों को अलग रखने की मांग की गई है, वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेडों से तकनीकी या वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं
- ग. यह सिद्ध करने का दायित्व पूर्णतः ऐसे अपवर्जन की मांग करने वाले पक्षकार पर होता है कि किसी प्रकार के उत्पाद को अलग रखा जाना है ।

घ. कुछेक ग्रेडों/प्रकारों को अलग रखे जाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जिसमें शुल्क का प्रभाव कम होता हो अथवा वह निष्प्रभावी बन जाता हो ।

25. जब तक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु निर्यातकों द्वारा उत्पादित ग्रेडों/प्रकारों के साथ वाणिज्यिक तथा तकनीकी रूप से प्रतिस्थापित की जा सकती है तब तक उन्हें अलग नहीं रखा जा सकता । यह भी अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु के किसी ग्रेड का उत्पादन करने में सक्षम है और अपवर्जन के दावों को सरसरी तौर पर रद्द किए जाने की जरूरत है ।

26. यह तर्क दिया गया है कि इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया और ताइवान से फुली ड्रॉन यार्न के मामले में इन्हीं परिस्थितियों में निर्यातकों ने फुली ड्रॉन यार्न के कुछेक ग्रेडों या प्रकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किए जाने का विरोध किया था तो प्राधिकारी ने यह निर्णय दिया था कि पाटित वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है । आयातित वस्तु का उपयोग प्रयोक्ता उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के साथ अदल-बदल कर किया जाता है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय होने के कारण पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत "समान वस्तुएं" हैं । अतः प्राधिकारी जांच के एक भाग के रूप में फुली ड्रॉन यार्न के समस्त ग्रेडों और प्रकारों को शामिल करते हैं ।

27. घरेलू उद्योग क्रमशः एफएल 7320एल, एफएल 7540एल, एफएल 7632एल, एफएस 5611एल, एफएस 6612एल, एफएल 7641एल, पीपी 2 अथवा एजैड564जी, बीआरए 61453बी, बीआरए 61454बी, बीआरए 61 एवं सीपीएस188454बी जैसे एसआर 070एनएस, एसआर 80एनएस, एसआर072एनएस, एसआर60एन, एसआर50एनएस, एसआर 071एनएस, बी400एमएन, बी650एमएन-बीएन84302एक्स, बी650एमएन-एफपीटी 20एफआर, बी550एमएन-एन70992 वाई और सी320एमएन-पीपीएस एन3 के समतुल्य ग्रेडों का विनिर्माण कर रहा है । घरेलू उद्योग के उपर्युक्त समतुल्य ग्रेडों का उल्लेख उत्पाद ब्रोशरों में समुचित ढंग से किया गया है ।

28. यह तर्क दिया गया है कि टी एस एम मानक प्रयोक्ता विशिष्ट मानक हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त मानक नहीं हैं । अतः यह कहना निर्णायक नहीं है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित ग्रेड टी एस एम मानकों को पूरा नहीं करते हैं । इसके अलावा, आयातक ने कभी भी उन्हें पूर्व में की गई किसी जांच की रिपोर्ट प्रदान नहीं की है । यह अनुरोध किया गया है कि आयातक स्वैच्छिक रूप से यह कह कर प्राधिकारी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि तीन विशेषताएं अर्थात् एम एफ आई, एच डी टी तथा इलॉगेशन महत्वपूर्ण होती है । कई तकनीकी मापदंड हैं और इनमें से सर्वाधिक मापदंड है आईजोड प्रभाव तथा फ्लैक्सुरल मोड्युलस, जो आयातक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है ।

29. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया है कि होमोपोलीमर और को-पॉलीमर वस्तुतः केवल पॉलीप्रोपीलीन हैं । चूंकि विचाराधीन उत्पाद में पॉलीप्रोपीलीन के समस्त प्रकार शामिल हैं इसलिए यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि इन उत्पादों में कुछेक अंतर होने मात्र से भेद करना होगा । आगे यह अनुरोध किया गया है कि पॉलीप्रोपीलीन के विभिन्न ग्रेडों/प्रकारों के बीच कुछेक अंतर होना लाजिमी है परंतु इसका जांच के दायरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ।

आगे यह अनुरोध किया गया है कि जहां तक घरेलू उद्योग का संबंध है, पॉलीप्रोपीलीन के दोनों प्रकारों की उत्पादन लागत में कोई अंतर नहीं है। कीमत अंतर भी मामूली (1 से 2%) है जैसा कि प्लाट्स से प्राप्त सूचना से देखा जा सकता है। यह भी अनुरोध किया गया है कि जहां बुटेन का उपयोग एथीलीन के साथ को-पॉलीमर बनाने के लिए भी किया जाता है, वहीं लागत में अंतर मामूली है क्योंकि बुटेन प्रयुक्त कुल कच्ची सामग्री की मात्रा लगभग 1-2% होती है।

30. टर पॉलीमर वस्तुतः विचाराधीन उत्पाद में शामिल हैं क्योंकि टर पॉलीमर में दोनों कच्ची सामग्री प्रोपीलीन तथा एथीलीन होती है। इसके अलावा किसी कोपॉलीमर करे तब तक विचाराधीन उत्पाद में शामिल किया जाता है जब तक उसका उत्पादन प्रोपीलीन तथा एथीलीन के उपयोग द्वारा किया जाता है और इस बात का कोई महत्व नहीं है कि क्या किसी अन्य अभिवर्धक/कच्ची सामग्री का उपयोग किया गया है अथवा नहीं।

31. जहां तक मिश्रण का संबंध है, यह अनुरोध किया जाता है कि विनिर्माण हेतु संबद्ध वस्तु का उपयोग करने से पूर्व यह ग्रेड के गुणधर्मों में परिवर्तन लाने के लिए अभिवर्धक जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें रंग, टेंसिल क्षमता, तापमानरोधी क्षमता, प्रभाव क्षमता आदि शामिल होते हैं। तथापि, मूल स्वरूप तथा उत्पाद में परिवर्तन नहीं होता है जो केवल पॉलीप्रोपीलीन बनी रहती है। अतः मिश्रणों को अलग नहीं किया जाता है क्योंकि उत्पाद अनिवार्यतः पॉलीप्रोपीलीन बना रहता है।

32. सीमाशुल्क अर्थनिरूपण नियमावली के अंतर्गत जहां किसी उत्पाद में दो या उससे अधिक सामग्री होती है, वहां उसे कच्ची सामग्री के प्रमुख तत्वों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा और अन्य कच्ची सामग्री की अनदेखी की जाएगी। अतः इस आधार पर भी मिश्रणों को जांच के दायरे से अलग नहीं रखा जा सकता।

प्राधिकारी द्वारा जांच

33. विचाराधीन उत्पाद: प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत करते समय जांच के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था अर्थात् पॉलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमोपॉलीमर्स और प्रोपीलीन तथा एथीलीन के कोपॉलीमर्स) और इस प्रकार "टर पॉलीमर" जांच की परिधि और दायरे में नहीं आती है। तथापि, यह कहना गलत होगा कि मिश्रण विचाराधीन उत्पाद के भाग नहीं हैं।

34. प्राधिकारी ने कुछेक ग्रेडों/प्रकारों को अलग रखे जाने से संबंधित दावों सहित विचाराधीन उत्पाद के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावों और प्रति दावों को नोट किया है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि होमोपॉलीमर और को-पॉलीमर के बीच कीमत में काफी अंतर है। तथापि, घरेलू उद्योग ने इन दावों का खंडन किया है। लेकिन किसी पक्षकार ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर, पॉलीप्रोपीलीन नहीं हैं।

35. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि पॉलीप्रोपीलीन कुछेक ग्रेडों को अलग रखे जाने से संबंधित दावों का घरेलू उद्योग है, प्रतिवाद और खंडन किया है। इस विषय पर उनके साथ किए

गए पत्र व्यवहार में घरेलू उद्योग ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि वे वस्तुतः ऐसे विशिष्ट ग्रेडों की संबद्ध वस्तु की पेशकश करते हैं जिसके बारे में निर्यातकों के कथनानुसार घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित होने का दावा किया गया है। उन्होंने समतुल्य ग्रेडों के ब्योरे भी प्रदान किए हैं। आगे यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने किसी वैज्ञानिक दस्तावेज अथवा तकनीकी साक्ष्य के साथ अपवर्जन संबंधी अपने दावों की पुष्टि नहीं की है।

36. तथापि, ईपीपी बीड्स (एक्सपेंडेड पॉलीप्रोपीलीन) के संबंध में, मै. पैराकोड प्रोडक्ट्स लि. द्वारा किए गए अनुरोधों और रिकॉर्ड में उपलब्ध संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ईपीपी बीड्स (एक्सपेंडेड पॉलीप्रोपीलीन) को इस जांच की परिधि और दायरे से अलग रखा जाता है।

37. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है: -

"समान वस्तु" का अर्थ एक ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटन के लिए जांच के अधीन वस्तु के समान हो या प्रत्येक दृष्टि से उसके जैसी हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य ऐसी वस्तु जो यद्यपि प्रत्येक दृष्टि से समान न हो तब भी उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हो;

38. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के बीच कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोगों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से आयातित संबद्ध उत्पाद से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर करते हैं।

39. इस प्रकार प्राधिकारी का यह विचार है कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध विचाराधीन उत्पाद के समान उत्पाद हैं।

ड. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

40. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा।

41. इस नियम में हाल ही में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा।"

42. आवेदक के अनुसार देश में समान वस्तु के केवल दो उत्पादक हैं। यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. द्वारा दायर किया गया है। अन्य उत्पादक अर्थात् मै. हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लि. ने आवेदन का समर्थन किया है।

43. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. का उत्पादन समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा बनता है जो भारतीय उत्पादन के 50% से काफी अधिक है। इस प्रकार यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी हितबद्ध पक्षकार ने आवेदक के आधार का खंडन नहीं किया है। इसके अलावा, मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के साथ पठित नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" माना जा रहा है।

च. गोपनीयता

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

44. यह तर्क दिया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि इस याचिका में मांगा गया गोपनीय व्यवहार सदाशयतापूर्ण और घरेलू उद्योग के अधिकारों से सुसंगत है। याचिका के पठन मात्र से इस बात का संकेत मिलता है कि गोपनीयता का दावा एक अपवाद के बजाए नियम के रूप में किया गया है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

45. निर्यातकों ने बिना किसी उचित आधार के अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। इसके अलावा, गोपनीय अंश में दी गई समस्त सूचना के लिए कोई उचित कारण बताए बिना प्रश्नावली के उत्तर में उनका अगोपनीय अंश प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अर्थ तर्कसंगत ढंग से समझने का पर्याप्त आधार सुलभ नहीं होता है। प्रश्नावली के उत्तर के अगोपनीय अंश से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्होंने पोलिप्रोपीलीन की प्रत्येक किस्म के लिए अलग-अलग सूचना प्रस्तुत की है। इस संदर्भ में यह अनुरोध किया जाता है कि सभी निर्यातकों ने आयातों की मात्रा के संबंध में भी गोपनीयता का दावा किया है जो स्वीकार्य

नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग को आवेदन के अगोपनीय अंश में भी मात्रा से संबंधित सूचना प्रस्तुत करनी पड़ी है ।

46. प्रकटन विवरण के पश्चात की गई अपनी टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि आंकड़ों के बारे में सहयोगी निर्यातकों की गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया गया है और इस जांच में उनके दावे के अनुसार उक्त आंकड़ों/सूचना को गोपनीय रखा गया है । यह अनुरोध किया गया है कि निर्यातक 25 मार्च, 2009 की व्यापार सूचना सं. 4/27/2007 के अनुसार अगोपनीय उत्तर उपलब्ध नहीं कराया है और अत्यंत कम सूचना देकर प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही पद्धति और दिशा-निर्देशों की अवहेलना की है जबकि घरेलू उद्योग पर उपर्युक्त व्यापार सूचना तथा दिशानिर्देशों के अनुसार अपने गोपनीय रूपांतरण में ब्यौरे देने के लिए अतिरिक्त बोझ डाला गया है । आगे यह अनुरोध किया गया है कि ऐसे ब्यौरों के अभाव में घरेलू उद्योग सही परिणाम पर पहुंचने में प्राधिकारी की मदद करने की स्थिति में नहीं है । तदनुसार उन्होंने अनुरोध किया है कि निर्यातकों से यह कहा जाए कि वे उपर्युक्त व्यापार सूचना तथा दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हें असहयोगी माना जा सकता है और उनका पाटन मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

47 प्राधिकारी ने उपर्युक्त अनुरोधों को नोट किया है । हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी । संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष नहीं किया गया है । संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता के दावे स्वीकार किए थे और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है । जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था । जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर ये जांच परिणाम दर्ज किए हैं ।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य

48. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी थी जिसमें उन्हें निर्धारित ढंग और पद्धति से सूचना प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी । निम्नलिखित कंपनियों से प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हुए थे ।

1. मै. ओमान पोलीप्रोपलीन एलएलसी, ओमान
2. मै. एडवॉर्ड पोलीप्रोपलीन कंपनी, सऊदी अरब
3. मै. विनमर इंटरनेशनल लि., अमरीका
4. मै. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, सऊदी अरब (सेबिक)
5. मै. सऊदी यूरोपियन पेट्रोकेमिकल कंपनी (आई बी एन जहार), सऊदी अरब
6. मै. स सऊदी थांबू पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट) सऊदी अरब
7. मै. एक्सोन मोबिल केमिकल एशिया पसिफिक, सऊदी अरब
8. मै. सऊदी पोलियोलेफाइन्स कंपनी, सऊदी अरब
9. मै. एक्सोन मोबिल केमिकल एशिया पसिफिक, सिंगापुर
10. मै. पोलियोलेफाइन्स कंपनी (सिंगापुर) पीटीई लि..
11. मै. इटोचू प्लास्टिक पीटीई लि., सिंगापुर
12. मै. मारुबेनी केमिकल एशिया पसिफिक पीटीई लि., सिंगापुर
13. मै. सुमितोमो कार्पोरेशन एशिया पीटीई लि., सिंगापुर
14. मै. टोयोटा टशूशो (सिंगापुर) पीटीई लि., सिंगापुर
15. मै. सुमितोमो कार्पोरेशन एशिया पीटीई लि., सिंगापुर
16. मै. मित्सुबिसी केमिकल (थाईलैंड) कं. लि.
17. मै. नेशनल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीयलाइजेशन मार्केटिंग कं, सऊदी अरब
18. मै. बसैल इंटरनेशनल ट्रेडिंग एफ जैड ई
19. मै. इनाबाटा सिंगापुर प्रा. लि.

घरेलू उद्योग के अनुरोध

49. प्रतिवादी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर का सार्थक सारांश प्रदान न कर भारतीय कानून के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहे हैं और उन्होंने किसी समुचित औचित्य के बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है ।

50. ओमान और सऊदी अरब के उत्पादकों के लिए कच्ची सामग्री की कीमत भरोसेमंद नहीं है । समस्त फीड स्टॉक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम से प्राप्त किया गया है और कीमत राज्य द्वारा नियंत्रित है ।

51. सऊदी अरब द्वारा जाहिर तौर पर फीड स्टॉक की कीमत के संबंध में दोहरी कीमत नीति अपनाई जाती है जिसे तुलनात्मक निर्यात कीमत से काफी कम पर तय किया जाता है । इस तथ्य का खंडन किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार नहीं किया है । इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि इस प्रकार से फीड स्टॉक की कीमत में न तो सही लागत प्रदर्शित होती है और न ही उचित तथा निष्पक्ष तुलना की जा सकती है । जहां कहीं प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 (1) (ग) के इन उपबंधों को नोट किया है कि घरेलू कीमत भरोसेमंद नहीं है और इससे विशेष बाजारी स्थिति के कारण उचित तथा निष्पक्ष तुलना नहीं की जा सकती, वहां घरेलू बिक्री को रद्द करना अपेक्षित है और उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया जाना है । आगे यह उल्लेख किया गया है कि निर्यात कीमत की तुलना में फीड स्टॉक की कीमत काफी कम होने के कारण सऊदी अरब ने एक

ऐसी विशेष बाजार स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमें संबद्ध वस्तु की घरेलू लागत और कीमत हमेशा ही निर्यात कीमत से काफी कम रहेगी। सऊदी अरब के उत्पादक घरेलू खपत हेतु कीमत नियंत्रण के सरकारी हस्तक्षेप के कारण विश्वभर के अन्य उत्पादकों के मुकाबले अनुचित ढंग से लाभ की कीमत में हमेशा बने रहेंगे।

52. इस संबंध में घरेलू उद्योग ने बाजार स्थिति संबंधी आस्ट्रेलियाई दिशा-निर्देशों की ओर भी प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित किया है जिनमें यह निर्धारित किया गया है कि "विशेष बाजार स्थिति" पद में ऐसी स्थिति सहित कई संभावित स्थितियां शामिल हैं जिसमें निर्यात के देश में घरेलू बिक्री कीमत सरकारी प्रभाव द्वारा अत्यधिक प्रभावित कर दी जाती है जिससे वे कीमतें घरेलू सामान्य मूल्य निर्धारित करने में उपयोग हेतु अनुचित बन जाती हैं।
53. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 के उपबंधों का हवाला देते हुए घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि सऊदी अरब में चूंकि फीड स्टॉक की कीमतें सपष्टतः राज्य द्वारा नियंत्रित हैं और इन पर भारी सब्सिडी दी जाती है, इसलिए इन पर उत्पादन से संबद्ध लागत का उचित प्रदर्शन करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में चीन तथा कोरिया से रबड़ रसायनों के मामले में (मामला सं. 14/5/2007-डीजीएडी) तथा बेलारूस और रूस से पोटेशियम क्लोराइड के मामले में ई सी जांच परिणाम (परिषद विनियमन सं. 1050/2006, दिनांक 11 जुलाई, 2006) प्राधिकारी के निर्णय का भी उल्लेख किया है।
54. प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि मै. ईटोशू ने अपने उत्तर में यह उल्लेख किया है कि उसने ग्राहकों को सीधे तथा व्यापारियों के जरिए संबद्ध वस्तु की आपूर्ति की है। उक्त व्यापारी से पूर्ण सूचना के अभाव में मै. ईटोशू को अलग व्यवहार अथवा पृथक पाटन मार्जिन प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत को हुए निर्यातों की पूर्ण श्रृंखला से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसे निर्यातकों को असहयोगी माना जाना चाहिए। यह भी अनुरोध किया गया है कि उन निर्यातकों को भी असहयोगी माना जाए जो भारत को निर्यातों की पूर्ण श्रृंखला की सूचना प्रदान करने में विफल रहे हैं और उन्हें अलग विभाग अथवा पृथक पाटन मार्जिन प्रदान न किया जाए। यह भी अनुरोध किया गया है कि निर्यातक यह दलील दे सकते हैं कि उनके पाटन मार्जिन और शुल्क का निर्धारण प्रत्यक्ष निर्यातों की सूचना के आधार पर किया जाए और अन्य व्यापारियों के जरिए हुए निर्यातों की अनदेखी की जाए। यह बताया गया है कि केवल भारत के ग्राहकों के लिए गए प्रत्यक्ष निर्यातों के आधार पर पाटन मार्जिन तथा क्षति निर्धारण किया जाना विधिक स्थिति और प्राधिकारी की सतत पद्धति के पूर्णतः प्रतिकूल होगा। इसके अलावा, इससे कानून का पालन करने के लिए निर्यातकों को अनुचित तथा अनपेक्षित लाभ मिलेगा। इससे क्षति एवं कारणात्मक संबंध सिद्ध हो जाने के बावजूद घरेलू उद्योग को कारगर सुरक्षा भी नहीं मिलेगी। ऐसी किसी स्थिति में ऐसे सभी निर्यातकों की समस्त सूचना को उस स्थिति में अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित है कि यदि उसका समर्थन भारत के लिए व्यापारियों की सूचना के साथ नहीं किया जाता है।

55. यह भी उल्लेख किया गया है कि मै. सेबिक, मै. आईबीएन जाहर तथा मै. येनपेट के विलंबित उत्तरों को अलग व्यवहार तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया है। यह अनुरोध किया गया है कि उक्त उत्पादकों तथा निर्यातकों के उत्तरों को रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता क्योंकि उन्हें काफी देर बाद अर्थात् प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद दायर किया गया है और ऐसी स्वीकृति न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है अपितु पाटनरोधी नियमावली के विशिष्ट उपबंधों के प्रतिकूल भी है। इसके अलावा, उक्त पक्षकारों के दस्तावेजों का अगोपनीय रूपांतरण भी उपर्युक्त व्यापार सूचना तथा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं है।

56. यह उल्लेख किया गया है कि सऊदी अरब के उत्पादकों की उत्पादन लागत के निर्धारण के बारे में वे यह समझते हैं कि प्राधिकारी का प्रस्ताव किसी माह विशेष के दौरान फीड स्टॉक की बाजार कीमत के आधार पर निर्धारित उत्पादन लागत पर विचार करने का है। सऊदी उत्पादकों के फीड स्टॉक की कीमतें फार्मूला आधारित कीमत के अनुसार होती हैं। फीड स्टॉक की यह कीमत फार्मूला के अनुसार होती है जिसमें बाजार कीमतें प्रदर्शित नहीं होती हैं अतः यह जरूरी है कि फीड स्टॉक की सही लागत निकालते समय प्राधिकारी को संबंधित माह के लिए वास्तविक बाजार मूल्य निकालने हेतु उक्त फार्मूला में फीड स्टॉक के बाजार मूल्य का मात्र स्थानापन्न का उपयोग करना चाहिए।

57. यह भी अनुरोध किया गया है कि मै. सेबिक ने ऐसी सभी संबद्ध कंपनियों के लिए सूचना प्रदान नहीं की है जो संबद्ध वस्तु के कार्यकलाप में संलग्न हैं जबकि कानूनन उनके लिए समस्त संबद्ध पक्षकारों की सूचना देना अपेक्षित है। उन्होंने मै. यनसाब येनबू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी तथा मै. सऊदी कयान के बारे में सूचना नहीं दी है जो भी संबद्ध वस्तु के कार्यकलाप में संलग्न हैं। इस संबंध में मै. सेबिक की वेबसाइट और वार्षिक रिपोर्ट के संगत पृष्ठ प्राधिकारी को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इनसे स्पष्टतः यह पता चलता है कि ये कंपनियां वस्तुतः मै. सेबिक से संबद्ध हैं और ये संबद्ध उत्पाद का कार्यकलाप करती हैं। ईयू, अमरीका, ब्राजील आदि में कई अन्य प्राधिकारियों के समक्ष पाटनरोधी जांच के मामले में भी यह अनुरोध किया गया है कि निर्यातकों के लिए ऐसे प्रत्येक संबद्ध पक्षकार के बारे में सूचना देनी अपेक्षित होती है जो संबद्ध उत्पाद का कार्यकलाप करता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति के अनुसार केवल इसी आधार पर मै. सेबिक के उत्तर को असवीकृत कर दिया जाना चाहिए।

संबद्ध देशों में निर्यातकों/उत्पादकों के अनुरोध

58. यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी को आवेदन में दी गई पाटन की गणना पर भरोसा नहीं करना चाहिए। निर्यातकों ने उचित निर्यात कीमत प्रभारित की है जो समान उत्पाद प्रकार, विनिर्देशन एवं गुणवत्ता हेतु विश्व तथा भारतीय कीमत के अनुरूप हैं। अतः आवेदन में परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर आवेदक के पाटन के आरोप

कल्पना पर आधारित हैं और पूर्णतः निराधार हैं और यह कि प्राधिकारी को इस संबंध में प्रश्नावली के संबंधित उत्तर का अवलोकन करना चाहिए।

59. निर्यातक मै. इनाबाटा सिगापुर प्रा. लि. ने यह उल्लेख किया है कि टी पी सी के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पर्याप्त मात्रा में अन्य बाजारों के लिए उसकी निर्यात कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।
60. मै. एडवांस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी (ए पी पी सी) ने यह अनुरोध किया है कि सऊदी अरब में कुछेक उत्पादों की विनियमित कीमतों की मौजूदगी से केवल सीमित संख्या के उत्पादों की ऐसी विनियमित कीमत को बनाए रखने के बारे में सऊदी सरकार के अधिकार से संबंधित डब्ल्यू टी ओ सदस्यों द्वारा किए गए समझौते का प्रदर्शन होता है। ए पी पी सी ने आगे यह उल्लेख किया है कि डब्ल्यू टी ओ में सऊदी अरब के शामिल होने से संबंधित कार्य दल की रिपोर्ट के उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि सऊदी अरब में प्राकृतिक गैस द्रव (एन जी एल) की घरेलू कीमत में स्थानीय बिक्री करने वाले उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य प्रदर्शित होता है और वह लागत की पूर्ण वसूली तथा उचित लाभ पर आधारित है। अतः घरेलू उद्योग के इस दावे को रद्द कर दिया जाना चाहिए कि ऐसी घरेलू कीमतों में बाजारी स्थिति प्रदर्शित नहीं होती है और उसका प्रचालन सब्सिडी के रूप में होता है। डब्ल्यू टी ओ करारों में ऐसी लागत की अनदेखी करने का कोई आधार नहीं है जिसमें सऊदी अरब में बाजार स्थिति का प्रदर्शन न होता हो क्योंकि डब्ल्यू टी ओ सदस्यों के बीच इस बात के बारे में कोई विवाद नहीं है कि सऊदी अरब बाजार अथर्व्यवस्था वाला देश है और यह कि इसे पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ भी ऐसा ही माना जाएगा।

एम ई टी के रूप में सऊदी अरब का व्यवहार

- सऊदी अरब के कुछेक निर्यातकों/उत्पादकों ने यह तर्क दिया है कि वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ सऊदी अरब को निम्नलिखित कारणों से बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए।

पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (3) (क) के पठन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी फर्म के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर कार्य करने के बारे में तभी घोषणा की जा सकती है जब निम्नलिखित सभी मापदंडों की पूर्ति होती हो : (क) संबंधित फर्मों के निर्णय बाजारी सिद्धांतों पर आधारित हैं ; (ख) संबंधित फर्मों के निर्णय राज्य के पर्याप्त हस्तक्षेप से रहित हैं; (ग) प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्यों का पर्याप्त प्रदर्शन होता है। घरेलू उद्योग अपने उत्तर में उपर्युक्त किसी भी शर्त की गैर-मौजूदगी सिद्ध करने में विफल रहा है और इस प्रकार घरेलू उद्योग के कथन आदितः निराधार हैं।

घरेलू उद्योग का दावा "डब्ल्यू टी ओ में सऊदी अरब किंगडम के शामिल होने के बारे में कार्यदल की रिपोर्ट" की विषयवस्तु के गलत

पाटन पर आधारित है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सऊदी अरब में फीड स्टॉक की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोपेन की कीमत में प्रवृत्तियों का प्रदर्शन होता है और यह सऊदी अरब द्वारा किसी भी रूप में प्रभावित अथवा नियंत्रित नहीं है। इस प्रकार के वाणिज्यिक कीमत निर्धारण फार्मूले से यह सुनिश्चित होता है कि प्रोपेन की घरेलू कीमतों से उचित लाभ तथा प्रोपेन की उत्पादन लागत की वसूली हो जाए।

iii. विगत में कई जांचों में माननीय प्राधिकारी ने सऊदी अरब को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है और इसलिए संबद्ध वस्तु के निर्यातकों को वही व्यवहार प्रदान किया जाना चाहिए।

iv. उपर्युक्त अनुरोधों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना किसी पाटनरोधी जांच में सब्सिडीसुदा कीमत, यदि कोई हो, का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

61. मै. सऊदी ओलियोलेफिस कंपनी ने यह स्वीकार किया है कि सऊदी आरमेको से एस पी सी द्वारा प्राप्त प्रोपेन की कीमत और अंतर्राष्ट्रीय मौके पर कीमत में अंतर है परंतु यह दावा किया गया है कि यह अंतर कुछेक कारकों अर्थात् अवसरचना में लागत, बचत; विपणन में लागत बचत; दीर्घावधिक संविदाओं से संबद्ध वाणिज्यिक लाभ; कम बाजारी अस्थिरता के कारण वाणिज्यिक मूल्य और बड़ी मात्रा में किए गए क्रय के वाणिज्यिक मूल्य के कारण होता है। उन्होंने यह अनुरोध किया है कि यद्यपि, प्रोपेन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत की तुलना उस कीमत के साथ करते समय, जिस कीमत पर एस पी सी द्वारा प्रोपेन की खरीद की गई है, प्राधिकारी को वास्तविक तुलना करने के लिए उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।

प्रकटन विवरण के बाद हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

62. प्रकटन विवरण के बाद सऊदी अरब के कुछेक निर्यातकों/उत्पादकों और सऊदी अरब किंगडम की सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अनुरोध किए हैं :-

(i) धारा 9 (1) (ग) (ii) और डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 के अंतर्गत प्राधिकारी को गहन बाजार अर्थव्यवस्था के मामले को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में उत्पादन लागत में संशोधन करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने जिस धारा 9 (1) (ग) (ii) पर भरोसा किया है वह समान वस्तु/संबद्ध वस्तु की कीमत के बारे में है न कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री/संघटक की कीमत के बारे में।

(ii) जहां तक सऊदी अरब के उत्पादन का संबंध है, प्रोपीलीन की उसकी उत्पादन लागत एक समान है चाहे उसका निर्यात किया गया हो अथवा घरेलू बिक्री। उत्पादन की कम लागत से प्राप्त लाभ का तात्पर्य उत्पादक द्वारा पाटन से कतई नहीं लगाया जा सकता।

(iii) प्राधिकारी का यह निष्कर्ष गलत है कि चूंकि सऊदी अरब के बाजार में फीड स्टॉक की कीमतें सरकार द्वारा नियंत्रित हैं, इसलिए वहां "विशेष बाजारी स्थिति" मौजूद है, जिसके परिणामस्वरूप सऊदी अरब में निर्यातकों/उत्पादकों की घरेलू लागत तथा कीमत को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) डब्ल्यू टी ओ में सऊदी अरब किंगडम को शामिल किए जाने से संबंधित अर्थनिरूपण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सऊदी अरब में प्रोपेन की कीमत बाजार संचालित है। इस संदर्भ में "डब्ल्यू टी ओ में सऊदी अरब किंगडम के शामिल होने से संबंधित कार्यदल की रिपोर्ट" का हवाला दिया जा सकता है और यह तर्क दिया गया है कि यह स्पष्ट होता है कि सऊदी अरब में प्रोपेन सहित प्राकृतिक गैस, द्रव फीड स्टॉक की कीमतों का निर्धारण बाजारी सिद्धांतों के अनुसार होता है। उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर यह अनुरोध किया गया है कि सऊदी अरब में फीड स्टॉक की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोपेन की कीमत की प्रवृत्तियों का प्रदर्शन होता है और ये सऊदी सरकार द्वारा किसी भी रूप में प्रभावित अथवा नियंत्रित नहीं हैं। इसके बजाए सऊदी अरब में लागू वाणिज्यिक कीमत संरचना "उत्पादक तथा ग्राहक के बीच सौदेबाजी" पर आधारित है। सऊदी सरकार द्वारा सऊदी अरब में केवल प्रोपेन की बिक्री हेतु वाणिज्यिक कीमत संरचना का समर्थन किया जाता है। इस प्रकार के वाणिज्यिक कीमत फार्मूले से प्रोपेन की घरेलू कीमत उचित लाभ तथा प्रोपेन की उत्पादन लागत की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। "डब्ल्यू टी ओ में सऊदी अरब किंगडम के शामिल होने से संबंधित कार्यदल की रिपोर्ट" में उल्लिखित उक्त फार्मूले से यह सुनिश्चित होता है कि प्रोपेन की घरेलू बिक्री कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों पर आधारित है जो निम्नलिखित वाणिज्यिक कारकों को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित हैं।

- निर्यातकों के लिए अपेक्षित अवसंरचना में बचत की लागत
- निर्यातकों के लिए अपेक्षित विपणन में बचत की लागत
- दीर्घावधिक घरेलू संविदाओं से जुड़ा वाणिज्यिक लाभ
- कम बाजारी अस्थिरता का वाणिज्यिक मूल्य
- बड़ी मात्रा में हुई खरीद का वाणिज्यिक मूल्य

(v) प्रोपेन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौके पर विद्यमान कीमत की तुलना उस कीमत से नहीं की जा सकती जिस पर सऊदी उत्पादक प्रोपेन की खरीद करते हैं। यह उल्लेख किया गया है कि उन्होंने प्रोपेन की आपूर्ति हेतु सऊदी आरामको के साथ बल्क आपूर्ति हेतु एक दीर्घावधिक करार (30 वर्ष) किया है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि दीर्घावधिक तथा बल्क आपूर्ति आधार पर खरीदी गई वस्तु की कीमतें हमेशा उक्त वस्तु की मौके पर कीमत की तुलना में कम होती हैं। प्राधिकारी ने सऊदी उत्पादकों द्वारा प्रदत्त प्रोपेन की वास्तविक कीमत की तुलना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोपेन की मौके पर कीमत के साथ करते हुए वास्तविक तुलना नहीं की है। प्राधिकारी को उस कीमत पर विचार

करना चाहिए जिस कीमत पर सऊदी उत्पादक प्रोपेन की खरीद करते हैं और उसकी तुलना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोपेन की मौके पर कीमत के साथ नहीं करनी चाहिए और यदि प्राधिकारी अन्य कंपनी द्वारा प्रदत्त प्रोपेन की कीमत में अंतर करना चाहते हैं तो उन्हें प्रोपेन की मौके पर कीमत पर विचार नहीं करना चाहिए और केवल उस कीमत पर विचार करना चाहिए जिस कीमत पर उसी प्रकार की कंपनी प्रोपेन की खरीद करती है ।

(vi) वास्तविक लागत के स्थान पर उपर्युक्तानुसार काल्पनिक लागत को लेना जरूरी नहीं है । प्रोपेन एन जी एल (प्राकृतिक गैस एवं द्रव) समूह का एक भाग है । मंत्रिपरिषद संकल्प वर्ष 1991 की सं 68 में एन जी एल की कीमत उन उत्पादों के लिए प्रभारित निर्यात कीमत से 30% कम रखी गई है । तथापि, के एस ए मंत्रि परिषद संकल्प सं. 260 दिनांक 7 जनवरी, 2002 में पूर्ववर्ती 1991 के संकल्प सं. 68 को रद्द कर दिया गया था । नए संकल्प 2002 की सं. 260 के अनुसार सऊदी अरब में फीड स्टॉक के रूप में प्रयुक्त एन जी एल की वाणिज्यिक कीमत लागू की थी । इसके अलावा के एस ए उच्चतम पेट्रोलियम मामला परिषद के निर्णय सं. 15 के तहत मंत्रि परिषद संकल्प सं. 260 को कार्यान्वित किया गया और उसमें ऐसी वार्ताशुदा कीमत संरचना का उल्लेख किया गया जिससे उत्पादन लागत तथा उचित लाभ की पूर्ण वसूली सुनिश्चित होती हो । संकल्प सं. 260 के साथ के साथ पठित निर्णय सं. 15 में यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक फार्मला निर्धारित है कि घरेलू एन जी एल कीमतें कुछेक लागत आधारित तथा अन्य वाणिज्यिक विचारों के लिए समायोजित अंतर्राष्ट्रीय विचार कीमतों पर आधारित होती हैं । इस प्रकार सऊदी अरब में प्रचलित प्रोपेन की बिक्री कीमत में वाणिज्यिक सिद्धांतों पर निर्धारित और उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच बातचीत द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का प्रदर्शन होता है ।

(vii) डब्ल्यू टी ओ में सऊदी अरब के शामिल होने और यह कि भारत सहित डब्ल्यू टी ओ के सभी सदस्यों ने "डब्ल्यू टी ओ में सऊदी अरब किंगडम के शामिल होने से संबंधित कार्यदल की रिपोर्ट " को पारित करने में समर्थन किया है । इससे स्पष्टतः उल्लिखित जांच में प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में विरोधाभास कापता चलता है ।

(viii) विगत में प्राधिकारी ने हमेशा सऊदी अरब को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है । यह नोट करना प्रासंगिक है कि पिछली किसी जांच में सऊदी अरब को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं माना गया है, इसलिए प्राधिकारी द्वारा सऊदी अरब को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानना प्राधिकारी की पूर्ववर्ती पद्धति के प्रतिकूल होगा ।

(ix) इस बात का अनुमान लगाते हुए परंतु उसे स्वीकार न करते हुए कि सऊदी घरेलू बाजार में प्रोपेन की कीमतें सरकार द्वारा नियंत्रित हैं, यह इस आशय का आधार नहीं हो सकता जिसे किसी पाटनरोधी जांच में उठाया जा सकता है । किसी खास कंपनी की उत्पादन लागत कीमतों पर सरकारी नियंत्रण अथवा निर्यातक कंपनी की सरकार द्वारा प्रदत्त छूट/सब्सिडी, घरेलू भारतीय कंपनी को क्षति, यदि कोई हुई हो, जैसे

कारकों के कारण भारतीय उत्पादकों की उत्पादन लागत की तुलना में कम होने की स्थिति में उसकी जांच किसी उचित जांच अर्थात् किसी सब्सिडीरोधी/प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी जांच में की जा सकती है।

- (x) आस्ट्रेलियाई दिशा निर्देश कच्ची सामग्री की लागत से संबंधित नहीं है अपितु उनका उद्देश्य ये है कि उस घरेलू बिक्री कीमत के मुद्दे का समाधान किया जाए जो सर्वप्रथम सामान्य मूल्य के निर्धारण में प्रयोग हेतु अनुचित है। इसी प्रकार चीन तथा कोरिया से रबड़ रसायनों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के जांच परिणामों का हवाला दिए जाने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि इस मामले में संगत जांच परिणाम चीन विशिष्ट थे जो पाटनरोधी जांच के संदर्भ में शामिल होने के प्रोटोकॉल के पैरा 15 के विशिष्ट प्रावधानों के अधीन भी है।
- (xi) "बाजार स्थिति" की अवधारण से संबंधित ई सी मूलभूत पाटनरोधी विनियम के अनुच्छेद 2.3 में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी बाजार स्थिति उदगम के देश में समान उत्पाद की बिक्री से संबंधित है न कि निविष्टि तथा लागत की मदों से। इसके अलावा, प्राधिकारी इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि ई सी पद्धति के उद्धारणों के रूप में उल्लिखित देश अर्थात् रूस और कजाकिस्तान सभी डब्ल्यू टी ओ के सदस्य नहीं हैं।
- (xii) सामान्य मूल्य के निर्धारण से संबंधित अमरीकी पाटनरोधी मैनुअल के अध्याय 8 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि "बाजार स्थिति" की अवधारण घरेलू बाजार में समान उत्पाद की बिक्री कीमत से संबंधित है।
- (xiii) डी जी ए डी द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित नीति डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार में किसी विधिक आधार के अनुरूप नहीं है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अनुसार ऐसी परिकलित लागत के प्रयोजनार्थ घरेलू कीमतों का परिकलन सामान्यतः जांचाधीन निर्यातक या उत्पादक द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। बशर्ते ऐसा रिकॉर्ड निर्यातक देश के सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार हो और उनमें विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबद्ध लागत का उचित प्रदर्शन होता हो।
- (xiv) जहां तक सऊदी उत्पादकों के रिकॉर्ड के सत्यापन और उनमें पोलीप्रोपीलीन के उत्पादन हेतु संबंधित उत्पादकों द्वारा व्यय की गई वास्तविक लागत के प्रदर्शन का संबंध है, इस बात का कोई कारण नहीं है कि उनके द्वारा रखे गए रिकॉर्डों की कच्ची सामग्री की लागत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अनदेखी क्यों की जानी चाहिए। डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार (अनुच्छेद 2.2) के अंतर्गत अयातक देश को यह अधिकार दिया गया है कि वह अंतिम उत्पाद की लागत की गणना कर सामान्य मूल्य का परिकलन करे न कि कच्ची सामग्री का परिकलन करने के बाद।

प्राधिकारी द्वारा जांच

63. सऊदी अरब की सरकार सहित सऊदी अरब के हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की निम्नानुसार जांच की गई है।

64. धारा 9 (1)(ग)(ii) में निम्नानुसार उल्लेख है :-

"जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

उक्त्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 में निम्नानुसार उपबंध है :-

"जब निर्यातक देश के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में उत्पाद की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश के बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो पाटन माजिन का निर्धारण किसी उचित तीसरे देश को निर्यात के समय समान उत्पाद की तुलनीय कीमत के साथ तुलना द्वारा किया जाएगा, बशर्ते यह कीमत प्रतिनिधिक हो अथवा उद्गम के देश में उत्पादन लागत जमा प्रशासनिक, बिक्री एवं सामान्य लागत तथा लाभ की उचित राशि की तुलना द्वारा किया जाएगा।

करार के अनुच्छेद 2.2.1 में निम्नानुसार उल्लेख है :-

उत्पादन लागत जमा बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागत की प्रति इकाई (निर्धारित तथा परिवर्तनीय) लागत से कम कीमत पर निर्यातक देश के घरेलू बाजार में समान उत्पाद की बिक्री अथवा किसी तीसरे देश को की गई बिक्री को कीमत की वजह से व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं माना जा सकता और उसे केवल उस स्थिति में सामान्य मूल्य के निर्धारण में अनदेखा किया जा सकता है यदि प्राधिकारी यह निर्धारित करें कि ऐसी बिक्री विस्तारित समयावधि में पर्याप्त मात्रा में की गई हैं और ये उस कीमत पर हुई हैं जिनसे उचित समयावधि के भीतर समस्त लागत की वसूली नहीं हो सकती है। यदि बिक्री के समय कीमतें लागत से कम हैं और जांच अवधि के लिए भारित औसत लागत से अधिक हैं, तो ऐसी कीमतों पर उचित समयावधि के भीतर लागत की वसूली हेतु विचार किया जाएगा।

65. यह देखा जाता है कि यद्यपि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1 में इस बात के निर्धारण की पद्धति का प्रावधान है कि क्या लागत से कम पर बिक्री "व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में" हुई है। तथापि, उक्त प्रावधान इस बात के निर्धारण की पद्धति के समापन से संबंधित नहीं है कि क्या ये बिक्रियां "व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में" हुई हैं। इस प्रावधान में इस बात के निर्धारण की संभावित पद्धतियों की मात्रा का भी प्रावधान नहीं है कि क्या ये बिक्रियां "व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में" हुई हैं। इस तर्क की पुष्टि अमरीका हॉट रोल्ड इस्पात (डब्ल्यू टी/डीएस 184/एबी/आर पैरा 147) के मामले में अपीलीय निकाय के निर्णय के मामले में इस विषय पर अपीलीय निकाय के इस निर्णय से होती है, जिसमें यह माना गया था कि उक्त प्रावधान इस बात के निर्धारण की पद्धतियों की मात्रा की समाप्ति से संबंधित नहीं है कि क्या बिक्रियां "व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में" हुई हैं:-

"हम यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1 में ही इस बात के निर्धारण की पद्धति का प्रावधान है कि क्या लागत से कम पर बिक्रियां "व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में" की गई हैं। तथापि, उक्त प्रावधान इस बात के निर्धारण की पद्धतियों की मात्रा के समापन से संबंधित नहीं है कि क्या बिक्रियां "व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में" की गई हैं और न ही इस बात के निर्धारण की संभावित पद्धतियों की मात्रा से संबंधित है कि क्या कम कीमत पर बिक्रियां "व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में" में की गई हैं। अनुच्छेद 2.2.1 में इस बात के निर्धारण की पद्धति तय की गई है कि कि क्या किन्हीं दो पक्षकारों के बीच बिक्रियां "व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में" हुई हैं; इससे संबद्ध पक्षकारों के बीच सौदों के अधिक विशिष्ट मुद्दे का समाधान नहीं होता है। ऐसे पक्षकारों के बीच सौदों में स्वयं संबद्धता एक ऐसा संकेत हो सकती है कि लागत से अधिक परंतु सामान्य बाजार कीमत से कम पर की गई बिक्रियां व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं हो सकती हैं अतः इस प्रकार के सौदे जांच प्राधिकारियों की विशेष संवीक्षा के अधीन हो सकते हैं।

66. उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी विशेष बाजार स्थिति के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति के समाधान की अपेक्षा की गई है जिसका संबद्ध वस्तु की संगत लागत तथा कीमत पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थितियों में प्राधिकारी ऐसी अन्य सूचना का सहारा ले सकते हैं जो ऐसी विकृतियों से अप्रभावित हो। उपर्युक्त खंड का मूल उद्देश्य प्राधिकारी को निष्पक्ष तथा उचित "सामान्य मूल्य" निकालने में समर्थ बनाना है।

67. चूंकि फीड स्टॉक अर्थात् प्रोपेन (प्रमुख कच्ची सामग्री) की कीमत, उसके बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम है और पुनश्च यह अंतर सऊदी अरब की सरकार के नीतिगत निर्णय के कारण है, इसलिए सऊदी अरब में एक ऐसी विशेष बाजार स्थिति विद्यमान हुई कही जा सकती है जिसमें संबद्ध वस्तु की घरेलू लागत और कीमत हमेशा निर्यात कीमत की तुलना में काफी कम रहेगी। इन परिस्थितियों में सऊदी अरब के उत्पादकों/निर्यातकों को घरेलू खपत एवं निर्यातों के लिए दोहरी कीमतें रखने हेतु सऊदी सरकार के पूर्ण हस्तक्षेप के कारण विदेशी अन्य उत्पादकों की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को

"विशेष बाजार स्थिति" के दायरे में लाया जाता है। "विशेष बाजार स्थिति" पद की

उक्त शिकवियाँ ध्याख्या इसी ढंग से डब्ल्यू टी ओ के कुछेक सदस्यों के प्राधिकारियों द्वारा भी की गई हैं। प्राधिकारियों का ध्यान खास तौर पर इस मुद्दे पर निम्नलिखित संदर्भों की ओर भी कि इनका विचारकृत किया जाता है कि शिकवियाँ किशोर उम्र वाले बच्चे को हक है किशोरों के हक के न्यायिक प्रक्रिया की शिकवियाँ

● "विशेष बाजार स्थिति" से संबंधित आस्ट्रेलियाई दिशानिर्देशों में यह निर्धारित है कि "विशेष बाजार स्थिति" पद में ऐसी स्थिति सहित कई संभावित स्थितियाँ शामिल हैं जिसमें निर्यात के देश में घरेलू बिक्री कीमत सरकारी प्रभाव द्वारा अत्यधिक प्रभावित कर दी जाती है जिससे वे कीमतें घरेलू सामान्य मूल्य निर्धारित करने में उपयोग हेतु अनुचित बन जाती हैं।

● निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन और कोरिया से रबड़ रसायनों के मामले में (मामला सं. 14/5/2007-डी जी ए डी) में यह अवधारित किया है कि कच्ची सामग्री की कीमत को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें उत्पादन से समुचित ढंग से संबद्ध लागत का प्रदर्शन नहीं होता है।

● ई सी ने ऐसी किसी आकस्मिकता का प्रावधान करने के लिए कानून में संशोधन किया है जिससे यह पता चलता है कि ऐसी कोई पद्धति डब्ल्यू टी ओ के अनुरूप है। ई सी ने रूस और कजाकिस्तान सहित कई मामलों में इस तर्काधार को लागू किया है जिनमें ई सी ने इस आधार पर स्थानीय आपूर्तिकर्ता से निर्यातक द्वारा गैस की खरीद कीमत को अस्वीकृत किया है कि गैस की निर्यात कीमत की तुलना में खरीद की लागत में उत्पादन से संबद्ध लागत का उचित प्रदर्शन नहीं होता है।

● इसके अलावा, अमरीकी प्राधिकारियों ने पाटनरोधी मैनुअल के अध्याय 8 में यह उल्लेख किया है कि "कोई विशेष बाजार स्थिति" उस समय विद्यमान हो सकती है जब किसी किशोर विदेशी बाजार में कीमत पर इतना व्यापक सरकारी नियंत्रण हो कि उक्त बाजार में कीमतों शिकवियों को प्रतिस्पर्धा के अनुसार निर्धारित त माना जा सके।

● 68वीं संसदीय अरब के निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के बारे में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग तथा निर्यातकों के तर्कों की जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि इस सत्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि जिस कीमत पर संसदी अरब से फीड स्टॉक का निर्यात किया जाता है उस कीमत की तुलना में संसदी अरब के भीतर घरेलू खपत की बिक्री होने की स्थिति में संसदी अरब में फीड स्टॉक की कीमतें काफी कम हैं। कुछेक उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने लिखित अनुरोधों में यह भी स्वीकार

किया है कि प्रोपेन की कीमतें प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से कम हैं। तथापि, उनमें से कुछ ने यह तर्क दिया है कि अवसंरचना में लागत बचत, विपणन में लागत बचत, दीर्घावधिक संविदाओं से संबद्ध वाणिज्यिक लाभ, कम बाजारी अस्थिरता के कारण वाणिज्यिक मूल्य तथा बड़ी मात्रा में खरीद के वाणिज्यिक मूल्य जैसे अंतर्निहित लाभों के कारण संसदी अरब में फीड स्टॉक की कीमतें कम होती हैं। तथापि, दोहरी/अलग कीमत की मौजूदगी और यह सत्य अविवादित रहता है कि घरेलू कीमतें काफी कम हैं, एक मामला कि घरेलू उद्योग ने इस बात का जोरदार तर्क दिया है कि घरेलू तथा निर्यात बाजार के बीच कीमतों में अंतर अथवा लागत के कारण किसी समायोजन को डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी क़रार के अनुच्छेद 2.4 अथवा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 6(i) के अनुसार वास्तविक सूचना के साथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए। केवल कथनों

तथा अभिकथनों के आधार पर कोई समायोजन नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे समायोजनों के दावे के समर्थन में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी को कोई सकारात्मक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। समूची जांच की कार्रवाई और मौके पर सत्यापन के समय निर्यातकों ने केवल ऐसे अंतर तथा उसकी मात्रा के कारणों का पता लगाने का अवसर प्रदान किया है। तथापि, प्रतिवादियों ने कीमत अंतर के कारणों के बारे में अपने अनुरोध की पुष्टि नहीं की है।

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी सऊदी प्रतिवादी ने ऐसे किसी साक्ष्य के साथ दावे की पुष्टि नहीं की है कि सऊदी अरब में प्रोपेन की कीमतों का निर्धारण उत्पादन एवं उपभोक्ताओं के बीच सौदेबाजी के आधार पर किया गया था। यहां तक कि के एस ए मंत्री परिषद संकल्प सं. 267, दिनांक 7 जनवरी, 2002 और के एस ए उच्चतम पेट्रोलियम कार्य मंत्रिपरिषद के निर्णय सं. 15 की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई है ताकि प्राधिकारी उनके दावे की जांच कर सकें। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि घरेलू बाजार में प्रोपेन की कीमत उसके निर्यात कीमत से काफी कम है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि अवसर प्रदान करने के बावजूद भी सऊदी प्रतिवादियों के इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है कि सऊदी अरब में प्रोपेन की कीमतें दुलाई लागत, अवसरचना, विपणन, दीर्घावधिक संविदा, बड़ी मात्रा में खरीद आदि जैसे कुछेक कारकों की वजह से कम है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि सऊदी अरब के प्रतिवादियों द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने और मात्रा निर्धारित किए जाने के बाद ही कोई समायोजन किया जा सकता है।

70. जहां तक इस तर्क का संबंध है, कि एन जी एल की विनियमित कीमत प्रणाली को चुनौती देना अब संभव नहीं है, प्राधिकारी का यह मत है कि शामिल होने संबंधी प्रोटोकॉल में ऐसा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सुझाव नहीं है जिससे पाटनरोधी उपबंधों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच से संबंधित शक्तियां प्रतिबंधित होती हैं अथवा उसका दायरा कम होता हो। किसी भी हालत में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वह डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार का पूर्ण सम्मान करते हुए भारतीय कानूनों के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज करे।

71. जहां तक पद्धतियों और निर्णीत मामलों की प्रयोज्यता और प्रासंगिकता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार स्थिति से संबंधित आस्ट्रेलियाई दिशानिर्देशों में यह निर्धारित है कि "विशेष बाजार स्थिति" पद में ऐसी स्थिति सहित कई संभावित स्थितियां शामिल हैं जिसमें निर्यात के देश में घरेलू बिक्री कीमत सरकारी प्रभाव द्वारा अत्यधिक प्रभावित कर दी जाती है जिससे वे कीमतें घरेलू सामान्य मूल्य निर्धारित करने में उपयोग हेतु अनुचित बन जाती हैं। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आस्ट्रेलियाई दिशा-निर्देशों में केवल घरेलू कीमतों का उल्लेख है न कि लागत का, प्राधिकारी का यह मत है कि ऐसा कोई निष्कर्ष उक्त दिशानिर्देशों के पाठ से नहीं निकलाता है जबकि यह स्वीकृत तथ्य है कि संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतें प्रमुख कच्ची सामग्री की सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों से अत्यधिक प्रभावित हो रही है।

72. आगे यह अनुरोध किया गया है कि बेलारूस और रूस से पोटेशियम क्लोराइड के मामले में ई सी जांच परिणाम (परिषद विनियम सं. 1050/2006, 11 जुलाई, 2006) ऐसे देशों के संदर्भ में है जो डब्ल्यू टी ओ के सदस्य नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तर्क सारहीन है क्योंकि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि प्रश्नगत मुद्दे को डब्ल्यू टी ओ सदस्यों और गैर-सदस्यों के बीच अलग-अलग ढंग से लागू किया जा सकता है। इसके अलावा, भारतीय कानून में प्रश्नगत उपबंधों के संदर्भ में ऐसा कोई भेद नहीं है।
73. जहां तक चीन तथा कोरिया से रबड़ रसायनों के मामले में (मामला सं. 14/5/2007-डी जी ए डी) प्राधिकारी के स्वयं के निर्णय का संबंध है, यह माना गया था कि कच्ची सामग्री की कीमतें स्वीकार नहीं की जा सकतीं क्योंकि उनमें गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से प्राप्त उत्पादन से संबद्ध लागत का उचित प्रदर्शन नहीं होता है और प्राधिकारी ने इसके बजाए उत्पादन लागत के निर्धारण हेतु कच्ची सामग्री की बाजार कीमत का उपयोग किया है। उपरोक्त निर्णय का अनुपात इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर प्रत्यक्षतः लागू होता है क्योंकि उक्त निर्णय का मूलभूत तर्कधार यह था कि यदि बाजार अर्थव्यवस्था में लागत में सही लागत (कारण कुछ भी हो) का प्रदर्शन नहीं होता है, तो ऐसी कच्ची सामग्री की लागत को अस्वीकृत किया जा सकता है। यह तथ्य कोई महत्व नहीं रखता है कि कीमत इस आधार पर अस्वीकृत की गई है कि कच्ची सामग्री गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से प्राप्त की गई थी क्योंकि एन एम ई व्यवहार से संबंधित प्रावधान (पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा 7) कोरिया गण. जैसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश पर लागू नहीं होता है।
74. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह मत है कि उपर्युक्त संदर्भों का हवाला "विशेष बाजार स्थिति" के संदर्भ में सही ढंग से दिया गया है। इसके अलावा, सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस बात की जांच करना जरूरी है कि क्या सऊदी उत्पादकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए दावा की गई लागत में उत्पादन से संबद्ध लागतों और विचाराधीन उत्पादों की बिक्री का उचित प्रदर्शन होता है। वस्तुतः विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु दावा की गई लागत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री अथवा अन्य निविष्टियों की कीमत शामिल होगी। इस बात का खंडन नहीं किया गया है कि सऊदी अरब में प्रोपेन की कीमत उसके निर्यात कीमत से काफी कम है। ऐसे किसी अंतर के लिए किसी भी सऊदी प्रतिवादक ने साक्ष्य के साथ कोई औचित्य नहीं दिया है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि सऊदी अरब में ऐसी विशेष बाजार स्थिति मौजूद है जिसकी वजह से संबद्ध वस्तु की कीमतें प्रतिस्पर्धी ढंग से निर्धारित नहीं की जा सकती जिसका सऊदी अरब में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का उचित और निष्पक्ष निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है।
75. यह तर्क दिया गया है कि दोहरी कीमत के मुद्दे का समाधान केवल सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार के अंतर्गत ही किया जा सकता है। इस संदर्भ में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में मुद्दा यह नहीं है कि क्या के एस ए की

अतः हमारी राय में अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत जांचाधीन निर्यातक या उत्पादक द्वारा रखे गए एंरिकोर्डों के आधार पर लागत की गणना करने और लागत के उचित आवंटन के बारे में उपलब्ध समस्त साक्ष्य पर विचार करने के दायित्व सहित जांच प्राधिकारियों को कुछेक सकारात्मक दायित्व सौंपे गए हैं। तथापि, इनमें से कोई भी दायित्व पूर्ण नहीं है, क्योंकि दोनों विमिलों में उक्त दायित्व तभी ("बशर्त") लागू होते हैं जब कुछेक शर्तों की पूर्ति होती हो। अतः इन शर्तों की भूमिका सदस्यों पर सकारात्मक दायित्व डालने की नहीं है अपितु ऐसी परिस्थितियाँ निर्धारित करने की है जिनमें कुछेक सकारात्मक दायित्व लागू होते हैं अथवा लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार हमारी राय में अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत यह अपेक्षित नहीं है कि

लागत की गणना जी.ए.ए.पी. के अनुसार की जाए और नहीं यह अपेक्षित है कि उसमें विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबद्ध लागत का उचित प्रदर्शन होता है। इसके बजाए इसमें साधारणतः यह अपेक्षित है कि लागत की गणना उस सीमा तक निर्यातक या उत्पादक के रिकॉर्डों के आधार पर की जाए जहां तक ये रिकॉर्ड जी.ए.ए.पी. के अनुसार हैं और उनमें विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबद्ध लागत का उचित प्रदर्शन होता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 2.2.1.1 में यह अपेक्षित नहीं है कि किसी जांच प्राधिकारी द्वारा किए गए समस्त आवंटनों का ऐतिहासिक रूप से उपयोग निर्यातक या उत्पादक द्वारा किया गया है। इसके बजाए इसमें सामान्य उपबंध यह है कि जांच प्राधिकारियों को उस सीमा तक प्रतिवादियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आवंटनों सहित लागत के उचित आवंटन से संबंधित उपलब्ध समस्त साक्ष्य पर विचार करना चाहिए। जहां तक ऐसे आवंटनों का ऐतिहासिक रूप से उपयोग उक्त निर्यातक या उत्पादक द्वारा किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अनुच्छेद 2.2.1.1 के बारे में कनाडा के तर्कों की जांच करेंगे।

। है।

78. अमरीका - ड्राम्स (डब्ल्यू टी/डी एस 00/आर (पैरा 6.66)) से संबंधित पैनल ने कोरिया के इस दावे का निवारण किया है कि अमरीकी प्राधिकारी ने आयात के उस आंकड़ों की अनदेखी कर अनुच्छेद 2.2.1.1 के प्रथम वाक्य पर असंगत रूप से कार्रवाई की है जिसमें उक्त अनुच्छेद के परंतुक में निर्धारित दोनों अपेक्षाओं अर्थात् "सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार" और "लागत का उचित प्रदर्शन" की पूर्ति होती है।

79. मिश्र-स्टील रीबार (डब्ल्यू टी/बी एस 211/आर (पैरा 7.393)) मामले में पैनल ने यह नोट किया कि दोनों अनुच्छेदों 2.2.1.1 तथा 2.2.2 में "घटकों पर जोर दिया गया है। प्रथम यह कि उत्पादन लागत की गणना संदर्भाधीन कंपनी द्वारा रखी गई वास्तविक बहियों और रिकॉर्डों के आधार पर करनी होती है जहां तक ये सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार रखी गई है परंतु दूसरा यह कि शामिल की जाने वाली लागत वह होती है जिसमें विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन एवं बिक्री से संबंधित लागत का उचित प्रदर्शन होता हो। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त अनुच्छेदों की दोनों अपेक्षाओं को अलग-अलग रूप में पढ़ना होगा।

80. प्रोपेन के संबंध में सऊदी अरब में प्रचलित दोहरी कीमत नीति की मौजूदगी के कारण संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री कीमत पर प्रतिस्पर्धी रूप से निर्धारित कीमत के रूप में विचार नहीं किया जा सकता। यह देखा जाता है कि प्रोपेन की निर्यात कीमत की तुलना करने पर संबद्ध वस्तु की सऊदी उत्पादकों के लिए प्रोपेन की लागत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन से संबंधित लागत का उचित प्रदर्शन नहीं होता है।

81. जहां तक सऊदी अरब को विचाराधीन उत्पाद के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालनरत माने जाने के बारे में घरेलू उद्योग का संबंध है, प्राधिकारी की सुविचारित राय यह है कि घरेलू उद्योग के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के घटकों की पूर्ति नहीं होती है। तथापि, उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब के उत्पादकों/निर्यातकों की घरेलू लागत और कीमत को विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में प्रचलित विशेष बाजार स्थितियों

के कारण उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लागत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबंधित लागत का उचित प्रदर्शन नहीं होता है। प्राधिकारी की सुविचारित राय यह है कि ऐसे सामान्य मूल्य पर आधारित कोई तुलना निष्पक्ष और उचित नहीं होगी।

82. अतः निष्पक्ष और उचित तुलना करने के लिए प्राधिकारी ने प्रोपेन की कीमत के संबंध में उत्पादन लागत में संशोधन करना उचित समझा। इस संशोधन के बाद जहां घरेलू बिक्री कीमत उत्पादन लागत से अधिक है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण निर्यातक देश में खपत के लिए नियत समान वस्तु के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। तथापि, जहां घरेलू कीमत उत्पादन लागत से कम है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण धारा 9 (1) (ग) (ii) में प्रदत्त विकल्पों के अनुसार किया गया है। ऐसे मामलों में प्राधिकारी ने जहां घरेलू कीमत स्वीकार्य नहीं पाई गई थी, वहां सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु अपनी सुसंगत पद्धति का सहारा लिया है।

सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति

83. प्राधिकारी ने उन सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया है जिन्होंने अपेक्षित सूचना प्रदान की है। सऊदी अरब के निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के बारे में उपर्युक्त मुद्दे के अलावा सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अपनाई गई सामान्य पद्धति निम्नानुसार है।
84. पहले यह देखा गया था कि क्या प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उनके घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्रियां घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्रतिनिधिक और व्यवहार्य हैं और क्या प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण पूरा होता है। जहां कहीं भी प्रतिवादियों ने उनके घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के सौदावार ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं, वहां इस प्रकार प्रदत्त सूचना पर व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी जांच और पर्याप्तता जांच करने के बाद वस्तु के सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु भरोसा किया गया है। इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच अवधि के भीतर संबद्ध वस्तु तथा कच्ची सामग्री की कीमत में काफी घट-बढ़ रही थी। प्राधिकारी ने प्रत्येक सहयोगी निर्यातक/उत्पादक के लिए माहवार आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की है।
85. जहां कोई बिक्री नहीं हुई है अथवा कोई खास बिक्री नहीं हुई है, वहां प्रतिवादी के दावे के अनुसार और प्राधिकारी के सत्यापन के अनुसार उत्पादन लागत स्वीकार की गई है जो उपर्युक्त पैरा 84 में उल्लिखित पुनर्गणना के अधीन है और जहां ऐसा करना व्यवहार्य नहीं हुआ था, वहां प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर किया है।

86. जहां होमोपॉलीमर और को पॉलीमर के संबंध में आंकड़े अलग-अलग आधार पर उपलब्ध थे, वहां पाटन मार्जिन का विश्लेषण और निर्धारण तदनुसार अलग-अलग किया गया है।

सामान्य मूल्य

ओमान

मै. ओमान पोलीप्रोपीलीन एल एल सी

87. ओपीपी ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को अपने जांच परिणाम पर पुनर्विचार करना चाहिए कि घाटे पर किए गए सौदे कुल बिक्री के 20% से अधिक हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी लाभ पर की गई बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य के इस प्रकार के निर्धारण करने में और घाटे पर हुए कई सौदों को अलग रखकर गलती कर रहे हैं। ऐसा करते समय प्राधिकारी ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा है कि किसी समय विशेष पर उत्पादन लागत में परिवर्तन किए जाने का इस प्रश्न पर प्रभाव पड़ता है कि क्या उक्त समयावधि से संबंधित कोई सौदा वास्तव में घाटे पर हुआ है अथवा नहीं। उदाहरणार्थ जांच अवधि के दौरान माह-दर-माह तेल की लागत और प्रोपीलीन की लागत में संबंधित उतार-चढ़ाव का माह-दर-माह उत्पाद की कीमत पर प्रभाव पड़ेगा और क्या उत्पाद की बिक्री कीमत से उससे संबंधित लागत प्राप्त हो गई है।
88. उठाए गए मुद्दे की जांच की गई है और प्राधिकारी का यह मत है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की लागत और कीमत में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए कंपनी के लिए सामान्य मूल्य का सही निर्धारण उसे प्रदत्त मासिक लागत आंकड़ों के आधार पर किया गया है।
89. सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत और सत्यापित सूचना/आंकड़ों पर भरोसा किया गया है। सत्यापन के दौरान प्रतिवादी ने कुछेक समायोजनों का दावा किया जिनका सत्यापन कर स्वीकार किया गया था। प्राधिकारी ने उत्तर की परिशिष्ट 8 में किए गए उल्लेखानुसार माहवार लागत के व्यौरों के आधार पर व्यापार की सामान्य प्रक्रिया (ओ सी टी) संबंधी जांच की है। यह नोट किया गया है कि जांच अवधि में घाटे पर किए गए सौदे घरेलू बाजार में हुई कुल बिक्री के 20% से अधिक थे। अतः प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के उपबंधों के अनुसार लाभ पर की गई बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण सामान्य मूल्य का निर्धारण आंकड़ों के माहवार विश्लेषण के आधार पर किया गया है।

असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

90. ओमान के किसी अन्य निर्यातक तथा उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उनका सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

सऊदी अरब**मै. एडवांस्ड पॉलीप्रोपीलीन कंपनी, सऊदी अरब**

91. कंपनी के उत्तर के अवलोकन से यह पता चलता है कि कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात मै. विनमार इंटरनेशनल लि. तथा मै. मित्सुबिसी कार्पो. सिंगापुर द्वारा किया गया है। तथापि केवल मै. विनमार इंट. लि. ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है और इस प्रकार मै. एडवांस्ड पॉलीप्रोपीलीन कंपनी, सऊदी अरब तथा मै. विनमार इंट. लि. के संबंध में ही अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है।

92. जांच की कार्रवाई के दौरान कंपनी ने यह उल्लेख किया था कि वर्ष 2009 में कंपनी का नाम बदलकर एडवांस्ड पेट्रोकेमिकल कंपनी कर दिया गया है, तथापि स्वामित्व या प्रबंधन (निदेशक मंडल) में तदनुसारी कोई परिवर्तन नहीं किया गया था और कोई विलय अथवा अधिग्रहण शामिल नहीं था। श्रेयधारकों तथा निदेशकों की सूची प्रस्तुत की गई थी। यह स्पष्ट किया गया था कि एस.ए.जी.आई.ए. का तात्पर्य कंपनी के औद्योगिक निवेश लाइसेंसों से है जिसमें प्रमुख श्रेयधारकों के नाम भी दर्ज हैं। संबद्ध अंतरनियम/उप-नियम भी अनुवाद सहित प्रस्तुत किए गए थे। कंपनी ने अपने बाह्य सऊदी काउंसिल डॉ. वालिद अल-नुवाइजर द्वारा एक अधिप्रमाणन (लाइसेंस तथा उसके अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित) भी यह कहते हुए अलग से दायर किया है कि नाम में परिवर्तन सऊदी कानून के उपबंधों के अनुसार है और यह कि नाम में परिवर्तन 17 मार्च, 2009 को किया गया है और उसमें स्वामित्व या प्रबंधन में तदनुसारी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस आशय के समर्थकारी दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए थे जिसकी एक प्रति सार्वजनिक फाइल में रखी गई थी। तदनुसार प्राधिकारी ने इस जांच के प्रयोजनार्थ कंपनी के नाम में परिवर्तन को रिकॉर्ड में ले लिया है।

93. कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों की जांच और सत्यापन किया गया था। कंपनी के उत्तर के अवलोकन से यह पता चला कि प्रतिवादी ने घरेलू बाजार में ऑफ स्पेक सामग्री की बिक्री की है जबकि भारत की निर्यातित संबद्ध वस्तु विभिन्न ग्रेडों की थी। घरेलू बाजार में बेची गई ऑफ स्पेक सामग्री से संबंधित और उत्तर की परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि प्रतिवादी ने मई, 2008 से दिसंबर, 2008 तक भारत की संबद्ध वस्तु को निर्यात किया है जबकि उसकी घरेलू बिक्री केवल नवंबर, और दिसंबर, 2008 की अवधि में की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सामान्यतः पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत और संबद्ध वस्तु की कीमत में उस अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है। जब घरेलू बिक्रियों की गई थीं अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रतिवादी द्वारा की गई घरेलू बिक्रियों को सामान्य मूल्य एवं पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ तुलनीय तथा प्रतिनिधिक नहीं माना जा सकता। यह नोट किया गया है कि कंपनी ने जांच अवधि में उच्च अस्थिरता के कारण सामान्य मूल्य के माहौल निर्धारण का अनुरोध किया है। इसे स्वीकार किया गया है और आंकड़ों का विश्लेषण मासिक आधार पर किया गया है।

94. प्रकटन विवरण के उत्तर में ए.पी.पी.सी.ने यही तर्क दिया है कि ए.डी.ए.डी. द्वारा समूची जांच अवधि में रहे उसके सामान्य मूल्य के आधार के रूप में घरेलू बिक्री का उपयोग न करने के निर्णय से यह तथ्य रेखांकित होता है कि यद्यपि घरेलू बाजार में बेचे गए "ऑफ स्पेक" उत्पाद और भारत को निर्यातित दोनों ग्रेडों में ऐसी अलग-अलग

रासायनिक विशेषताएं हैं जिनसे वे अलग-अलग प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बन जाएंगे, दोनों अलग-अलग ग्रेडों की उत्पादन प्रक्रिया एक समान रहती है और उत्पाद की रासायनिक संरचना में छिटपुट अंतर से उसका मूलभूत स्वरूप अर्थात् पॉलीप्रोपीलीन में परिवर्तन नहीं होता है। अतः कंपनी की राय यह है कि उक्त आधार पर कंपनी की घरेलू बिक्री की डी जी ए डी द्वारा अनदेखी किए जाने का निर्णय न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा, यदि प्राधिकारी ए पी पी सी के लिए परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर अपनी कार्य प्रणाली की पुष्टि करते हैं तो कंपनी का यह अनुरोध है कि निष्पक्षता के रूप में सामान्य मूल्य के लिए अतिरिक्त समायोजन किए जाने चाहिए। वस्तुतः इस समय परिकलित सामान्य मूल्य के लिए प्रयुक्त कंपनी की पूर्ण उत्पादन लागत में सयंत्र में हैंडलिंग प्रभार शामिल है, जिनकी कटौती निर्यात कीमत में से की गई है। परिणामतः परिकलित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कटौती परिकलित सामान्य मूल्य में से की जाए। ए पी पी सी ने यह गणना की है कि परिशिष्ट 1 में सूचित इन हैंडलिंग प्रभारों की राशि ऋण पत्रों के बिना बीजक मूल्य के 0.90% बनती है। कंपनी का प्रस्ताव परिकलित सामान्य मूल्य में कटौती के रूप में इसी अनुपात को लागू करने का है।

95. प्राधिकारी का यह मत है कि ऑफ स्पैक सामग्री की कीमत मानक सामग्री से कम रखी जाती है जिससे निष्पक्ष और उचित तुलना नहीं होगी। अतः मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी का यह मत है कि परिकलित लागत के आधार पर निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने का निर्णय सही है। तथापि, जहां तक वस्तु की हैंडलिंग के लिए 0.90% के समायोजन के दावे का संबंध है, उसे स्वीकार किया गया है और सामान्य मूल्य तथा परिणामी पाटन मार्जिन की तदनुसार पुनः गणना की गई है।
96. तदनुसार प्राधिकारी ने परिशिष्ट 8 में उनके द्वारा सूचित बनाने और बेचने की इकाई लागत के आधार पर (इन जांच परिणामों के पैरा 84 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उत्पादन लागत की पुनः गणना के अधीन) माहवार आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है और 5% की दर से लाभ मार्जिन जोड़ा है।

मै. सऊदी पोलियोलेफिन्स कंपनी (एस पी सी)

97. मै. सऊदी पोलियोलेफिन्स कंपनी ने दिनांक 26.8.2009 के अपने पत्र द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया है कि उनकी ओर से असावधानीवश हुई गलती की वजह से एस पी सी द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु के एक निर्यातक के नाम का उल्लेख गलती से हो गया था और उसका उल्लेख प्रारंभिक जांच परिणामों में भी किया गया था। यह उल्लेख किया गया है कि निर्यातक का सही नाम "बसेल पोलियोलेफिन्स कंपनी" की बजाए "बसेल इंटरनेशनल ट्रेडिंग एफ जेड ई, दुबई" है। कंपनी ने इस दावे का समर्थन दस्तावेजों को प्रस्तुत करके किया है जिनकी एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी रखी गई है। अतः प्राधिकारी ने इन जांच परिणामों में नाम में सुधार कर दिया है।
98. एस पी सी द्वारा प्रश्नावली के प्रस्तुत किए गए उत्तर को पढ़ा गया था और सत्यापित किया गया था। यह पाया गया था कि प्रतिवादी ने अपने उत्तर में संगत परिशिष्टों में संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत संबंधी ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं। कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों को इन जांच परिणामों के पैरा 84 में यथार्थित उत्पादन लागत के आंकड़ों की पुनः गणना के अधीन स्वीकार किया गया था। तदनुसार ओ सी टी

परीक्षण करने के बाद सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। निर्यातक द्वारा दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार किया गया है। यह पाया गया है कि 20% से अधिक घरेलू सौदे घाटे में किए गए हैं अतः निर्यातक के सामान्य मूल्य का निर्धारण महीनावार आधार पर लाभ कमाने वाली बिक्रियों के अनुसार किया गया है क्योंकि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव हुए हैं। जब भी किसी माह विशेष में लाभप्रद बिक्रियां नहीं हुई थी तब उस महीने के लिए सामान्य मूल्य की गणना वस्तु को बनाने और बेचने की इकाई लागत और 5% की दर से लाभ मार्जिन को जोड़कर की गई है।

99. सऊदी पोलियोलिफिन कंपनी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी ने एस पी सी के लिए उत्पादन लागत की गणना करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा विचार की गई प्रोपेन की कीमत को उन्हें प्रस्तुत नहीं किया है। उत्पादन की परिकल्पित लागत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा विचार की गई प्रोपेन की कीमत के अभाव में वह प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए सामान्य मूल्य पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।
100. प्राधिकारी ने विचार की गई प्रोपेन की कीमतों का पर्याप्त प्रकटन किया है। विचार की गई प्रोपेन की कीमतों से संबंधित ब्यौरे सार्वजनिक फाइल में भी रखे गए थे।
101. सऊदी पोलियोलिफिन कंपनी द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि आंकड़े/अनुरोध एस पी सी के रिकॉर्डों के अनुसार आंकड़ों पर आधारित थे। उदाहरणार्थ किसी सौदा विशेष के लिए यदि एस पी सी द्वारा जांच अवधि के दौरान बीजक प्रस्तुत किए गए थे तो उन पर आंकड़ों में विचार किया गया था। यद्यपि वह बिक्री जांच अवधि के पश्चात डीआईटी या एन पीआईएमसी द्वारा की गई थी। इसी प्रकार यदि जांच अवधि के दौरान कोई सौदा विशेष किया गया था जिसके बीजक जांच अवधि से पहले एस पी सी द्वारा तैयार किए गए थे तो ऐसी बिक्रियों को प्राधिकारी के समक्ष किए गए अनुरोधों से बाहर रखा गया है। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में पी आई टी के माध्यम से एस पी सी के लिए पाटन मार्जिन की गणना करते समय उन सौदों को बाहर रखा है जिनके लिए एस पी सी द्वारा दिसंबर, 2008-09 बीजक तैयार किए गए थे परंतु उन्हें जनवरी, 2009 में बी आई टी द्वारा पूरा किया गया था। यह अनुरोध किया गया है कि इन सौदों पर बीआईटी के जरिए एस पी सी के लिए पाटन मार्जिन की गणना के प्रयोजनार्थ भी विचार किया जाए।
102. प्राधिकारी का यह मत है कि बीआई टी के जरिए एस पी सी के लिए पाटन मार्जिन की गणना करते समय उसे उन सौदों से बाहर रखना सही है जिनके लिए एस पी सी द्वारा दिसंबर, 2008 में बीजक तैयार किए गए थे परंतु जनवरी, 2009 में बी आई टी द्वारा जिन्हें पूरा किया गया था क्योंकि यह जांच अवधि के बाद हुआ है।

मै. सऊदी यूरोपियन पेट्रोकेमिकल कंपनी (आई बी एन जाहर), मै. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन, सऊदी अरब (एस ए बी आई सी) के जरिए सऊदी अरब

103. यह देखा गया है कि आई बी एन जाहर और यान्टेड जो पॉलीप्रोपीलीन के दो विनिर्माता हैं, एस ए बी आई सी से संबद्ध हैं। इन दोनों उत्पादकों द्वारा उत्पादित पॉलीप्रोपीलीन की बिक्री एस ए बी आई सी द्वारा घरेलू बाजार और निर्यात बाजार दोनों में की जाती है।

104. दोनों उत्पादक कंपनियां उनके द्वारा उत्पादित पोलीप्रोपीलीन को एस ए बी आई सी को हस्तांतरित करती हैं और इस हस्तांतरण को अनंतिम कीमत पर की गई बिक्री के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। चूंकि एस ए बी आई सी को किए गए सभी हस्तांतरण सऊदी अरब किंगडम के भीतर हैं, इसलिए इन सौदों को इन उत्पादक कंपनियों द्वारा घरेलू बिक्रियों के रूप में दर्शाया गया है। एस ए बी आई सी द्वारा क्रेता से ली जाने वाली वास्तविक अंतिम कीमत में से माल वहन/वितरण के खर्चों में हुए खर्चों को घटाया गया है। इस प्रकार ज्ञात की गई राशि एफ ओ बी मूल्य है। एफ ओ बी मूल्य से 5%/6% को वस्तुओं के विपणन के लिए एस ए बी आई सी के विपणन शुल्क के रूप में घटाया गया है। विपणन शुल्क घटाकर ज्ञात किए गए एफओबी मूल्य को निवल प्राप्ति कहा जाता है जिसे तत्पश्चात् उत्पादक संबद्ध कंपनी को प्रेषित किया गया है।
105. प्रकटन विवरण के उत्तर में यह तर्क दिया गया है कि आई बी एन जाहर के लिए सामान्य मूल्य ज्ञात करने में प्राधिकारी ने उन सभी महीनों के लिए घाटे वाली बिक्रियों की उपेक्षा की है, यहां तक कि ऐसे मामलों, जिनमें किसी महीने की घाटे वाली बिक्रियां उस विशेष महीने की बिक्रियों की 20% से कम रही हैं, उन मामलों में भी ऐसा ही किया गया है और इस प्रकार बिक्रियों को बाहर रखा जाना पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 पैरा 2 (i) के विरुद्ध है। प्रोपीलीन से पोलीप्रोपीलीन की खपत संबंधी मानक और परिवर्तन लागत के स्रोतों का भी खुलासा नहीं किया गया है।
106. यह तर्क भी दिया गया है कि प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की गणना के लिए माल वहन व्ययों के संदर्भ में दोहरी कटौती की है और इसे सही करने का अनुरोध किया गया है। एस ए बी आई सी द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि उचित तुलना के लिए केवल उन्हीं ग्रेडों हेतु पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाए जिनका निर्यात भारत को किया गया है।
107. जहां तक ओ सी टी परीक्षण का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसे जांच अवधि में की गई कुल बिक्रियों के संबंध में किया जाना अपेक्षित होता है। अतः जहां कहीं भी संपूर्ण जांच अवधि के लिए घाटे वाली बिक्रियां कुल बिक्रियों के 20% से अधिक थीं, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभ कमाने वाली बिक्रियों के आधार पर किया गया है। जहां तक खपत संबंधी मानकों और प्रोपीलीन से पोलीप्रोपीलीन की परिवर्तन लागत के स्रोतों का संबंध है, ये अन्य सहयोगी उत्पादकों के उत्तर पर आधारित हैं। प्राधिकारी ने माल वहन व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन की पुनः गणना की है। इस तर्क के संबंध में कि उचित तुलना के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण केवल उन्हीं ग्रेडों हेतु किया जाए जिनका भारत को निर्यात किया गया है, यह नोट किया जाता है कि उत्पादक ने ओ सी टी परीक्षण के लिए लागत निर्धारण संबंधी ग्रेडवार आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं और इसलिए प्राधिकारी प्रदत्त सूचना/आंकड़ों के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए बाध्य है।
108. प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों की तदनुसार जांच की गई है। इनमें इन जांच परिणामों के पैरा 84 में यथावर्णित उत्पादन लागत संबंधी आंकड़ों की पुनः गणना के अधीन स्वीकार किया गया है। निर्यातक द्वारा दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार किया गया है और घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के ऋण आधार पर होने के रूप में ऋण लागत का भी समायोजन किया गया था। तदनुसार ओ सी टी परीक्षण करने के पश्चात् सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। यह पाया गया है कि 20% से अधिक

घरेलू सौदे घाटे पर हुए हैं अतः निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव की वजह से महीना वार आधार पर लाभ कमाने वाली बिक्रियों के अनुसार किया गया है। जब कभी भी किसी विशेष महीने में कोई लाभप्रद बिक्रियां नहीं हुई हैं, वहां उस महीने के लिए सामान्य मूल्य की गणना व संबद्ध वस्तु को बनाने व बेचने की इकाई लागत (इन जांच परिणामों के पैरा 84 में यथावर्णित उत्पादन लागत संबंधी आंकड़ों की पुनः गणना के अधीन) और 5% की दर से लाभ मार्जिन जोड़कर की गई है।

मै. सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट), मै. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पो., सऊदी अरब (एस ए बी आई सी) के जरिए सऊदी अरब

109. एस ए बी आई सी के उत्तर को पढ़ा गया है और यह नोट किया गया है कि एस ए बी आई सी दो संबंधित कंपनियों अर्थात् मै. आई बी एन जाहर और मै. यानपेट द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करती है। आरंभ में प्रतिवादी ने केवल परिशिष्ट 1 और 2, 3 और 3 1 में ब्यौरे उपलब्ध कराए थे और तत्पश्चात् अन्य ब्यौरे अन्य परिशिष्टों अर्थात् परिशिष्ट 4-9 के संबंध में उपलब्ध कराए गए हैं। यह भी देखा गया है कि मै. सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट), केवल मै. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पो. सऊदी अरब (एस ए बी आई सी) के जरिए घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करता है। तथापि, उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु मै. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पो., सऊदी अरब (एस ए बी आई सी) और मै. एक्सान मोबाइल कैमिकल एशिया पैसिफिक, सऊदी अरब द्वारा भारत को निर्यात की गई है।
110. प्रकटन विवरण के उत्तर में यह तर्क दिया गया है कि यानपेट के लिए सामान्य मूल्य ज्ञात करने में प्राधिकारी ने उन सभी महीनों के लिए घाटे वाली बिक्रियों की उपेक्षा की है, यहां तक कि ऐसे मामलों, जिनमें किसी महीने की घाटे वाली बिक्रियां उस विशेष महीने की बिक्रियों की 20% से कम रही हैं, उन मामलों में भी ऐसा ही किया गया है और इस प्रकार बिक्रियों को बाहर रखा जाना पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 पैरा 2 (i) के विरुद्ध है। खपत संबंधी मानक और प्रोपीलीन से पॉलीप्रोपीलीन की परिवर्तन लागत के स्रोतों का भी खुलासा नहीं किया गया है।
111. यह तर्क भी दिया गया है कि प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की गणना के लिए माल वहन व्ययों के संदर्भ में दोहरी कटौती की है और इसे सही करने का अनुरोध किया गया है। एस ए बी आई सी द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि उचित तुलना के लिए केवल उन्हीं ग्रेडों हेतु पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाए जिनका निर्यात भारत को किया गया है।
112. जहां तक ओ सी टी परीक्षण का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसे जांच अवधि में की गई कुल बिक्रियों के संबंध में किया जाना अपेक्षित होता है। अतः जहां कहीं भी संपूर्ण जांच अवधि के लिए घाटे वाली बिक्रियां कुल बिक्रियों के 20% से अधिक थीं, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभ कमाने वाली बिक्रियों के आधार पर किया गया है। जहां तक खपत संबंधी मानकों और प्रोपीलीन से पॉलीप्रोपीलीन की परिवर्तन लागत

के स्रोतों का संबंध है, ये अन्य सहयोगी उत्पादकों के उत्तर पर आधारित है। प्राधिकारी ने माल वहन व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन की पुनः गणना की है। इस तर्क के संबंध में कि उचित तुलना के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण केवल उन्हीं ग्रेडों हेतु किया जाए जिनका भारत को निर्यात किया गया है, यह नोट किया जाता है कि उत्पादक ने ओ सी टी परीक्षण के लिए लागत निर्धारण संबंधी ग्रेडवार आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं और इसलिए प्राधिकारी प्रदत्त सूचना/आंकड़ों के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए बाध्य है।

113. प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों की तदनुसार जांच की गई है। इनमें इन जांच परिणामों के पैरा 84 में यथावर्णित उत्पादन लागत संबंधी आंकड़ों की पुनः गणना के अधीन स्वीकार किया गया है। निर्यातक द्वारा दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार किया गया है और घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के ऋण आधार पर होने के रूप में ऋण लागत का भी समायोजन किया गया था। तदनुसार ओ सी टी परीक्षण करने के पश्चात सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। यह पाया गया है कि 20% से अधिक घरेलू सौदे घाटे पर हुए हैं अतः निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव की वजह से महीना वार आधार पर लाभ कमाने वाली बिक्रियों के अनुसार किया गया है। जब कभी भी किसी विशेष महीने में कोई लाभप्रद बिक्रियां नहीं हुई हैं, वहां उस महीने के लिए सामान्य मूल्य की गणना व संबद्ध वस्तु को बनाने व बेचने की इकाई लागत (इन जांच परिणामों के पैरा 84 में यथावर्णित उत्पादन लागत संबंधी आंकड़ों की पुनः गणना के अधीन) और 5% की दर से लाभ मार्जिन जोड़कर की गई है।

मै. सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट) मै. एक्सन मोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक सऊदी अरब के जरिए सऊदी अरब

114. यह देखा गया है कि मै. सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट) केवल मै. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पो., सऊदी अरब (एस ए बी आई सी) के जरिए घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री करती है। तथापि, उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात मै. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पो., सऊदी अरब (एस ए बी आई सी) और मै. एक्सन मोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक सऊदी अरब द्वारा किया गया है।
115. चूंकि घरेलू बिक्रियां केवल एस ए बी आई सी द्वारा की गई हैं, इसलिए पाटन मार्जिन के प्रयोजनार्थ मै. एक्सन मोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक सऊदी अरब की निर्यात कीमत के साथ तुलना के लिए इसी सामान्य मूल्य को अपनाया गया है।

सहयोगी उत्पादक/निर्यातक

116. सऊदी अरब से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उनके सामान्य मूल्य निर्धारित किए हैं।

सिंगापुर

मै. दि पोलियोलिफिन कं.(सिंगापुर) पी टी ई लि. (टी पी सी)

117. कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना एवं आंकड़ों की जांच और सत्यापन किया गया था। यह नोट किया गया है कि कंपनी ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का सीधे निर्यात नहीं किया है। तथापि कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात निम्नलिखित कंपनियों द्वारा किया गया है :-
1. मै. इतोचू प्लास्टिक्स पी टी ई लि., सिंगापुर
 2. मै. मारुबेनी कैमिकल एशिया पैसिफिक, पी टी ई लि., सिंगापुर
 3. मै. सुमितोमो कार्पो. एशिया पी टी ई लि., सिंगापुर
 4. मै. सुमितोमो कैमिकल एशिया पी टी ई लि., सिंगापुर
 5. मै. टोयेटा सूसो (सिंगापुर) पी टी ई लि., सिंगापुर
 6. मै. इनाबाटा सिंगापुर प्रा. लि.
118. मै. इनाबाटा जिन्होंने काफी देरी से सूचना प्रस्तुत की है, को छोड़कर इन सभी निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली में सूचना दी है। देरी से उत्तर देने के बावजूद निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों की जांच की गई थी। प्रकटन विवरण में यह नोट किया गया था कि मै. इनाबाटा ने वाणिज्यिक मात्रा में संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है और मै. इनाबाटा ने उनके द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तु के विशेष ग्रेडों की कोई घरेलू बिक्रियां नहीं की हैं। यह भी समझा गया था कि मै. इनाबाटा टी पी सी से वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद उनका आगे प्रसंस्करण करता है। टी पी सी ने अपने उत्तर के परिशिष्ट 8 ख में संगत ग्रेडों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं।
119. इनाबाटा द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जांच अवधि के दौरान गैर-वाणिज्यिक मात्रा का निर्यात करना इनाबाटा द्वारा उठाए गए मुद्दों को नजरअंदाज करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क की लेवी (यदि उसे सभी पर लगाया जाता है) न केवल पूर्ववर्ती निर्यात को प्रभावित करेगी बल्कि इनाबाटा के भावी निर्यातों को भी प्रभावित करेगी। अतः यह दर्शाना संगत और महत्वपूर्ण है कि क्या इनाबाटा ने अपने उत्पादों का पाटन किया है और उसके परिणामस्वरूप कोई पाटनरोधी शुल्क अपेक्षित है, इनाबाटा द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को आगे सही साबित करने के लिए उनके आपूर्तिकर्ता टी पी सी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि इनाबाटा ने टी पी सी द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं पर व्यापारिक प्रयोजन के लिए कोई प्रसंस्करण नहीं किया है।
120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि टी पी सी द्वारा परिशिष्ट 2 में प्रदत्त निर्यात व्यौरों के अनुसार ऐसे केवल 3 सौदे हैं जिनका निर्यात इनाबाटा के जरिए किया गया है जबकि इनाबाटा द्वारा प्रदत्त परिशिष्ट-2 में 5 सौदे दर्शाए गए हैं। सितंबर, 2008 और नवंबर, 2008 में इनाबाटा द्वारा बताई गई दो पोषकद्वानों को टी पी सी के आंकड़ों में दर्शाया नहीं गया है, इस प्रकार टी पी सी और इनाबाटा द्वारा भारत को निर्यात के संबंध में दी गई जानकारी एक-दूसरे से मेल नहीं खाती है। उनके द्वारा भारत को निर्यात संबंधी सूचना के बीच

समानता के अभाव में प्राधिकारी इनाबाटा के लिए पृथक निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण भी नहीं कर सकते हैं ।

121. इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि टी पी सी ने सिंगापुर में मै. सुमिटोमो कैमिकल एशिया पी टी ई लि. को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है परंतु मै. सुमिटोमो कैमिकल एशिया पी टी ई लि. ने टी पी सी से इस प्रकार प्राप्त संबद्ध वस्तु की कुछ मात्रा का टी पी सी की पूर्व जानकारी के बिना भारत को निर्यात कर दिया है ।
122. टी पी सी के आंकड़ों के पठन से यह पता चलता है कि इस कंपनी द्वारा लागत निर्धारण संबंधी कोई ग्रेडवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं तथापि, उन्हें महीनावार आधार पर उपलब्ध कराया गया है । इसलिए ओ सी टी परीक्षण करने के लिए कंपनी द्वारा होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स के संबंध में यथाप्रदत्त आंकड़ों को अपनाया गया है । आंकड़ों से यह देखा जाता है कि होमोपॉलीमर्स और को-पॉलीमर्स की घाटे वाली बिक्रियां क्रमशः ***% और ***% रही हैं और समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए घाटे वाली बिक्रियां लगातार ***% रही हैं । अतः सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है ।
123. यह भी नोट किया जाता है कि टी पी सी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि वह मै. सुमिटोमो कैमिकल एशिया पी टी ई लि. को छोड़कर असंबंधित पक्षकारों को बिक्री करती है । अतः मै. सुमिटोमो कैमिकल की बिक्री कीमतों की जांच असंबद्ध पक्षकारों की बिक्री कीमतों के संदर्भ में की गई थी । ऐसी बिक्रियों और असंबंधित पक्षकारों को की गई बिक्रियों के बीच कोई खास अंतर नहीं पाया गया था । अतः टी पी सी द्वारा उसके घरेलू बाजार में की गई सभी लाभप्रद बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है ।
124. मालभाड़ा, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं जैसा कि दावा किया गया था और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था । जैसा कि ऊपर बताया गया है सामान्य मूल्य का निर्धारण जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के कारण महीनावार आधार पर किया गया है ।

मै. एक्सोन मोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक सिंगापुर

125. यह नोट किया जाता है कि यह कंपनी भारत को विचाराधीन उत्पाद का सीधे निर्यात करने के अलावा मै. मित्सुबिसी कैमिकल थाईलैंड (कंपनी) लिमिटेड के जरिए भी संबद्ध वस्तु का निर्यात करती है ।
126. कंपनी द्वारा प्रदत्त आंकड़ों की जांच और सत्यापन किया गया है । यह नोट किया जाता है कि इस कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह बताते हुए परिशिष्ट-1 में घरेलू बिक्रियों संबंधी ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए हैं कि वह भारत को निर्यात बिक्रियों के 5% से कम की बिक्री करती है । अतः उसने दावा किया है कि उसका सामान्य मूल्य तीसरे देश की सूचना के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए । तथापि, यह नोट किया जाता है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण की पद्धति का चयन करने के विकल्प के संबंध में स्वविवेक

उत्पादक/निर्यातक के पास नहीं होता है, यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू बिक्रियों के सौदों के आधार पर नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकारी के पास यह विकल्प होता है कि वह किस प्रकार सामान्य मूल्य निर्धारित करें। अतः परिकलन पद्धति अर्थात् उद्गम के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत और प्रशासनिक बिक्री तथा सामान्य लागतों और लाभ के लिए तर्कसंगत अभिवृद्धि करने के आधार पर निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन करना उचित समझा गया है।

127. यह देखा गया है कि कंपनी ने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर्स के लिए कोई पृथक लागत संबंधी ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए हैं अतः निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन परिशिष्ट 8 ख में प्रदत्त उत्पादन लागत के ब्यौरों में 5% का लाभ जोड़कर किया गया है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के कारण सामान्य मूल्य का निर्धारण महीनावार आधार पर किया गया है।

असहयोगी निर्यातक/उत्पादक

128. सिंगापुर से किसी अन्य निर्यातक और उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उनका सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

निर्यात कीमत:

ओमान

मै. ओमान पॉलीप्रोपीलीन एल एल सी

129. कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों का सत्यापन किया गया था और निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु उन्हें स्वीकार किया गया था। निर्यातक ने कमीशन, सेवा प्रभार और परिवहन के संबंध में समायोजनों का दावा किया है जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। आंकड़ों के माहवार विश्लेषण के आधार पर निर्यात कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई है।
130. ओमान से किसी अन्य निर्यातक और उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उनकी निर्यात कीमत निर्धारित की है।

सऊदी अरब

मै. विनमार इंटरनेशनल लि., यू एस ए के जरिए मै. एडवांस्ड पॉलीप्रोपीलीन कंपनी, सऊदी अरब

131. प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों का सऊदी अरब में सत्यापन किया गया था और निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु उन्हें स्वीकार किया गया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, वित्त प्रभार और विपणन प्रभार के संबंध में समायोजनों का दावा किया है जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। आंकड़ों के माहवार विश्लेषण के आधार पर निर्यात कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई है।

मै. नेशनल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रलाइजेशन मार्केटिंग कंपनी, सऊदी अरब के जरिए मै. सऊदी पोलियोलफिन कंपनी

132. प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों का सत्यापन किया गया था और निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु उन्हें स्वीकार किया गया है। प्रतिवादियों ने अंतरदेशीय भाड़ा, विदेशी भाड़ा, निकासी और प्रहस्तन प्रभार और ऋण लागत के संबंध में समायोजनों का दावा किया है जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। आंकड़ों के माहवार विश्लेषण के आधार पर निर्यात कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई है।

मै. बशेल इंटरनेशनल ट्रेडिंग एफजेंडई के जरिए मै. सऊदी पोलियोलफिनस कं.

133. प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों का सत्यापन किया गया था और निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु उन्हें स्वीकार किया गया है। प्रतिवादियों ने अंतरदेशीय भाड़ा, विदेशी भाड़ा, निकासी और प्रहस्तन प्रभार और ऋण लागत के संबंध में समायोजनों का दावा किया है जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। आंकड़ों के माहवार विश्लेषण के आधार पर निर्यात कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई है।

मै. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पो., सऊदी अरब (एस ए बी आई सी) के जरिए मै. सऊदी यूरोपियन पेट्रोकेमिकल कं. (आई बी एन जाहर)

134. एस ए बी आई सी के उत्तर को पढ़ने से यह पता चलता है कि भूटान और नेपाल को की गई बिक्रियों को भारत के समक्ष दर्शाया गया है क्योंकि ये सभी पोतलदानें हल्दिया/कोलकाता पत्तन के मार्ग से आई थीं। भूटान और नेपाल को निर्यात के संबंध में बिलों की पहुंच से स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित होता है कि ये वस्तुएं अंतिम गंतव्य के रूप में इन देशों के लिए थीं और हल्दिया/कोलकाता पत्तन के जरिए इन देशों को अंतरित की गई थीं। इस प्रकार भूटान और नेपाल को निर्यात के संबंध में सौदों पर निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया गया है।

135. प्रकटन विवरण के उत्तर में एस ए बी आई सी द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि प्राधिकारी ने निर्यात कीमत की गणना के लिए माल वहन व्ययों के संदर्भ में दोहरी कटौती की है और इसे सही करने का अनुरोध किया गया है। एस ए बी आई सी द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि उचित तुलना के लिए केवल उन्हीं ग्रेडों हेतु पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाए जिनका निर्यात भारत को किया गया है।

136. प्राधिकारी ने माल वहन संबंधी व्ययों के संबंध में कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार करते हुए निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की पुनः गणना की है। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि उचित तुलना के लिए केवल उन्हीं ग्रेडों हेतु पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाए जिनका भारत को निर्यात किया गया है, यह नोट किया जाता है कि एस ए बी आई सी के दो उत्पादकों ने व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण करने के लिए ग्रेडवार लागत निर्धारण आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं और इस प्रकार प्राधिकारी प्रदत्त सूचना/आंकड़ों के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए बाध्य है।

137. इस प्रकार प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत यथासत्यापित सूचना/आंकड़ों को निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, बैंक प्रभारों, निकासी व्ययों आदि जैसे खर्च के लिए समायोजनों की अनुमति दी है। यह नोट किया गया था कि यद्यपि, भुगतान ऋण आधार पर किया गया था, परंतु परिशिष्ट 2 में ऋण लागत के लिए कोई कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार जांच अवधि के लिए इस कटौती को करने हेतु सऊदी रियाल और अम.डॉ. में सत्यापन के दौरान यथाप्राप्त अल्पावधिक उधार पर ब्याज की दर का प्रयोग परिशिष्ट-2 में आवश्यक संशोधन करने हेतु किया गया है। आंकड़ों के माहवार विश्लेषण के आधार पर निर्यात कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई है।

मै. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पो सऊदी अरब (एस ए बी आई सी) के जरिए मै. सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कं. (यानपेट) सऊदी अरब

138. एस ए बी आई सी के उत्तर को पढ़ने से यह पता चलता है कि भूटान और नेपाल को की गई बिक्रियों को भारत के समक्ष दर्शाया गया है क्योंकि ये सभी पोतलदानें हल्दिया/कोलकाता पत्तन के मार्ग से आई थीं। भूटान और नेपाल को निर्यात के संबंध में बिलों की पहुंच से स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित होता है कि ये वस्तुएं अंतिम गंतव्य के रूप में इन देशों के लिए थीं और हल्दिया/कोलकाता पत्तन के जरिए इन देशों को अंतरित की गई थीं। इस प्रकार भूटान और नेपाल को निर्यात के संबंध में सौदों पर निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया गया है।

139. प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत यथासत्यापित सूचना/आंकड़ों को निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, बैंक प्रभारों, निकासी व्ययों आदि जैसे खर्च के लिए समायोजनों की अनुमति दी है। यह नोट किया गया था कि यद्यपि, भुगतान ऋण आधार पर किया गया था, परंतु परिशिष्ट 2 में ऋण लागत के लिए कोई कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार जांच अवधि के लिए इस कटौती को करने हेतु सऊदी रियाल और अम.डॉ. में सत्यापन के दौरान यथाप्राप्त अल्पावधिक उधार पर ब्याज की दर का प्रयोग परिशिष्ट-2 में आवश्यक संशोधन करने हेतु किया गया है। आंकड़ों के माहवार विश्लेषण के आधार पर निर्यात कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई है।

मै. एक्सोन मोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक, सऊदी अरब के जरिए मै. सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट) सऊदी अरब

140. प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों को निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया है। आंकड़ों के माहवार विश्लेषण के आधार पर निर्यात कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई है।

असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

141. सऊदी अरब से किसी अन्य निर्यातक और उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उनकी निर्यात कीमत निर्धारित की है।

सिंगापुरमै इटोचू प्लास्टिक पी टी ई लि. के जरिए मै. पोलियोलिफेन कंपनी (सिंगापुर) पी टी ई लि. (टी पी सी)

142. कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों का सत्यापन किया गया था और निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया है। निर्यातक द्वारा परिशिष्ट 2 में किए गए दावे अनुसार कमीशन और ब्याज हेतु समायोजनों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था, की अनुमति दी गई है। टी पी सी से सत्यापित पैकिंग, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, भंडारण, प्रहस्तन, विदेशी भाड़ा, विदेशी बीमा और पोतलदान प्रभार के लिए अन्य समायोजन भी किए गए हैं। आंकड़ों के माहवार विश्लेषण के आधार पर निर्यात कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई है।

मै. मेरुबेनी कैमिकल एशिया पैसिफिक पी टी ई लि, सिंगापुर के जरिए मै. दि पोलियोलिफिन कंपनी, सिंगापुर, पी टी ई लि. (टी पी सी)

143. कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों का सत्यापन किया गया था और निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु उन्हें स्वीकार किया गया है। टी पी सी के उत्तर से सत्यापित पैकिंग, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, भंडारण, प्रहस्तन, विदेशी भाड़ा, विदेशी बीमा और पोतलदान प्रभार के लिए अन्य समायोजन भी किए गए हैं। आंकड़ों के माहवार विश्लेषण के आधार पर निर्यात कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई है।

मै. सुमिटोमो कार्पो. एशिया पी टी ई लि, सिंगापुर के जरिए मै. दि पोलियोलिफिन कंपनी (सिंगापुर) पी टी ई लि. (टी पी सी)

144. टैर पॉलीमर को विश्लेषण से बाहर रखने के संबंध में किए गए अनुरोध को स्वीकार किया गया है। तदनुसार कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों को निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया है। निर्यातक द्वारा परिशिष्ट 2 में किए गए दावे अनुसार कमीशन, ब्याज और बैंक प्रभारों हेतु समायोजनों की अनुमति दी गई है। टी पी सी के उत्तर से सत्यापित पैकिंग, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, भंडारण, प्रहस्तन, विदेशी भाड़ा, विदेशी बीमा और पोतलदान प्रभार के लिए अन्य समायोजन भी किए गए हैं। आंकड़ों के माहवार विश्लेषण के आधार पर निर्यात कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई है।

मै. सुमिटोमो कैमिकल एशिया पी टी ई लि, सिंगापुर के जरिए मै. दि पोलियोलिफिन कंपनी (सिंगापुर) पी टी ई लि. (टी पी सी)

145. निर्यातक द्वारा यह बताया गया है कि गोपनीय प्रकटन विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय होमोपॉलीमर्स को गलती से को-पॉलीमर्स मान लिया गया है और यह कि एफएस 3011ई, एफएस 2011ई, एफवाई 2011ईआर और वाई 101 ई जैसे ग्रेडों को को-

पॉलीमर मान लिया गया है जबकि ये ग्रेड होमोपॉलीमर है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा किए गए दावे को स्वीकार किया है और तदनुसार निर्यात कीमत की पुनः गणना की है।

146. कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों को निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया है। निर्यातक द्वारा अंतरदेशीय भाड़े, भंडारण, अभिलेखीकरण, विदेशी भाड़े और विदेशी बीमा हेतु समायोजनों का दावा किया गया है और उनकी अनुमति दी गई है। आंकड़ों के माहवार विश्लेषण के आधार पर निर्यात कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई है।

मै. टोयोटा सूसो (सिंगापुर) पी टी ई लि. (टी टी एस पी एल) के जरिए मै. पोलियोलफिन कंपनी (सिंगापुर) पी टी ई लि. (टी पी सी)

147. टी टी एस पी एल ने यह तर्क दिया है कि भारत को निर्यात के लिए टी टी एस पी एल की बिक्रियां दीर्घावधिक संविदाओं के तहत की गई थीं जबकि घरेलू सिंगापुर बाजार में टी पी सी की बिक्रियां मौके पर कीमत आधार पर की गई थीं और यह कि जांच अवधि के दौरान अप्रैल से सितंबर, 2008 के लिए कीमतें प्लेट्स कीमत सूची के अनुसार पिछले 6 महीने में प्रचलित कीमतों के आधार पर तय की गई थीं। इसी प्रकार अक्टूबर से मार्च, 2008 की अवधि के लिए वह जुलाई से सितंबर, 2008 में प्रचलित कीमत के आधार पर तय की गई थी। भारत माहवार तुलना करके पाटन और क्षति के कृत्रिम मार्जिन सृजित किए गए हैं। सर्वोत्तम ढंग से तुलना या तो संपूर्ण अवधि के लिए भारत औसत के साथ की जा सकती है जैसा कि प्राधिकारी द्वारा अनेक मामलों में और प्रारंभिक जांच परिणामों में भी किया गया है या फिर अप्रैल-सितंबर, 2008 और अक्टूबर-दिसंबर, 2008 की अवधि के लिए क्रमशः भारत औसतों के आधार पर की जा सकती है। टी टी एस पी एल ने यह अनुरोध किया है कि प्रारंभिक जांच परिणामों में पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया है।
148. प्राधिकारी ने टी टी एस पी एल के इन अनुरोधों को नोट किया है कि भारत को निर्यात के लिए टी टी एस पी एल की बिक्रियां दीर्घावधिक संविदाओं के तहत की गई थीं जबकि घरेलू सिंगापुर बाजार में टी पी सी की बिक्रियां मौके पर कीमतों पर आधारित रही थीं।
149. उपर्युक्त के मद्देनजर जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करते समय दीर्घावधिक संविदाओं के दावों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों को निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया है। टी पी सी के उत्तर से सत्यापित पैकिंग, अंतरदेशीय भाड़े, बीमा, भंडारण, प्रहस्तन, विदेशी भाड़े, विदेशी बीमा और पोतलदान प्रभारों के लिए भी समायोजन किए गए हैं ताकि निवल समायोजित निर्यात कीमत ज्ञात की जा सके।

मै. एक्सोन मोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक, सिंगापुर

150. एमकैप सिंगापुर, द्वारा यह तर्क दिया गया है कि निर्यात कीमत की गणना के लिए सौदों को पोतलदान की तारीख की बजाए ऑर्डर की तारीख के आधार पर समूहबद्ध किया गया है। एमकैप यह मानती है कि उचित तुलना के लिए मासिक निर्यात कीमत का निर्धारण निर्यात

की तारीख या पोतलदान की तारीख के संदर्भ में किया जाना चाहिए और न कि ऑर्डर की तारीख के संदर्भ में ।

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी प्रावधानों के अनुसार सामान्यतः संविदा, खरीद आदेश, आदेश पुष्टिकरण या बीजक की तारीख जिससे भी बिक्री की वास्तविक शर्तें निर्धारित होती हों, बिक्री की तारीख होती है । सत्यापन के दौरान भी बिक्री की वास्तविक शर्तों के निर्धारण के रूप में बीजक की तारीख पर विचार किया गया था । इसके अलावा कंपनी ने इस बात को निर्धारित और सिद्ध नहीं किया है कि पोतलदान की तारीख बिक्री की वास्तविक शर्तों को निर्धारित करती है । इस प्रकार प्राधिकारी का यह मत है कि निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन, की गणना सही ढंग से निर्धारित की गई है ।

152. कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों का सत्यापन किया गया था और निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु उन्हें स्वीकार किया गया था । पैकिंग, कमीशन और विदेशी भाड़े जैसे व्ययों के संबंध में दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दी गई है । आंकड़ों के माहवार विश्लेषण से निर्यात कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई है ।

मै. मित्सुबिशी कैमिकल थाईलैंड (कंपनी) लि. के जरिए मै एक्सोन मोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक, सिंगापुर

153. कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर की जांच की गई है । थाईलैंड में संकट के कारण निर्यातक के उत्तर का पूर्णतः सत्यापन नहीं हो सका था । इसलिए प्रस्तुत की गई सूचना और कुछ हद तक सत्यापित सूचना पर विचार किया गया है । पैकिंग, कमीशन और विदेशी भाड़े जैसे व्ययों के लिए समायोजनों को एक्सोन मोबिल के उत्तर से स्वीकार किया गया है । आंकड़ों के माहवार विश्लेषण से इस प्रकार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है ।

असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

154. सिंगापुर से किसी अन्य निर्यातक और उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है । प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है ।

ज. पाटन मार्जिन

155. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

नाम	देश	पाटन मार्जिन	
		अम.डॉ./मी.ट.	%
म. आमान पालाफन एल एल सा	आमान	***	21.49%
असहयोग उत्पादक तथा निर्यातक	आमान	***	35.90%
म. सुभलमा कापा. एशिया पा टा इ ल. क जारए म. इद पालफन कंपनी (सिंगापुर) प्रा.लि. (टी पी सी)	सिंगापुर	***	14.42%
म. सुभलमा कापा. एशिया पा टा इ ल. क जारए म. इद पालफन कंपनी (सिंगापुर) पी टी ई लि.	सिंगापुर	***	17.33%
म. टायाटा टशुहा (सिंगापुर) पा टा इ ल. क जारए म. इद पालफन कंपनी (सिंगापुर) पी टी ई लि.	सिंगापुर	***	22.18%
म. मरुबना कामकल एशिया कामकल एशिया पाराफक पाटाइ ल. क जारए म. दि पोलिफन कंपनी (सिंगापुर) पी टी ई लि.	सिंगापुर	***	9.93%
म. इटायू फ्लोस्टक्स पा टा इ ल. क जारए म. इद पालफन कंपनी (सिंगापुर) पी टी ई लि.	सिंगापुर	***	24.55%
म. एक्सान माबलू कामकल एशिया पाराफक, सिंगापुर	सिंगापुर	***	13.39%
म. मत्सुबसा कामकल थाइलंड (क.) लि. क जारए म. एक्सान माबलू केमिकल एशिया पैसिफिक, सिंगापुर	सिंगापुर	***	9.00%
असहयोग उत्पादक तथा निर्यातक	सिंगापुर	***	43.05%
म. वनमार इंटरनशनल लि., यू एस ए क जारए म. एडवारड पोलिप्रोपीलीन क. सऊदी अरब	सऊदी अरब	***	20.92%
म. सऊदी वासक इंडस्ट्राल कापारशन, सऊदी अरब (साबक) क जारए म. सऊदी यूरोपियन पेट्रोकेमिकल कंपनी (आई वी एन जाहर), सऊदी अरब	सऊदी अरब	***	20.45%
म. सऊदी वासक इंडस्ट्राल कापारशन, सऊदी अरब (साबक) क जारए म. सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट)	सऊदी अरब	***	5.37%

म. एक्सान माबल कामकल, एशया पासाफक, सऊदा अरब क जारए मै. मै. सऊदी यानवू पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट)	सऊदा अरब	***	16.30%
म. नशनल पेट्रोकामकल इंडास्ट्रलाइजेशन माकाटम कंपनी, सऊदा अरब के जारिए मै. सऊदी पोलिकेनस कंपनी	सऊदा अरब	***	7.01%
बसल इटरनशनल ट्राउंग एक जड इ. दुबई क जारए, म. सऊदा पोलिफिन्स कंपनी	सऊदा अरब	***	4.00%
असहयागा उत्पादक तथा निर्यातक	सऊदा अरब	***	39.42%

झ. क्षति

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

156. निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को उनके संगत पाए जाने की सीमा तक नीचे संक्षेप में दिया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि :

- (i) भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में 2005-06 में 91.34% से जांच अवधि के दौरान 92.16% तक की वृद्धि हुई है। इस प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि संबद्ध देशों से हुए आयातों में मांग में हुई संपूर्ण वृद्धि पर कब्जा कर लिया है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आयातों में वृद्धि के कारण हुई है।
- (ii) घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से काफी अधिक पाटित आयातों के कारण क्षति जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। इस संबंध में यह नोट किया जाना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. ने बी एस ई इंडिया को यह सूचित किया है उसने अपने कुछ पालिस्टर संयंत्रों को नवंबर, 2008 महीने के दौरान नेमी स्वरूप के रखरखाव और उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए बंद कर दिया है और मरम्मत का कार्य लगभग 4 हफ्तों तक चलेगा। इसके कारण क्षमता उपयोग में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- (iii) घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि उसे आयातों में वृद्धि के कारण अप्रैल-जून, 2008 की तुलना में अक्टूबर-दिसंबर, 2008 के दौरान घाटा उठाना पड़ा है। इस संबंध में यह नोट किया जाना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह सूचित किया है कि उसके पाताल गंगा संयंत्र ने लागत ईष्टतम बनाने की अपनी सामान्य प्रक्रिया के एक भाग के रूप में 5 अक्टूबर, 2008 को एक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना घोषित की थी और 400 से अधिक लोगों ने इसके विकल्प को चुना।
- (iv) जांच अवधि के दौरान बिक्री मूल्य और मात्रा में कोई गिरावट नहीं आई है क्योंकि बिक्री मात्रा में 2005-06 में 100 सूचीबद्ध इकाइयों से 2008-09 में 131 सूचीबद्ध वार्षिकीकृत इकाइयों की वृद्धि हुई है। बिक्री मात्रा और बिक्री मूल्य में हुई

- वृद्धि के विश्लेषण से यह पता चलता है कि प्रति मी.ट. बिक्री प्राप्ति में भी वृद्धि हुई है क्योंकि बिक्री मूल्य में हुई वृद्धि बिक्री मात्रा में हुई वृद्धि से अधिक है ।
- (v) आवेदक ने स्वीकार किया है कि क्षति जांच अवधि के दौरान कर्मचारियों की सं. और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी पर कोई ऋणात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है । इस प्रकार इस कारक पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।
- (vi) माननीय प्राधिकारी ने स्वयं प्रारंभिक जांच परिणाम में यह निष्कर्ष निकाला था कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है और इसके बावजूद आयातों के बाजार हिस्से में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में गिरावट अर्थात् 6.4% से 5.8% आई है । इसके अलावा, माननीय प्राधिकारी ने जांच परिणाम में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा नकद प्रवाह, रोजगार और मजदूरी, उत्पादकता में सुधार हुआ है ।
- (vii) घरेलू उद्योग को क्षति यदि कोई हो, वह स्वआरोपित है और वह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात के कारण नहीं हुई है । यह नोट करना संगत है कि जांच अवधि (9 महीने) के दौरान एक महीने के लिए घरेलू उद्योग में योजनागत बंदी को अपनाया है । यह बंदी कुल मांग और कुल घरेलू उत्पादन के बीच अंतर को पाटने के लिए क्षमता में वृद्धि के लिए की गई थी । योजनागत बंदी के कारण घरेलू उद्योग को व्यापार में हुए किसी नुकसान के लिए केवल घरेलू उद्योग के कार्य उत्तरदायी हैं और कथित पाटित वस्तुओं के आयातों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ।
- (viii) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, अस्थायी प्रकृति के हैं, जो आयात के विरुद्ध निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने को न्यायोचित नहीं ठहराती है । जांच अवधि के दौरान वैश्विक मंदी के कारण और कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता के कारण संबद्ध वस्तु के उत्पादक और विक्रेता विश्व भर में प्रतिकूलतः प्रभावित हुए थे ।
- (ix) संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए संबद्ध वस्तु के आयात अनिवार्य हैं । यह अनुरोध किया जाता है कि 100% क्षमता उपयोग के स्तर पर भी घरेलू उद्योग बाजार में कुल मांग को पूरा नहीं कर सकता है । अतः पाटनरोधी शुल्क लागू करना घरेलू उपभोक्ताओं के हित में नहीं है ।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

157. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार बताया है :

- (i) जहां तक बाजार हिस्से के मुद्दे का संबंध है, हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग ने निर्धारित प्रपत्र में बिल्कुल सही ढंग से आवेदन प्रस्तुत किया है और क्षति के संबंध में किए गए अनुरोध भी क्षति विश्लेषण से संबंधित विधिक प्रावधानों के अनुक्रम में है । घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उसके बाजार हिस्से में गिरावट आई है । उनका यह दावा है कि इस हिस्से में गिरावट अन्य उत्पादक की बिक्री पर विचार करने के बाद आई है । अतः गलत और गुमराह करने वाले दावे प्रस्तुत करने का आरोप निधाराधार है । इसके अलावा किसी भी मामले में बाजार हिस्से की

गतिविधियाँ (अर्थात् समग्र घरेलू उत्पादकों को शामिल करने के बाद या उससे पहले) सार्वजनिक रूप से घरेलू उद्योग के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कुछ खास नहीं है।

- (ii) हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आर आई एल की योजनाबद्ध बंदी के कारण आई है, यह अनुरोध किया गया है कि :

(क) यह बंदी केवल जामनगर परिसर में की गई थी जबकि आर आई एल के पास 5 उत्पादन सुविधाएँ हैं।

(ख) विचाराधीन उत्पाद की माहवार मालसूची की स्थिति यह दर्शाती है कि माल सूचियों में अप्रैल, 2008 में *** मी.ट. से सितंबर, 2008 के अंत में *** मी.ट. की वृद्धि हुई है, जिसमें अक्टूबर, 2008 के अंत में *** मी.ट. की आगे और वृद्धि हुई है। इस प्रकार अप्रैल से अक्टूबर, 2008 में अंतिम स्टॉक में हुई वृद्धि दोगुने से अधिक रही थी।

(ग) मालसूचियों में वृद्धि से उन वस्तुओं के भंडारण की गंभीर व्यावहारिक समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि पाटित कीमतों पर बढ़े हुए आयातों के कारण वस्तुओं के भंडारण के लिए वास्तविक स्थान की कमी पड़ गई थी। इस संदर्भ में ही योजनागत बंदी की गई थी क्योंकि आर आई एल पाटित कीमतों पर आयातों में अचानक वृद्धि के कारण घरेलू बाजार में उत्पाद की बिक्री करने में सक्षम नहीं था।

(घ) हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि यह घाटा "योजनाबद्ध" बंदी के कारण हुआ था। यह अनुरोध किया जाता है कि रखरखाव की बंदी के लिए दिनों की संख्या एक दिन से कम है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है शेष अवधि के लिए की गई बंदी जामनगर परिसर में मालसूचियों के अत्यधिक और विशाल जमावाड़े के कारण हुई थी। अपने इस तर्क के समर्थन में कि योजनाबद्ध रखरखाव के लिए बंदी के दिनों की संख्या जरूरी थी, रखरखाव संबंधी योजनागत बंदी के ब्यौरे पिछले वर्षों के दौरान देखे जाने चाहिए।

(ङ) इन वर्षों के दौरान विशिष्ट रखरखाव बंदी पूरे वर्ष भर में 7 दिनों से कम रही है जिसे सरलता से प्राधिकारी द्वारा उनके संयंत्रों में रखे जाने वाले दैनिक रिकॉर्डों के ब्यौरों से देखा जा सकता है अतः यह तर्क कि उत्पादन और क्षमता उपयोग में योजनागत बंदी के कारण कमी आई थी, पूर्णतः निराधार है। रिकॉर्डों से यह स्पष्ट है कि यह बंदी बढ़ती हुई मालसूची और पाटित आयातों के कारण की गई थी।

- (iii) जहाँ तक पाताल गंगा में सवैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का संबंध है, यह अनुरोध किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों का तर्क निराधार है क्योंकि पाताल गंगा परिसर में पॉलीप्रोपीलीन का कोई उत्पादन नहीं किया जाता है और सवैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंध लागतें यद्यपि काफी कम हैं, परंतु वह संबंध वस्तु अर्थात् पॉलीप्रोपीलीन के उत्पादन से भी संबंध नहीं हैं।
- (iv) बिक्री मात्रा और बिक्री मूल्य कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग का यह दावा कि कीमतों में लागतों में हुई वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है, के संबंध में घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने कुछ स्वयंसिद्ध निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए सूचीबद्ध संख्याओं का विश्लेषण किया है। घरेलू उद्योग द्वारा उनके आवेदन में दी गई वास्तविक संख्याओं से घरेलू उद्योग का मुद्दा स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि लागतों में हुई वृद्धि जांच अवधि के दौरान कीमतों में वृद्धि को कवर नहीं कर रही है।
- (v) मालसूचियों के संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि उन्होंने निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रारूप IV क में मूलभूत सूचना उपलब्ध कराई है जिसमें भंडार के संबंध में बिन्दुवार सूचना देना अपेक्षित है। भाग 4 में दी गई सूचना के साथ घरेलू उद्योग के मासिक भंडार की स्थिति स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में सितंबर और अक्टूबर के महीनों के दौरान अभूतपूर्व स्तर तक वृद्धि हुई थी और तत्पश्चात् जब घरेलू उद्योग के पास अपने भंडारों को घाटे में बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तब भंडार सतर में कमी आई। यह तथ्य घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है जिसमें यह दर्शाया गया है कि घरेलू उद्योग को अप्रैल-सितंबर, 2008 की अवधि की तुलना में अक्टूबर-दिसंबर, 2008 के दौरान घाटा उठाना पड़ा था।
- (vi) पृष्ठ 14 पर तालिका में दी गई लाभप्रदता संबंधी सूचना प्रारूप IV क के अनुपालन में है।

प्रकटन विवरण के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

158. यह तर्क दिया गया है कि नियोजित पूंजी पर आय की 22% की सीमा को अपनाया जाना अतर्कसंगत और बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है और इससे घरेलू उद्योग अनुचित रूप से यदि पाटन नहीं भी होता है तो भी एक बेहतर स्थिति में आ जाएगी। यह भी अनुरोध किया गया है कि नियोजित पूंजी पर आय की सीमा औद्योगिक मानकों और/या जांच अवधि के दौरान प्रचलित आर्थिक परिस्थितियों पर विचार करते हुए नियोजित पूंजी पर आय के ऐतिहासिक स्तरों के आधार पर तय की जानी चाहिए।

159. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि प्राधिकारी ने स्वयं यह निष्कर्ष निकाला है कि जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि (32%) हुई है और मांग में उक्त वृद्धि के बावजूद आयातों का बाजार हिस्सा लगभग समान रहा है और अधिकांश बाजार हिस्सा घरेलू उद्योग द्वारा नियंत्रित है (73%) अन्य घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में भी भारी वृद्धि अर्थात् 89% से 92% हुई है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू उद्योग को

क्षति, यदि कोई हो संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण नहीं हुई है बल्कि वह घरेलू उत्पादकों के बीच बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है। इसके अलावा घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा (20% तक की वृद्धि), रोगगार और मजदूरी (8% तक की वृद्धि), प्रति कर्मचारी उत्पादकता (27% तक की वृद्धि), माल सूची (27% तक की गिरावट), में जांच अवधि के दौरान सुधार हुआ है। इन सभी से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है जैसा कि आरोप लगाया गया है।

160. घरेलू उद्योग को हुई क्षति यदि कोई हो, तो वह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कथित पाटित आयातों के कारण नहीं हुई है बल्कि वह स्वआरोपित है। कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। यह नोट करना संगत है कि जांच अवधि (9 महीने) के दौरान एक महीने के लिए घरेलू उद्योग ने योजनाबद्ध बंदी की थी। यह बंदी कुल मांग और कुल घरेलू उत्पादन के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए क्षमता में वृद्धि हेतु की गई थी। योजनाबद्ध बंदी के कारण घरेलू उद्योग को व्यापार में घाटा हुआ है और यह केवल घरेलू उद्योग के क्रियाकलापों के कारण हुआ है और इसके लिए कथित पाटित वस्तुओं के आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

161. जांच अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमतों में वैश्विक मंदी की अस्थिरता के कारण; संबद्ध वस्तु के उत्पादक और विपणनकर्ता विश्वभर में प्रतिकूलतः प्रभावित हुए थे। कच्ची सामग्री की कीमतें 2008 में 147 अम.डॉ./बैरल से 40 अम.डॉ./बैरल रही हैं। कच्ची सामग्री की वयुत्पत्ति प्रोपीलीन उत्पादन लागत का 3 चौथाई से अधिक हिस्सा होता है। इस प्रकार विनिर्माताओं को सबसे पहले उच्चतर मूल्य वाली कच्ची सामग्री का निपटान करना था। कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट के बावजूद उत्पादन लागत अधिक रही थी। इसके अलावा, बाजार से प्राप्त होने वाली कीमत भी कुछ समय के लिए घट गई थी। तथापि, इसमें कच्ची सामग्री की कीमतों में स्थिरता आने पर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। संबद्ध वस्तु की बिक्रियों और कीमत पर उक्त प्रतिकूल प्रभाव केवल घरेलू उद्योग तक सीमित नहीं रहा था। इससे स्पष्टतः यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति यदि कोई हो अस्थायी प्रकृति की है और उससे संबद्ध वस्तु के आयातों पर 5 वर्ष की अवधि के निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का औचित्य नहीं बनता है। इससे भारत में संबद्ध वस्तु के अन्य घरेलू उत्पादकों और विपणनकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। घरेलू उद्योग ने जानबूझकर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि को चुना ताकि वह प्राधिकारी को गुमराह कर सके।

162. संबद्ध वस्तु का आयात किया जाना संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने की दृष्टि से अनिवार्य है। यह अनुरोध किया जाता है कि 100% क्षमता उपयोग के स्तर पर भी घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के लिए बाजार में कुल मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। कुल घरेलू को पूरा करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता इस तथ्य से और गंभीर हो जाती है कि घरेलू उद्योग एक महत्वपूर्ण घटक मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., जो जांच अवधि के दौरान ई ओ यू रहे हैं, ने भारी मात्रा के निर्यात का अधिदेश दिया है और वह वास्तव में संबद्ध वस्तु की भारी मात्रा का निर्यात कर रहे हैं।

163. क्षति संबंधी मापदंडों के निर्धारण में एक छोर से दूसरे छोर की तुलना न केवल अतर्कसंगत है बल्कि डब्ल्यू टी ओ कानून से भी असंगत है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

164. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों को नोट किया है और निम्नानुसार क्षति संबंधी विश्लेषण किया है ।

165. नियोजित पूंजी पर 22% की सीमा को अपनाए जाने के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातित पूंजी पर 22% की आय (निवल स्थिर परिसंपत्तियों को देखते हुए) सही है और उसका संगत रूप से प्राधिकारी द्वारा पालन किया जा रहा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर 35% से अधिक की आय अर्जित की थी, तथापि, प्राधिकारी ने इसे उचित स्तर पर रखने के लिए नियोजित पूंजी पर आय को 22% तक सीमित रखा है ।

166. कच्ची सामग्री की कीमतों और संबद्ध वस्तु की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव को देखते हुए प्राधिकारी ने महीनावार विश्लेषण किया है ।

167. प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य आयातों को पूर्णतः रोकना नहीं है बल्कि उचित व्यापार की स्थिति बहाल करना है । इसके अलावा, प्राधिकारी को देश में संबद्ध वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की अक्षमता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं में कोई तर्काधार दिखाई नहीं देता है क्योंकि यह कानून के अंतर्गत अधिदेशित नहीं है । इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यात का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि वर्तमान जांच में क्षति संबंधी विश्लेषण घरेलू प्रचालनों तक सीमित है ।

168. इन जांच परिणामों के सावधानीपूर्वक पठन से यह प्रदर्शित होगा कि यह विश्लेषण क्षति जांच अवधि के लिए किया गया है और प्राधिकारी ने हाल के वर्षों की तुलना में जांच अवधि में हुए परिवर्तनों की भी जांच की है ।

संचयी आकलन

169. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II पैरा (iii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के आयात एक साथ पाटनरोधी जांच के अधीन हों तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आंकलन करेंगे यदि यह निर्धारित होता हो कि: -

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में निर्धारित पाटन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में 2% से अधिक हो और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान

वस्तु के आयात का 3% हो या जहां अलग-अलग देशों से निर्यात 3% से कम हो वहां आयात संचयी रूप से समान वस्तु के आयात के 7% से अधिक हो तथा

ख. आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उचित हो ।

170 प्राधिकारी यह समुक्ति करते हैं कि :

- i. संबद्ध देशों में से प्रत्येक का पाटन मार्जिन ऊपर निर्धारित सीमाओं से अधिक है ;
- ii. संबद्ध देशों में से प्रत्येक से आयातों की मात्रा निर्धारित सीमाओं से अधिक है;
- iii. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से होने वाले निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जा रही समान वस्तु से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं । यह बात इस तथ्य से साबित होती है कि घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद समान वस्तु हैं; संबद्ध देशों में से प्रत्येक से आयात न्यूनतम सीमा से अधिक हैं; भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करती हैं; साझे पक्षकार आयातित सामग्री और घरेलू सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं; भारतीय उत्पादकों के उपभोक्ता घरेलू सामग्री और आयातित सामग्री का उपयोग कर रहे हैं; संबद्ध देशों से निर्यातक और आवेदक ने समान अवधियों में उपभोक्ताओं के समान समूहों को समान उत्पाद की बिक्रियां की हैं आदि ।

171. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी आकलन करना उपयुक्त होगा ।

172. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच करने का प्रावधान है । (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव । पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव की जांच करते समय प्राधिकारी द्वारा इस बात की जांच किया जाना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है । पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी द्वारा इस बात की जांच किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की जा रही है या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में भारी कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गई होती ।

173 जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नानुसार वर्णन है :-

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमत, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

174. सभी संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयातों से संबंधित ब्यौरे निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए हैं:

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देशों से आयात (मी.ट.)	61493	70164	110227	103677
आयात (अन्य देश) मी.ट.	40242	42718	66966	35033
कुल आयात (मी.ट.)	101735	112882	177193	138711
संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा %	60%	62%	62%	75%
संबद्ध देशों से आयातों में प्रवृत्ति	100	114	179	169
वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन (%)		14	57	-6
अन्य देशों से आयातों में प्रवृत्ति	100	106	166	87
वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन (%)		6	57	-48
कुल आयातों में प्रवृत्ति	100	111	174	136
वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन (%)		11	57	(22)
कुल मांग (मी.ट.)	1327308	1525077	1745061	1766985
मांग में संबद्ध देशों का % हिस्सा	5%	5%	6%	6%

175. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से हुए आयातों में समग्र रूप से क्षति अवधि के दौरान 100 (2005-06) से जांच अवधि में 169 की वृद्धि हुई है। इसी के साथ अन्य देशों से होने वाले आयात आधार वर्ष में 100 से घटकर जांच अवधि में 87 रह गए हैं। भारत में कुल मांग की दृष्टि से आयातों में क्षति अवधि के दौरान भी वृद्धि हुई विशेष रूप से जांच अवधि के दौरान इनमें आधार वर्ष में 5% से जांच अवधि में 6% की वृद्धि हुई है।

मांग और बाजार हिस्सा

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग की बिक्री (मी.ट.)	983572	1163196	1310868	1285607
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	242000	249000	257000	342667
भारत में कुल घरेलू बिक्री (मी.ट.)	1225572	1412196	1567868	1628274
संबद्ध देशों से आयात (मी.ट.)	61493	70164	110227	103677
अन्य देशों से आयात (मी.ट.)	40242	42718	66966	35033
कुल आयात (मी.ट.)	101735	112882	177193	138711
कुल मांग (मी.ट.)	1327308	1525077	1745061	1766985
मांग में कुल घरेलू बिक्री का बाजार हिस्सा	74%	76%	75%	73%
मांग में कुल घरेलू बिक्री का बाजार हिस्सा	92%	93%	90%	92%
मांग में संबद्ध देशों का % हिस्सा	5%	5%	6%	6%

176. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में समान वस्तु के केवल दो ज्ञात उत्पादक हैं जिनमें से एक आवेदक (घरेलू उद्योग) है। घरेलू उद्योग की बिक्रियों की प्रवृत्तियां 2007-08 तक वृद्धिकारी रही थीं परंतु जांच अवधि के दौरान इनमें गिरावट आई। तथापि, विचाराधीन उरत्पाद की मांग में आधार वर्ष की तुलना में लगभग 33% तक की वृद्धि हुई थी। संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा 5% से धीरे-धीरे बढ़कर 6% हो गया है।

क्षमता, उत्पादन एवं क्षमता उपयोग

177. क्षति अवधि के दौरान क्षमता एवं उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
क्षमता (मी.ट.)	1400000	1700000	1700000	1725000
उत्पादन (मी.ट.)	1285511	1639199	1710002	1517688
क्षमता उपयोग %	92%	96%	101%	88%

178. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वर्ष 2007-08 तक वृद्धि होती रही, जब वह अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर रहा था, परंतु जांच अवधि के दौरान इसमें भारी गिरावट आई और यह 101% (2006-07) से घटकर 88% रह गई। संक्षेप में, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में आधार वर्ष (2005-06) तथा इसके पूर्ववर्ती वर्ष दोनों की तुलना में गिरावट आई जो मुख्यतः जामनगर स्थित संयंत्र बंद हो जाने के कारण आई।

179. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संयंत्र बंद होने का प्रमुख कारण सितंबर तथा अक्टूबर, 2008 माह में मालसूची के स्तर में अत्यधिक वृद्धि होना था और उसके बाद स्टॉक के स्तर में गिरावट आई क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा स्टॉक का निपटान घाटा उठाकर किया गया।

iv. बिक्री

180. जैसा कि पहले नोट किया गया है, देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ती रही और घरेलू उद्योग मांग में बढ़ोत्तरी के अनुरूप अपनी बिक्री की मात्रा बढ़ाने में सक्षम रहा। दरअसल घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में 2006-07 में 20% की वृद्धि कर ली थी।

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
बिक्री की कुल मात्रा (मी.ट.)- घरेलू	983572	1163196	1310868	1285607
बिक्री मूल्य (लाख रुपए) - घरेलू	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	135	155	166

घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	जांच अवधि
पहुंच मूल्य रु./मी.ट.	51163	58897	59565	67940
सूचीबद्ध	100	115	116	133
घरेलू बिक्री कीमत रु./मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	114	117	127
लागत रु./मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	109	112	151

181. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों का पहुंच मूल्य 100 (आधार वर्ष 2005-06) से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 131 हो गया था। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी इसी प्रकार बढ़ोत्तरी का रुख देखा गया। संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमतों से सदैव अधिक रहे, अतः आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कीमत कटौती नहीं हुई। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान कीमत में प्रतिकूल कटौती देखी गई है। इस संदर्भ में घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि भारित औसत बिक्री मूल्य के साथ भारित औसत पहुंच मूल्य की तुलना से इस दृष्टि से सही स्थिति सामने नहीं आती कि भारत में इस कीमत पर आने वाले माल के आधार पर घरेलू कीमतें लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित देशों से निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा बुक किए गए आदेशों तथा इन सामानों के भारत में

पहुँचने के समय में अंतर है। यह मानते हुए कि जांच अवधि के दौरान संबंधित सामानों की कीमतों में पर्याप्त उतार चढ़ाव आया है, भारत औसत आधार पर कोई तुलना करने से भ्रामक स्थिति सामने आने की संभावना है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने बिक्री कीमतों में वृद्धि लागतों में वृद्धि के अनुसार नहीं हो सकती। तथापि, बिक्री कीमतों में तदनुरूपी वृद्धि की तुलना में लागतों में वृद्धि की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को कीमत संबंधी दबाव झेलना पड़ा है।

कीमत कटौती

182. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक संबद्ध देश के कारण नकारात्मक कीमत कटौती हुई है। प्रत्येक संबंधित देश के लिए कम कीमत पर बिक्री माहवार ली गई है। कम कीमत पर बिक्री से संबंधित ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

देश	माह	मी.ट.	एनआईपी -रु. / मी.ट.	पहुँच मूल्य (रु. /मी.ट.)	कम कीमत पर बिक्री-रु. / मी.ट.	कम कीमत पर बिक्री - (%)
संबद्ध देश	अप्रैल-08	***	***	***	***	-1% - 4%
	मई-08	***	***	***	***	3% - 8%
	जून-08	***	***	***	***	9% - 13%
	जुलाई-08	***	***	***	***	14% - 18%
	अगस्त-08	***	***	***	***	7% - 11%
	सितं.-08	***	***	***	***	0% - 5%
	अक्टू.-08	***	***	***	***	1% - 6%
	नवं.-08	***	***	***	***	-23% - -18%
	दिसं.-08	***	***	***	***	-8% - -2%
संबद्ध देश- कुल		***	***	***	***	8% - 13%
ओमान	अप्रैल-08	***	***	***	***	-4% - 1%
	मई-08	***	***	***	***	1% - 6%
	जून-08	***	***	***	***	30% - 35%
	जुलाई-08	***	***	***	***	10% - 15%
	अगस्त-08	***	***	***	***	3% - 8%
	सितं.-08	***	***	***	***	-6% - -1%
	अक्टू.-08	***	***	***	***	-14% - 9%
	नवं.-08	***	***	***	***	100% - 105%
	दिसं.-08	***	***	***	***	3% - 5%
ओमान कुल		***	***	***	***	9% - 14%
सऊदी अरब	अप्रैल-08	***	***	***	***	-1% - 4%
	मई-08	***	***	***	***	3% - 8%
	जून-08	***	***	***	***	9% - 14%
	जुलाई-08	***	***	***	***	14% - 19%
	अगस्त-08	***	***	***	***	8% - 13%
	सितं.-08	***	***	***	***	1% - 6%

	अक्टू.-08	***	***	***	***	-7% - 1%
	नव.-08	***	***	***	***	-21% - -15%
	दिसं.-08	***	***	***	***	-6% - -1%
सऊदी अरब कुल		***	***	***	***	10% - 15%
सिंगापर	अप्रैल-08	***	***	***	***	-3% - 2%
	मई-08	***	***	***	***	1% - 6%
	जून-08	***	***	***	***	7% - 12%
	जुलाई-08	***	***	***	***	12% - 17%
	अगस्त-08	***	***	***	***	4% - 9%
	सितं.-08	***	***	***	***	-3% - 2%
	अक्टू.-08	***	***	***	***	3% - 8%
	नव.-08	***	***	***	***	-30% - -24%
	दिसं.-08	***	***	***	***	-19% - -12%
सिंगापुर कुल		***	***	***	***	5% - 10%

लाभप्रदता

183. लाभप्रदता से संबंधित ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	जांच अवधि वार्षिकीकृत
कुल बिक्री (मी.ट.)	983572	1163196	1310868	1285607
सूचीबद्ध	100	118	133	131
बिक्री मूल्य (लाख रुपए)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	135	155	166
बिक्री कीमत/इकाई	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	114	117	127
लागत(लाख रुपए)	***	***	***	***
लागत/इकाई	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	109	112	151
लाभ (लाख रुपए)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	167	188	5
लाभ/मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	142	141	4
लाभ/हालि (%)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	124	121	3

184. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जांच अवधि के दौरान, जहां 2005-06 की अवधि में 100 की तुलना में बिक्री की लागत 151 (सूचीबद्ध) थी, परंतु बिक्री कीमतों में तदनुरूप अवधि में हुई वृद्धि केवल 100 से 127 थी। संक्षेप में, घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान लागत में वृद्धि के अनुरूप कीमतों में वृद्धि

नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता में तेजी से गिरावट आई। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में आई गिरावट पूर्ववर्ती वर्ष की गिरावट की तुलना में अत्यधिक प्रवृत्ति के विश्लेषण से जांच अवधि के दौरान उल्लेखनीय कीमत हास होने का पता चलता है।

लगाई गई पूंजी से आय

185. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूंजी से आय में भी क्षति अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है।

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	जांच अवधि वार्षिकीकृत
नियोजित पूंजी	***	***	***	***
ब्याज पूर्व लाभ	***	***	***	***
आरओसीई (%)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	151	170	7

नकद प्रवाह

186. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की नकद प्रवाह की स्थिति में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई और इसकी प्रवृत्ति भी लाभप्रदता और लगाई गई पूंजी से आय (आरओसीई) के समान देखी गई।

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	जांच अवधि वार्षिकीकृत
लाभ/हानि (लाख रुपए)	***	***	***	***
जोड़ें: मूल्यहास (लाख रुपए)	***	***	***	***
नकद प्रवाह (लाख रुपए में)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	156	170	27
नकद प्रवाह/इकाई	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	132	128	21

रोजगार एवं मजदूरी

187. यह नोट किया गया है कि कर्मचारियों की संख्या आंशिक रूप में कम हुई है। तथापि, क्षति जांच अवधि में उन्हें दी गई मजदूरी में वृद्धि हुई है।

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	जांच अवधि वार्षिकीकृत
कर्मचारियों की संख्या	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	97	97	93
मजदूरी कुल (लाख रु.)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	108	105	108

उत्पादकता

188. क्षति की जांच अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी वृद्धि हुई। यह नोट किया जाता है कि उत्पादकता घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

	2005 - 52006	2006 - 2007	2007 - 2008	जांच अवधि वार्षिकीकृत
उत्पादन (मी.ट.)	1285511	1639199	1710002	1517688
कर्मचारी	***	***	***	***
प्रति कर्मचारी उत्पादन (मी.ट.)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	131	137	127

वृद्धि

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि				
क्षमता उपयोग	100	105	110	96
बाजार हिस्सा	100	103	101	98
लाभप्रदता	100	167	188	5
नकद लाभ	100	156	170	27
नियोजित पूंजी पर आय	100	151	170	7

189. यह नोट किया जाता है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान देश में मांग में वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा मांग में वृद्धि को देखते हुए नहीं बढ़ा है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में स्थिर रहा है और उससे ठीक पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक रूप से कम हुआ है। क्षति जांच अवधि में क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, आर ओ सी ई और नकद प्रवाह में भी कमी आई है। इससे स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग का विकास प्रभावित हुआ है।

मालसूची

190. आवेदन में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि औसत मालसूची 100 (आधार वर्ष 2005-06) से घटकर 73 रह गई जो कुल खरीद में वृद्धि दर्शाती है।

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	जांच अवधि
प्रारम्भिक स्टॉक (मी.ट.)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	136	153	132
अंतिम स्टॉक (मी.ट.)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	112	97	29
औसत स्टॉक (मी.ट.)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	122	121	73

191. घरेलू उद्योग ने तत्पश्चात् स्टॉक की माहवार स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत किया था जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सितंबर और अक्टूबर, 2008 माह के दौरान मालसूची में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी और उसके बाद स्टॉक के स्तर में कमी आई क्योंकि घरेलू उद्योग ने घाटा उठाकर स्टॉक का निपटान किया ।

माह	अंतिम स्टॉक	सूचीबद्ध
अप्रैल 2008	***	100
मई 2008	***	83
जून 2008	***	61
जुलाई 2008	***	100
अगस्त 2008	***	142
सितंबर 2008	***	158
अक्टूबर 2008	***	204
नवंबर 2008	***	71
दिसंबर 2008	***	29

पूंजी/निवेश जुटाने की क्षमता

192. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है । पिछली बार क्षमता में वृद्धि वर्ष 2006-07 में की गई थी । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चूंकि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग बढ़ रही है और यह घरेलू उद्योग की क्षमता से अधिक है अतः आयात अवश्यभावी है, जब घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का निर्यात भी कर रहा है । परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि ऐसे आयात पाटित कीमतों पर किए जाने चाहिए ।

193. ऐसे परिदृश्य में जब मांग घरेलू उद्योग की क्षमता से अधिक है, घरेलू उद्योग क्षमता वर्धन हेतु उत्सुक होगा । तथापि लाभप्रदता से संबंधित मानदंड इस बात का समर्थन नहीं करते कि घरेलू उद्योग निवेश हेतु बाजार से पूंजी जुटाने में समर्थ होगा ।

ट. कारणात्मक संबंध

194. यह जांच की गई कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में कोई योगदान दिया है। यह निम्नानुसार पाया गया है :- :

- (क) तीसरे देशों से आयात:- जांच अवधि के दौरान कोरिया को छोड़कर अन्य संबद्ध देशों से स्रोतों से आयात न्यूनतम से कम हैं। तथापि कोरिया की कीमतें संबद्ध देशों द्वारा पेशकश की गई कीमतों से अधिक हैं।
- (ख) मांग में संकुचन :- यह नोट किया गया है कि विचाराधीन अवधि के दौरान मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। इसके विपरीत क्षति की जांच अवधि के दौरान मांग में समग्रतः 32% की वृद्धि हुई है।
- (ग) खपत की पद्धति :- खपत के पैटर्न में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं देखा गया है।
- (घ) प्रतिस्पर्धा की शर्तें :- आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति के लिए प्रतिस्पर्धा की शर्तें अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां उत्तरदायी नहीं हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस दावे का प्रतिवाद नहीं किया है।
- (ङ.) प्रौद्योगिकी विकास : आवेदक ने दावा किया है कि प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।
- (च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन: घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन ने घरेलू बाजार में याचिकाकर्ता की वित्तीय तथा आर्थिक स्थिति को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया है। पूर्ववर्ती पैराग्राफों में किए गए क्षति विश्लेषण में निर्यात संबंधी आंकड़े शामिल नहीं किए गए हैं।

195 प्राधिकारी नोट करते हैं कि सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारक जहां घरेलू उद्योग को कोई क्षति प्रदर्शित नहीं करते, वहीं निम्नलिखित कारक दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति, पाटित आयातों के कारण हुई है।

- क. संबद्ध देशों से पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप में तथा भारत में कुल आयातों, कुल मांग तथा उत्पादन के सापेक्ष वृद्धि हुई है।
- ख. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि मांग में वृद्धि हुई है।
- ग. मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की कीमतों में हास हुआ है।
- घ. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन अत्यधिक है और प्रत्येक संबद्ध देश से कम कीमत पर भी अत्यधिक बिक्री हुई है।

ट. निष्कर्ष:

196. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों एवं उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच के उपरांत तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:-

- (क) संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात संबंधित सामान्य मूल्यों से कम मूल्यों पर किया गया है ।
- (ख) विचाराधीन उत्पाद में घरेलू उद्योग ने वास्तविक क्षति का सामना किया है ।
- (ग) संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

ठ. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

197. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल किया जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे; अतः उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

198. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण से संबद्ध वस्तुओं के प्रयोग से विनिर्मित उत्पाद की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं और इसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की सापेक्षिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है । तथापि, पाटनरोधी उपायों के कारण भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी; विशेष रूप से तब, जब पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निवारण के लिए जरूरी राशि तक सीमित रखा जाए। इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण से पाटन पद्धतियों द्वारा हासिल अनुचित लाभ दूर होगा, घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता को बनाए रखने में सहायता मिलेगी । निचले स्तर के उद्योग पर इस प्रभाव को कम से कम करने की दृष्टि से प्राधिकारी ने पाटन एवं क्षति का अंश कम करने के आधार पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना उचित समझा है । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबंधित देशों से आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

ड. सिफारिशें

199. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत करके इसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई थी और निर्यातकों, आयातकों व अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के बारे में सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था । पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में पाटन, क्षति व उनके बीच कारणात्मक संबंध के बारे में जांच की शुरुआत कर उसे जांच संपन्न करने और संबंधित देशों से निर्यातित अथवा वहां से मूल रूप में आने वाले संबंधित सामानों के आयात से संबंधित सकारात्मक पाटन मार्जिन के निश्चयात्मक निर्धारण तथा ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को सिद्ध करने के बाद प्राधिकारी का विचार है कि वर्तमान मामले में पाटन तथा "क्षति" को निष्प्रभावी करने के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करना

अपेक्षित है । अतः प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निम्नलिखित रूप तथा तरीके से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना आवश्यक समझते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं ।

200. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन तथा "क्षति" मार्जिन में से कमतर के निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की "क्षति" दूर हो सके । तदनुसार संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की जाती है ।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष / उप शीर्ष	वस्तु का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	ओमान	ओमान	मै. ओमान पोलीप्रोपीलीन एलएलसी	मै. ओमान पोलीप्रोपीलीन एलएलसी	67.68	मी.ट.	अम.डॉ.
2	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	ओमान	ओमान	क्र.सं.1 में विनिर्दिष्ट संयोजन को छोड़कर अन्य कोई		241.82	मी.ट.	अम.डॉ.
3	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	ओमान	ओमान से इतर कोई	कोई	कोई	241.82	मी.ट.	अम.डॉ.
4	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	उन देशों को छोड़कर कोई देश, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	ओमान	कोई	कोई	241.82	मी.ट.	अम.डॉ.
5	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सऊदी अरब	सऊदी अरब	एडवार्ड पोलीप्रोपीलीन कंपनी	बिनमार इंटरनेशनल लि., अमरीका	166.20	मी.ट.	अम.डॉ.
6	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सऊदी अरब	सऊदी अरब	सऊदी पोलीओलेफिन्स कंपनी	नेशनल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीयलाइजे शन मार्केटिंग कंपनी/वेसल पोलीओलेफिन्स कंपनी	89.23	मी.ट.	अम.डॉ.
7	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सऊदी अरब	सऊदी अरब	सऊदी पॉलीफिन्स कंपनी	वेसिल इंटरनेशनल ट्रेडिंग एफ जैड ई	51.16	मी.ट.	अम.डॉ.
8	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सऊदी अरब	सऊदी अरब	सऊदी यूरोपियन पेट्रोकेमिकल कंपनी	सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन	171.97	मी.ट.	अम.डॉ.
9	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सऊदी अरब	सऊदी अरब	सऊदी गानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी	सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन	87.86	मी.ट.	अम.डॉ.

10	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सऊदी अरब	सऊदी अरब	सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी	मै. एक्सोन मोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक	177.56	मी.ट.	अम.डॉ.
11	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सऊदी अरब	सऊदी अरब	क्र.सं.5 से 10में विनिर्दिष्ट संयोजन को छोड़कर अन्य कोई		322.57	मी.ट.	अम.डॉ.
12	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सऊदी अरब	सऊदी अरब से इतर अन्य कोई	कोई	कोई	322.57	मी.ट.	अम.डॉ.
13	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	उन देशों से इतर अन्य कोई देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	सऊदी अरब	कोई	कोई	322.57	मी.ट.	अम.डॉ.
14	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सिंगापुर	सिंगापुर	दि पोलीफिन कंपनी (सिंगापुर) पी टी ई लि.	सुमितोमो कोर्पोरेशन एशिया पी टी ई लि..	121.28	मी.ट.	अम.डॉ.
15	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सिंगापुर	सिंगापुर	दि पोलीफिन कंपनी (सिंगापुर) पी टी ई लि.	टोयोटा टयूशो (सिंगापुर) पी टी ई लि..	295.09	मी.ट.	अम.डॉ.
16	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सिंगापुर	सिंगापुर	दि पोलीफिन कंपनी (सिंगापुर) पी टी ई लि.	मारुबेनी कैमिकल एशिया पैसिफिक पी टी ई लि..	शून्य	मी.ट.	अम.डॉ.
17	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सिंगापुर	सिंगापुर	दि पोलीफिन कंपनी (सिंगापुर) पी टी ई लि.	इटोचू प्लास्टिक पी टी ई लि.	शून्य	मी.ट.	अम.डॉ.
18	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सिंगापुर	सिंगापुर	दि पोलीफिन कंपनी (सिंगापुर) पी टी ई लि.	सुमितोमो कैमिकल एशिया पी टी ई लि..	28.49	मी.ट.	अम.डॉ.
19	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सिंगापुर	सिंगापुर	एक्सोन मोबिल कैमिल एशिया पैसिफिक	एक्सोन मोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक	38.77	मी.ट.	अम.डॉ.
20	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सिंगापुर	सिंगापुर	एक्सोन मोबिल कैमिल एशिया पैसिफिक, सिंगापुर	मिल्सुबिसी कैमिकल थाईलैंड (क.) लि.	शून्य	मी.ट.	अम.डॉ.
21	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सिंगापुर	सिंगापुर	क्र.सं.14 से 20 में विनिर्दिष्ट संयोजन को छोड़कर अन्य कोई		323.50	मी.ट.	अम.डॉ.
22	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	सिंगापुर	सिंगापुर से इतर कोई	कोई	कोई	323.50	मी.ट.	अम.डॉ.
23	39021000 एवं 39023000	पोलीप्रोपीलीन (अर्थात् प्रोपीलीन के होमो-पॉलीमर्स एवं प्रोपीलीन तथा एथीलीन के को-पॉलीमर्स)	उन देशों से इतर अन्य कोई देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	सिंगापुर	कोई	कोई	323.50	मी.ट.	अम.डॉ.

*ईपीपी बीड्स (एक्सपेंडेड पॉलीप्रोपीलीन) को इन सिफारिशों की परिधि और दायरे से बाहर रखा जाता है ।

201. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3 क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लागू शुल्क को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल हैं;

202. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2010

Final Findings

Subject : Anti-Dumping Investigation concerning imports of Polypropylene originating in or exported from Oman, Saudi Arabia and Singapore.

No.14/5/2009-DGAD.—Whereas the Designated authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the AD Rules); recommended imposition of Anti Dumping duty on the imports of 'Polypropylene' originating in or exported from Oman, Saudi Arabia and Singapore.

A. Background of the Case

2. Having regard to the Act and the AD Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), received a written application from M/s Reliance Industries Ltd. on behalf of the domestic industry, alleging dumping of 'Polypropylene (i.e., homo polymers of propylene and co-polymers of propylene and ethylene)' (hereinafter also referred to as the subject goods); originating in or exported from Oman, Saudi Arabia and Singapore (hereinafter also referred to as subject countries).
3. The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries. The Authority notified High Commission/Embassies of the subject countries in India about the receipt of the application claiming, *inter alia*, allegations of dumping and consequent injury to the domestic industry before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules. The Authority issued a public notice dated 24th February, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries, in accordance with the Rule 6(1) of the AD Rules to determine the existence, degree and effect

of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

4. The Authority recommended imposition of provisional Anti-dumping duty on the imports of 'Polypropylene' originating in or exported from Oman, Saudi Arabia and Singapore falling under Sub-headings 39021000 and 39023000. The Preliminary findings were notified vide Notification No 14/5/2009-DGAD dated 15th June 2009.

B. PROCEDURE

5. In these proceedings the procedure described herein below has been followed:

- i. The High Commission/Embassies of the subject countries in India were informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.
- ii. The Designated Authority sent copies of the initiation notification dated 24th February 2009 to the High Commission/Embassies of the subject countries in India, known exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, and the domestic industry, as per the information available with it. Parties to this investigation were requested to file the questionnaires' responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to the High Commission/Embassies of the subject countries along with a list of known exporters / producers with a request to advise the exporters/ producers from the subject countries to respond to the questionnaires within the prescribed time.
- iii. Copy of the non-confidential version of the application filed on behalf of the domestic industry was made available to the known exporters and the High Commission/Embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
- iv. Questionnaires were sent to the following known exporters from the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules to elicit relevant information:
 1. Advanced Polypropylene Company, Saudi Arabia
 2. SABIC Basic Industries Corporation, Saudi Arabia
 3. Tasnee – National Industrialization Company, Saudi Arabia
 4. ExxonMobil Chemical Co, Singapore 098633
 5. Oman Polypropylene LLC, Oman
- i. In response to the initiation notification, the following exporters / producers from subject countries have responded:

1. M/s Oman Polypropylene LLC, Oman
 2. M/s Advanced Polypropylene Company, Saudi Arabia
 3. M/s Vinmar International Ltd.
 4. M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC)
 5. M/s Saudi European Petrochemical Company (IBN ZAHAR), Saudi Arabia
 6. M/s Saudi Yanbu Petro-Chemical Company (YANPET), Saudi Arabia
 7. M/s Saudi Polyolefins Company, Saudi Arabia
 8. M/s National Petrochemical Industrialization Marketing Company, Saudi Arabia
 9. Basell International Trading FZE,
 10. M/s Exxon Mobil Chemical Asia Pacific, Saudi Arabia
 11. M/s Exxon Mobil Chemical Asia Pacific, Singapore
 12. M/s Itochu Plastics Pte. Ltd.
 13. M/s Marubeni Chemical Asia Pacific PTE Ltd., Singapore
 14. M/s Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd., Singapore
 15. M/s Sumitomo Corporation Asia Pte Ltd., Singapore
 16. M/s The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd.
 17. M/s Toyota Tsusho (Singapore) Pte Ltd., Singapore
 18. M/s Inabata Singapore Private Limited
 19. M/s Mitsubishi Chemical (Thailand) Co. Ltd.
- ii. Questionnaires were sent to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4):
1. Organization of Plastics Processors Of India, Mumbai
 2. All India Plastics Manufacturers Association, Mumbai
 3. All India Flat Tape Mfrs. Association, New Delhi
 4. P.P. Products Pvt. Ltd., Kolkata
 5. Tarajyot Polymers Ltd., Kolkata
 6. ITC Ltd., Kolkata
 7. Paharpur Cooling Towers Ltd., Kolkata
 8. Time Packaging Ltd., Mumbai
 9. Petro Plast Industries Limited, Chennai
 10. The Supreme Group, Mumbai
 11. Big Bags (India) Private Ltd., Bangalore
 12. Paramount Communications Ltd., New Delhi
 13. Packaging India Pvt Ltd., Chennai
 14. Flex Industries Limited, Noida
 15. Bishan Saroop Ramkishan Agro, delhi
 16. Blow Packaging (India) Ltd. , Chennai
 17. Chennai Polypack Private Ltd., Chennai
 18. Hydro S & S Industries Ltd., Chennai
 19. Exide Industries Ltd., Kolkata
 20. Pentadaewha Auto Parts Ltd., Chennai

21. Veekay Polycoats Ltd., New Delhi
22. Machino Plastics Ltd., Gurgaon
23. Dow Chemical International Ltd., Mumbai
24. Hitech Plast Ltd., Mumbai
25. General Commodities Pvt. Ltd., Bangalore
26. Balmer Lawrie-Van Leer Ltd., Mumbai
27. Baxter India Pvt. Ltd., Gurgaon

iii. In response thereof, following have responded:

1. Trichy & Pudukkottai Districts Plastic Manufacturers, Traders' Association (TRIPMA),
2. M/s. P.P. Products Private Limited, Bangalooru
3. M/s. Rajyot Polymers Ltd., Bangalore,
4. Chennai Plastics Manufacturers & Merchants Association,
5. Coimbatore Plastic Manufacturers & Trader's Association, Tamilnadu,
6. The Coimbatore District Plastics Manufacturer's Association,
7. PLASMA, Pondy Plastic Manufacturers & Merchants Association,
8. Sivakasi Plastic Manufacturers Association (SIPMA),
9. Tirupur Plastics Manufacturers Association (TIPMA),
10. Veekay Polycoats Limited, Gurgaon/New Delhi,
11. North Orissa Chamber of Commerce & industry,
12. Dindigul District Polythene Bag Manufactures
13. Dealers Welfare Association
14. Exide Industries Ltd., Kolkata
15. Salem Plastic Sellers' & Manufacturers' Association.
16. All Pondicherry Plastic Traders & Manufacturers Association (APPTMA)
17. M/s Kanpur Plastipack Ltd.
18. M/s Jolly Containers, India
19. M/s Daman Polyfabs, India
20. M/s Essel Propack Ltd., India
21. All India Plastic Manufacturers' Association (AIPMA)-Mumbai,
22. All India Flat Tape Manufacturers' Association (AIFTMA)-Bangalore,
23. All India Syringes and Needles Manufacturer's Association
24. Indian Plastics Federation (IPF)-Kolkata,
25. Organisation of Plastic Processors of India (OPPI)-Mumbai,
26. Gujarat State Plastics Manufacturers' Association (GSPMA)-Ahmedabad,
27. The Tamil Nadu Plastics Manufacturers' Association (TAPMA)-Chennai.
28. Andhra Pradesh Plastics Manufacturers' Association (APPMA), Hyderabad
29. Ms/ Blow Packaging (India) Ltd. , India
30. M/s Jumbo Bag Ltd., Chennai
31. M/s Hitech Plast Ltd., India
32. M/s Paracoat products Limited

- iv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years and for the period of investigation.
- v. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- vi. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic Industry.
- vii. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2008 to 31st December 2008 (hereinafter also referred to as the POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, covers the periods April 2005-March 2006; April 2006-March 2007, April 2007-March 08 and the POI.
- viii. The Authority, having regard to the Act and the AD Rules; vide Notification No. 14/5/2009-DGAD dated 15th June 2009 recommended imposition of provisional Anti Dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries. The provisional Anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries was imposed vide Customs notification No. 82/2009-Customs dated 30th July 2009.
- ix. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 10th December 2009. The parties, which presented their views in the public hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally. Interested parties were provided opportunity for rejoinder submissions on the views expressed by opposing interested parties.
- x. The arguments made in the written submissions / rejoinders received from interested parties have been considered, wherever found relevant, in these final findings;
- xi. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry and the co-operating producers/exporters.
- xii. In accordance with Rule 16 of the AD Rules, the essential facts considered by the Authority were disclosed to the known interested parties and comments received on the same have been duly considered, wherever found relevant, in these final findings.

- xiii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xiv. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the facts available.
- xv. *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

Submissions made by Oman PP as regards de-minimis imports from Oman

- 6. It has been contended by Oman PP that the volume of imports from Oman are negligible and well below three percent of the imports. In support of their claim, they provided the import data downloaded from the Ministry's website (<http://commerce.nic.in>) for the year 2008-09 and for the POI and stated that it has been computed proportionately for 9 months from the data for the whole financial year 2008-09. Besides, they also provided the import data obtained from Info-drive for the whole financial year 2008-09. Based on the two data, it has been claimed that imports of the subject goods from Oman is below the *de-minimis* thresholds. It has been further contended that since the product under consideration includes compounds the imports under HS Code 39029000 (Other Polymers of Propylene in Primary Forms) would be covered by the scope of the present investigation. This means that the imports under HS Code 39029000 are also required to be taken in to account of in the present investigation.

Examination by the Authority

- 7. The Authority has carefully examined the contention of the exporter from Oman regarding their *de minimis* share in the total imports of the subject goods. The Authority has received the transaction-wise details of the actual imports from DGCI&S for the POI i.e. April 2008 to December 2008 and thus is of the view that the consolidated data of imports for the POI from the whole financial year downloaded from the Ministry of Commerce website submitted by the exporter is not required to be considered.
- 8. An examination of the DGCI&S data pertaining to the subject goods shows that the actual imports of the product under consideration from Oman are well above the *de minimis* thresholds. Besides, the Authority also examined the transaction-wise import data obtained by the respondent from Info-drive. An examination of the same revealed that the import data, *inter alia*, contains transactions which did not relate to product under

consideration. It was further noted that there were particularly three entries in the import data where the price per MT was shown as abnormally low. The matter was also discussed with the representatives of Oman PP. A scrutiny of these entries showed that the import volume for one transaction was about 16000 MT and for the other two it was about 32000 MT which is not possible to be shipped under one invoice. Besides the values associated were not reflective of the prices at which the imports were being made at the time and these values were abysmally low. Apparently, the error with regard to these transactions was because of incorrect mention of the unit of measurement in the import data. The Authority therefore corrected the unit of measurement for these transactions from MT to KG and analysed the rectified data. Even on the basis of rectified but unsorted data it was noted that the imports from Oman were well above the *de minimis* thresholds and the share of imports from Oman would be higher, if it is seen on the basis of sorted import data. With regard to consideration of imports under HS Code 39029000, it is noted that the same have also been considered while undertaking the analysis.

9. In view of the above, the Authority concludes that the imports from Oman are above the *de minimis* thresholds and Oman is not required to be excluded from the ambit and scope of the present investigation.

C. Period of Investigation

Submissions made by the Interested Parties

10. It has been contended that the period of investigation in the present case is too short and includes the months during which the movement of raw materials and polypropylene prices was erratic due to global recession. The period of investigation should be fixed for a period of 18 months for a fair and proper analysis.

Examination by the Authority

11. The Authority notes that no new submissions have been made after the preliminary findings by the interested parties on the period of investigation. The Authority, therefore, confirms the preliminary findings that the period of investigation in the instant matter has been appropriately chosen, covering the most recent available data on the subject.
12. However, considering significant movements in the prices of raw-materials and that of the subject goods during the POI, the analysis of the data has been undertaken on a month-wise basis; to the extent the same was feasible.

D. Product Under Consideration and Domestic Like Article

13. The product under consideration is 'Polypropylene (i.e., homo-polymers of propylene and co-polymers of propylene and ethylene)'. The subject goods are used as woven sacks for

cement, food-grains, sugar, fertilizer, bags for fruits & vegetables, TQ & BOPP films, containers etc.

14. The subject goods are classified under Custom Headings 39021000 and 39023000. However, the Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Submissions made by the Interested Parties

15. It has been contended that the Application covers two products i.e. Propylene homo-polymer and Propylene co-polymers as classified under the sub-heading 39021000 and 39023000 of the Customs Tariff Act and that these two products are different from each other. Propylene co-polymer is ***% expensive than Polypropylene homo-polymer and is technically superior to Polypropylene.
16. M/s TPC has stated that the COSMOPLANE grades AZ564G – specially designed for industrial parts, BRA61 453B, BRA61 454B, & BRA61 used for automotive compounding or injection molding of automotive, CPS188 454B - used for automotive interior parts that requires good surface appearance and FL7540L, FS5611L, FS6612L, FL7320L, FL7540L, FL7632L, FS5611L, FS6612L & FL7641L should be excluded from the purview of the product under consideration as the domestic industry does not produce equivalent to these grades of Polypropylene produced by TPC and exported.
17. M/s ExxonMobil has stated that the grades namely PP7033N, AP3N, PP7555KNE1 & PP 7684 are not manufactured by the domestic industry. M/s ExxonMobil believes that the specialised products such as Achieve 6936G1, Vistamaxx 3000, Vistamaxx 3020FL, Vistamaxx3980FL, Vistamaxx 6102, Exxon IT0316, Exxtral compounded and filled polypropylenes do not fall within the scope of the product under consideration.
18. M/s Toyota Tsusho India has stated that the equivalent domestic grade B400MN is not as per the TSM standards and also do not meet some of the chemical characteristics with that of grade for PP2 or AZ564G on the basis of the test report of ARAI.
19. M/s Paracoat products Limited has stated that no one is manufacturing EPP beads (Expanded Polypropylene) in India and hence EPP beads (Expanded Polypropylene) should be excluded from the scope of this investigation and no anti-dumping duty should be levied against it. They have supported their claim by attaching an E-mail correspondence with M/s Reliance Industries Limited to this effect.
20. Some of the interested parties have stated that the homo-polymer and co-polymers are two different products and the injury analysis therefore, is required to be carried out separately.
21. It has been contended that ter-polymer and compounds cannot be included within the purview of the investigation and that the scope of product in the initiation notification

was homopolymers of propylene, and co-polymers of ethylene and propylene. It did not cover other polymers. A ter-polymer is a co-polymer consisting of 3 distinct monomers by using propylene, ethylene and butene. It is distinct and different from the co-polymers of propylene and ethylene. Some of the interested parties have stated that the polypropylene compounds are also required to be excluded from the investigation.

Submissions made by the domestic industry

22. The domestic industry has stated that the interested parties have claimed exclusion of certain grades on the basis of mere statements and have not provided sufficient details with regard to technical specifications, chemical composition, commercial and technical substitutability, etc. The domestic industry submits that in the absence of such basic details about the products concerned, it is impossible for any party to offer its comments.
23. The interested parties have not given any cogent basis to establish that the stated grades/types/nomenclatures are not like articles to the product under consideration. Since the onus of proof of exclusion is entirely on the parties claiming such exclusion, no grade or type should be excluded until such interested parties provide sufficient legal and factual basis along with evidence.
24. The domestic industry has contended that it has been the consistent practice of the Designated Authority to consider exclusion of certain grades/types from the purview of the product under consideration by adopting the following tests:
 - a. That the domestic industry does not produce the said product and is also not capable of producing the same.
 - b. That the grades which are sought to be excluded are not technically or commercially substitutable with the grades produced by the domestic industry.
 - c. That the onus of proving that any product type is to be excluded is entirely on the party which seeks such exclusion.
 - d. That the exclusion of certain grades/types should not lead to a situation whereby the effect of duty is diluted or becomes ineffective.
25. As long as the goods produced by the domestic industry can commercially and technically be substituted for the grades/types produced by the exporters, the same cannot be excluded. It has also been submitted that the domestic industry is capable of producing any grade of the subject goods and the claims of exclusion need to be rejected summarily.
26. It has been contended that in Fully Drawn Yarns from Indonesia, Korea, Malaysia and Taiwan case, under the similar circumstances the exporters had disputed inclusion of certain grades or types of fully drawn yarn under the purview of product under consideration, the Authority had then held that there is no significant difference in the dumped goods and the product under consideration manufactured by the domestic industry. The imported goods are used by the user industry interchangeably with the goods produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry and produced by the subject countries, being technically and commercially

substitutable, are 'like articles' under the Anti-dumping Rules. The Authority, therefore, included all types of the grades and types of fully drawn yarns as part of the investigation.

27. The domestic industry is manufacturing the equivalent grades for FL7320L, FL7540L, FL7632L, FS5611L, FS6612L, FL7641L, PP2 or AZ564G, BRA61453B, BRA61454B, BRA61 and CPS188454B as SR070NS, SR80NS, SR072NS, SR60N, SR50NS, SRO71NS, B400MN, B650MN-BN84302X, B650MN-FPT20FR, B550MN-AN70992Y and C320MN-PPSN3 respectively. The equivalent grades of the DI mentioned above are appropriately reflected in the product brochures.
28. It has been contended that the TSM standards are user specific standards and are not internationally recognized standards. Therefore, to state that the grade manufactured by the domestic industry does not meet TSM standards is inconsequential. Further, the importer never provided to them any test report earlier. It has been submitted that importer is trying to mislead the Authority by arbitrarily stating about three characteristics namely MFI, HDT & Elongation at break as important ones. There are various technical parameters and the most important of them are izod impact and flexural modulus, which meet the criteria laid down by the importer.
29. No interested party has disputed about the fact that both homo-polymer and co-polymer are indeed Polypropylene only. Since the product under consideration covers all types of Polypropylene, it cannot be argued that a distinction has to be made out merely because there are some differences in the products. It is further submitted that there are bound to be some differences between the various grades/types of Polypropylene but this should have no bearing on the scope of investigations. It is further submitted that as far as the Domestic Industry is concerned, there is no difference in the cost of production of the two types of Polypropylene. The price difference is also minimal (1 to 2%) as can be seen from the information from Platts. It is further submitted that wherein butene is also used for making the co-polymers along with ethylene, the difference in cost is insignificant as the butene is only about 1-2% of total raw materials used.
30. Ter polymers are indeed covered under the product under consideration as the ter polymers contain both the raw materials propylene and ethylene. Further any co-polymer is covered under the product under consideration as long as the same is produced by using propylene and ethylene and it is immaterial whether any other additive / raw material is used or not.
31. With regard to compounding, it is submitted that it is a process of adding additives to change the properties of the grade which include colour, tensile strength, temperature resistance, impact strength etc. before using the subject goods for the manufacture. However, the basic form and the product does not change which remains polypropylene only. Therefore, compounds are not to be excluded as the product essentially continues to remain Polypropylene.
32. Under the Customs Rules of Interpretation, where a product contains two or more materials, the same would be classified based on the majority contents of a raw material

and ignoring the other raw materials. Therefore, on this ground also, the compounds cannot be excluded from the purview of investigation.

Examination by the Authority

33. **Product under Consideration:** The Authority notes that the scope of the investigation was clearly defined while initiating the investigation viz. 'Polypropylene (i.e., homo-polymers of propylene and co-polymers of propylene and ethylene)' and thus 'ter-polymer' is not within the ambit and scope of the investigation. However, it would not be correct to state that compounds are not part of the product under consideration.
34. The Authority has taken note of the claims and counterclaims made by the interested parties with respect to PUC, including those in respect of exclusion of certain grades/types. Some of the interested parties have contended that there is a significant price difference between the homo-polymer and the co-polymer. These claims have, however, been disputed by the domestic industry. However, it has not been disputed by any party that co-polymers of propylene and ethylene are not Polypropylene.
35. The Authority further notes that the claims regarding exclusion of certain grades of polypropylene have been contested and refuted by the domestic industry. In a reference made to them on the subject, the domestic industry has categorically asserted that they indeed offer the subject goods of the specified grades claimed to be not manufactured by the domestic industry as per the assertion of the exporters. They have also provided the details of the equivalent grades. It is, further noted that the interested parties have not substantiated their claims regarding exclusion with any scientific literature or technical evidence.
36. However, considering the submissions made by M/s Paracoat products Limited in respect of EPP beads (Expanded Polypropylene) and the relevant facts available on record; EPP beads (Expanded Polypropylene) is excluded from the ambit and scope of this investigation.
37. With regard to like article, Rule 2(d) of the AD Rules provides as under: -
- "like article " means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation"*
38. After considering the information on record, the Authority notes that there is no significant difference in product under consideration exported from the subject countries and the product produced by the Indian industry. Product under consideration produced by the domestic industry are comparable to the imported subject goods in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, in respect of manufacturing process & technology, product specifications, distribution & marketing

and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

39. Thus, the Authority is of the view that the subject goods produced by the applicant domestic industry are like article to the product under consideration in accordance with the AD Rules.

E. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

40. At the time of the initiation of this investigation, Rule 2(b) of the AD Rules read as follows:-

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers may be deemed not to form part of domestic industry".

41. This Rule has been recently been amended as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only"

42. According to the applicant, there are only two producers of the like Article in the country. The Application has been filed by M/s Reliance Industries Ltd. on behalf of the domestic industry. The other producer, that is, M/s Haldia Petrochemicals Ltd. has supported the application.

43. As per the evidence available on record, production of M/s Reliance Industries Ltd. accounts for a major proportion of the domestic production of like article, being significantly more than 50% of Indian production. The application thus satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules. The Authority notes that no interested party has disputed the 'standing' of the applicant. Therefore, the applicant M/s Reliance Industries Ltd. is being treated as 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) read along with Rule 5 of the AD Rules for the purpose of the present investigation.

F. CONFIDENTIALITY**Submissions made by Interested Parties**

44. It has been contended that the Designated Authority must come to a categorical conclusion that confidential treatment contended in the petition is bona fide and germane to the rights of the domestic industry. A bare perusal of the petition indicates that confidentiality has been claimed as a rule rather than exception.

Submissions made by the domestic industry

45. The exporters have claimed excessive confidentiality without any proper justification. Further, non-confidential version of the questionnaire response has not been given for all the information contained in the confidential version without assigning proper reasons. It is not in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. From the non-confidential version of the questionnaire responses, it is not clear whether they have given the information separately for each type of Polypropylene. In this context, it is submitted that all the exporters have claimed confidentiality on even the quantum of imports which is not admissible since the Domestic Industry has been made to provide quantity related information even in the non-confidential version of the application.
46. In their post disclosure statement comments, the domestic industry has stated that the confidentiality claims of the cooperating exporters relating to their data have been accepted and data / information has been kept confidential as claimed by them in this investigation. It is submitted that the exporters by not providing the non-confidential response in accordance with the Trade Notice No. 4/27/2007 dated 25th March 2009 and the practice and guidelines being followed by the Authority have got away with the minimal information whereas the domestic industry was put under extra burden to give details in its non-confidential version in accordance with the aforesaid trade notice and guidelines. It is further submitted that in the absence of such details the domestic industry is not in a position to assist the Authority to arrive at the correct results. They have accordingly requested that the exporters may be asked to provide their complete response in accordance with the aforesaid trade notice and the guidelines or else they may be treated as non-cooperative and their dumping margin be determined based on the facts available.

Examination by the Authority

47. The Authority has taken note of the above submissions. The information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information

on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the 'facts available'.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Normal Value

48. The Authority sent questionnaire to the known exporters/producers from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. Response to the questionnaires were received from the following companies –

1. M/s Oman Polypropylene LLC, Oman
2. M/s Advanced Polypropylene Company, Saudi Arabia
3. M/s Vinmar International Ltd., USA
4. M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC)
5. M/s Saudi European Petrochemical Company (IBN Zahr), Saudi Arabia
6. M/s Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet), Saudi Arabia
7. M/s Exxon Mobil Chemical Asia Pacific, Saudi Arabia
8. M/s Saudi Polyolefins Company, Saudi Arabia
9. M/s Exxon Mobil Chemical Asia Pacific, Singapore
10. M/s The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd., Singapore
11. M/s Itochu Plastics Pte. Ltd., Singapore
12. M/s Marubeni Chemical Asia Pacific PTE Ltd., Singapore
13. M/s Sumitomo Corporation Asia Pte Ltd., Singapore
14. M/s Toyota Tsusho (Singapore) Pte Ltd., Singapore
15. M/s Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd., Singapore
16. M/s Mitsubishi Chemical Thailand (Co.) Ltd., Thailand
17. M/s National Petrochemical Industrialization Marketing Company, Saudi Arabia
18. Basell International Trading FZE,
19. M/s Inabata Singapore Private Limited

Submissions made by Domestic Industry

49. The responding exporters have failed to fulfill their obligation under the Indian law by not providing the meaningful summary of the response to exporters' questionnaire and claimed excessive confidentiality without any proper justification.
50. The raw material prices for the producers in Oman and Saudi Arabia are not reliable as the same are not determined based on the market conditions. All the feedstock is sourced from State-owned enterprise and the pricing of the same is State controlled.

51. Saudi Arabia admittedly follows a dual price policy with respect to feedstock prices which are admittedly fixed significantly lower than the comparative export prices. This fact has also not been denied by any of the interested parties to the best of their knowledge. It may be appreciated that the pricing of feedstock in such a manner does not reflect the true costs nor does it allow a proper and fair comparison. Wherever the Authority notes in terms of the provisions of Section 9A (1) (c) of the Custom Tariff Act that the domestic prices are not reliable and the same do not permit a fair and proper comparison on account of a particular market situation, the domestic sales are required to be rejected and normal value for the producers is to be constructed. It has been further stated that because of the feedstock prices being significantly lower as compared to the export prices; a particular market condition has been created by Saudi Arabia, wherein the domestic costs and prices of the subject goods would always be significantly lower than the export price. The producers located in Saudi Arabia would always be in an unfairly advantageous position as against the other producers across the globe entirely on account of the government intervention of controlling the prices for domestic consumption.
52. In this context, the domestic industry has also drawn attention of the Authority to the Australian Guidance on Market Situation, wherein it has been laid down that the term 'particular market situation' potentially covers a variety of situations including the situation where the domestic selling prices in the country of export have been materially affected by government influence rendering those prices unsuitable for use in establishing domestic normal values.
53. Referring to the provisions of Para 1 of Annexure I to Anti-dumping Rules, the domestic industry has stated that as the feedstock prices are admittedly State-controlled and heavily subsidized in Saudi Arabia, the same cannot be considered to reasonably reflecting the cost associated with the production. They have also cited the decision of the Authority in the case of Rubber Chemicals from China and Korea (Case No.14/5/2007-DGAD) and EC findings, (Council Regulation No. 1050/2006 of 11th July 2006) in the case of Potassium Chloride from Belarus and Russia in support of their contention.
54. The domestic industry in their comments to the disclosure statement has stated that M/s Itochu in its response has mentioned that it has supplied the subject goods directly to the customers and through traders. In the absence of complete information from the said trader, M/s Itochu cannot be granted an individual treatment or separate dumping margin as information relating to the complete chain of exports to India cannot be established. Such exporters ought to be treated as non-cooperative. It is also submitted that other exporters who have failed to provide information for the full chain of exports to India also be treated as non-cooperative and may not be granted an individual treatment or separate dumping margin. It is further submitted that the exporters may take a plea that their dumping margin and duty be determined based on the information of their direct exports and exports through other traders may be ignored. It is stated that the dumping margin and duty determination based on their direct exports to customers in India only would be completely contrary to the legal position and the consistent practice of the Authority besides the fact that it would give undue and unfair advantage to the exporters

for non-adherence to law. It would also deny effective protection to the domestic industry despite injury and causal link being proved. Under such a situation, the entire information of all such exporters is required to be rejected in case the same are not supported with the information of the traders to India.

55. It has been stated that the late responses of M/s Sabic, M/s IBN Zahr and M/s Yanpet have been accepted for individual treatment and the determination of dumping margin. It has been submitted that the responses of the said producers and exporter cannot be taken on record as the same have been filed at a very late stage i.e. after preliminary findings and such acceptance is not only against the principles of natural justice but also against the specific provisions of the AD Rules. Moreover, the non-confidential version of the documents of the said parties was also not in accordance with the aforesaid Trade Notice and the guidelines laid down by the Authority.

56. It has been stated that with regard to the determination of the cost of production for Saudi Arabian producers, they understand that the Authority proposes to consider the cost of production determined on the basis of the market prices of the feedstock during any particular month. The feedstock prices of the Saudi producers are based on a formula-based pricing. It is the price of the feedstock used in the formula which is not reflective of the market prices. Therefore, it is imperative that while arriving at the true cost of the feedstock, the Authority should simply substitute the market values of feedstock in the formula for arriving at the real market value for the concerned month.

57. It is also submitted that M/s Sabic has not provided the information for all the related companies who are engaged in the activity of the subject goods whereas legally they are required to give the information for all the related parties. They have not given any information for M/s Yansab Yanbu National Petrochemical Company and M/s Saudi Kayan who are also engaged in the activity of the subject goods. In this connection, relevant pages from M/s Sabic's website and the annual report have already been provided to the Authority. It clearly indicates that these companies are indeed related to M/s Sabic and are engaged in the activity of product concerned. It is also submitted in case of anti-dumping investigation before the several other authorities in EU, USA, Brazil etc., the exporter is required to give information for each related party which is engaged in the activity of the product concerned. The response from M/s Sabic ought to be rejected on this ground alone as per the consistent practice of the Designated Authority.

Submissions made by exporters / producers in subject countries

58. It has been contended that the Authority should not rely on the dumping calculation given in the application. The exporters have charged fair export prices which are in line with world and Indian prices for the like products type, specifications and quality. As such, the Applicant's dumping allegations, based on normal value calculated in the application are in accordance with their figment of imagination and are entirely baseless and that the Authority should refer to the respective questionnaire responses in this regard.

59. The exporter M/s Inabata Singapore Private Limited has stated that the normal value for TPC should be determined based on its export price to other markets with sufficient volume.
60. M/s Advanced Petrochemical Company (APPC) has stated that the existence of regulated prices for certain products in Saudi Arabia only reflects the agreement reached by WTO members concerning the right of the Saudi Government to maintain such regulated prices for a limited number of products. APPC has further stated that the extracts of the Working Party Report on the accession of Saudi Arabia to the WTO make it clear that the domestic price for Natural Gas Liquids (NGLs) in Saudi Arabia reflects the market value to producers of local sales and is based on the full recovery of costs and a reasonable profit. The claim of the domestic industry that such domestic prices do not reflect market conditions and would operate as a form of subsidization should therefore be dismissed. There is no basis in the WTO Agreements to disregard costs which reflect the market conditions in Saudi Arabia as it is undisputed among WTO members that Saudi Arabia is a market economy, and that it should also be treated as such for the purpose of anti-dumping investigations.

Treatment of Saudi Arabia as MET

- It has been contended by some exporters/producers from Saudi Arabia that Saudi Arabia should be given market economy status for the purpose of the present investigation for the following reasons:
 - i. On a plain reading of paragraph 8(3)(a) to Annexure I to the Anti Dumping Rules, it is amply clear that a firm can be declared to be working on market economy principles if all the following are satisfied: a) The decisions of the concerned firms are based on market principles; b) The decisions of the concerned firms are made without significant state interference; c) Costs of major inputs substantially reflect market values. The Domestic Industry in its submission has failed to prove non-existence any of the above mentioned conditions and hence the assertions made by the Domestic Industry falls flat on its face.
 - ii. The claim of the domestic industry is based on an incorrect reading of the content of "Report of working party on the accession of the Kingdom of Saudi Arabia to the WTO". The same makes it evident that feedstock prices in Saudi Arabia are reflective of the trends in the prices of the propane in the international market and is in no manner influenced or controlled by the Saudi Government. Such commercial pricing formula ensures that domestic propane prices ensure the recovery of reasonable profits and costs for the production of propane.
 - iii. In past, the Hon'ble Authority in various investigations has treated Saudi Arabia as a market economy and therefore similar treatment should be given to exporters of the subject goods.

iv. Without prejudice to the submissions above, allegations of the subsidized prices, if any, cannot be raised in an Anti Dumping

61. M/s Saudi Polyolefins Company has acknowledged that there are differences in the price at which propane is procured by SPC from Saudi Aramco and the international spot prices but it has claimed that the same is on account of certain factors, namely cost savings in infrastructure; cost savings in marketing; commercial advantage associated with long-term contracts; commercial value of reduced volatility and commercial value of large-volume purchases. It has been submitted by them that whilst comparing the international prices of propane with the prices at which propane has been procured by SPC, the Authority should keep the factors abovementioned to do an apple to apple comparison.

Submissions made by interested parties after the Disclosure statement

62. Subsequent to the disclosure statement, some of the exporters/producers from Saudi Arabia and as well as the Government of Kingdom of Saudi Arabia have filed their submissions which, *inter alia*, include the following:

- (i) Section 9A(1)(c)(ii) and Article 2.2 of the WTO Anti-Dumping Agreement do not confer power on the Authority to modify the cost of production, under any circumstances, except in the case of a non-market economy. Section 9A(1)(c)(ii) on which reliance has been placed by the Authority talks about the price of the like article / subject goods and not the price of the raw material / component that is used in the production of the subject goods.
- (ii) As far as the Saudi Arabian producer is concerned, his cost of production for the polypropylene is the same, whether intended for export or domestic sale. An advantage arising from a lower cost of production cannot by itself be construed as dumping by the producer.
- (iii) The Authority's conclusion that since the feedstock prices are government controlled there exists a "particular market situation" in Saudi domestic market as a result of which the domestic costs and prices of the producers / exporters in Saudi Arabia should not be accepted, is incorrect.
- (iv) Interpretation of Accession of Kingdom of Saudi Arabia to the WTO makes it evident that the prices of propane in Saudi Arabia are market driven. Reference in this regard may be made to the "Report of working party on the accession of the Kingdom of Saudi Arabia to the WTO" and it has been contended that it is evident that prices of Natural gas liquid feedstock in Saudi Arabia, including propane, are determined as per market principles. Based on the above mentioned report, it has been submitted that feedstock prices in Saudi Arabia are reflective of the trends in the prices of the propane in the international market and is in no manner influenced or controlled by the Saudi Government. Rather, the commercial pricing structure

applied in Saudi Arabia was “*negotiated between producer and consumers*”. Saudi government merely supports a commercial pricing structure for sales of propane in Saudi Arabia. Such commercial pricing formula ensures that domestic propane prices enables recovery of reasonable profits and costs for the production of propane. The said formula, as detailed in the “Report of working party on the accession of the Kingdom of Saudi Arabia to the WTO”, ensures that domestic selling price of propane are based on international market prices, adjusted to reflect the following commercial factors:

- cost of savings in infrastructure required for exports,
- cost of savings in marketing requisite for exports,
- commercial advantage associated with long term domestic contracts
- commercial value of reduced volatility
- commercial value of large volume purchases.

(v) On-spot international market prices of the Propane cannot be compared with the price at which Saudi producers procure propane. It has been stated that they entered into a long term (30 years), bulk supply agreement with the Saudi Aramco for supply of Propane. It is a known fact that prices of goods procured on long term and bulk supply basis are always less as compared to the on-spot prices of the goods. The Authority by comparing the actual price of propane paid by Saudi producers with the on-spot prices of propane in the international market is not doing an apple to apple comparison. The Authority should consider the price at which Saudi producers procure propane and should not compare the same with the on-spot prices of propane in the international market, even if the Authority seeks to factor in the price of the propane paid by another entity, it should not consider the on-spot price of propane and should only consider the price at which a similarly placed entity procures propane.

(vi) There is no warrant to replace the actual cost with the notional cost as stated above. Propane is a part of NGL (Natural Gas Liquids) group. The Council of Ministers Resolution No.68 of 1991 set NGL prices 30% lower than the export prices charged for those products. However, KSA Council of Ministers Resolution No.260 dated 7 January 2002 cancelled the earlier resolution No.68 of 1991. In terms of the new Resolution No.260 of 2002, Saudi Arabia applied commercial pricing to NGLs used as feedstock in Saudi Arabia. Further, Decision No.15 of the KSA Supreme Council for Petroleum Affairs implemented the Council of Ministers Resolution No.260 and reflected a negotiated pricing structure that ensured full recovery of production costs and a reasonable profit. Decision No.15 read with Resolution No.260 set out a detailed formula for ensuring that domestic NGL prices are based on international market prices adjusted for certain cost-based and other commercial considerations. Thus, the sale prices prevailing in Saudi Arabia for propane reflect international prices determined on commercial principles and negotiated between the producers and consumers.

- (vii) Saudi Arabia's WTO accession and that all WTO Members, including India, supported the adoption of the "Report of working party on the accession of the Kingdom of Saudi Arabia to the WTO", which clearly contradicts the approach taken by the Authority in the captioned investigation.
- (viii) The Authority in past has always treated Saudi Arabia as a Market Economy. It is pertinent to note that in none of the past investigations Saudi Arabia has been treated as a non-market economy; therefore, treating Saudi Arabia as a non market economy by the Authority would be contrary to the past practice of the Authority.
- (ix) Assuming but not admitting that the prices of Propane in Saudi domestic market is government controlled, the same cannot be a ground that can be raised in an anti-dumping investigation. In the event the cost of production of a particular entity is lower than the cost of production for the Indian producers on account of factors such as government control over the prices or exemption / subsidy given by the government of exporting entity, injury, if any, caused to the domestic Indian entity, can be examined in an appropriate investigation i.e. in an anti-subsidy / countervailing measures investigation.
- (x) The Australian guidelines are not concerned with the costs of raw materials but their purpose is to address the issue of domestic selling prices which are unsuitable for use in establishing normal values in the first place. Similarly, the reference to the Designated Authority's findings in the case of Rubber Chemicals from China and Korea omits to specify that the relevant findings in this case were specific to China which is also subject to the specific provisions of paragraph 15 of its Protocol of Accession in the context of anti-dumping investigations.
- (xi) Article 2.3 of the EC basic anti-dumping Regulation, which deals with the concept of "market situation", makes clear that such market situation relates to sales of the like product in the country of origin, and not to input and cost items. Further, the Authority cannot ignore that the countries cited as examples of the EC practice, i.e. Russia and Kazakhstan, are all non-WTO Members.
- (xii) Chapter 8 of the US AD manual, which deals with the establishment of normal value, also makes clear that the concept of "market situation" relates to the selling price of the like product on the domestic market.
- (xiii) The approach proposed to be taken by DGAD does not have any legal basis in the WTO Anti dumping Agreement. As per Article 2.2.1.1 of ADA when domestic prices are constructed, for the purpose of such construction costs shall normally be calculated on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided such records are in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country and reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration.

- (xiv) There is no reason why records kept by the Saudi producers should be disregarded for the purpose of determining raw material costs in so far as they can be verified and reflect the costs actually incurred by the producers concerned for the production of poly propylene. The WTO Anti dumping Agreement (Article 2.2) gives the importing country right to construct normal value only by calculating the cost of the final product and not by constructing the costs of raw materials.

Examination by the Authority

63. The issues raised by the interested parties from Saudi Arabia including by Government of Saudi Arabia have been examined as follows:
64. Section 9A (1) (c) (ii) reads as:

"when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

- (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under subsection (6):..."*

Article 2.2 of WTO's Anti-dumping Agreement reads as:

When there are no sales of the like product in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or when, because of the particular market situation or the low volume of the sales in the domestic market of the exporting country, such sales do not permit a proper comparison, the margin of dumping shall be determined by comparison with a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country, provided that this price is representative, or with the cost of production in the country of origin plus a reasonable amount for administrative, selling and general costs and for profits

Article 2.2.1 of the Agreement reads as

2.2.1 Sales of the like product in the domestic market of the exporting country or sales to a third country at prices below per unit (fixed and variable) costs of production plus selling, general and administrative costs may be treated as not being in the ordinary course of trade by reason of price and may be disregarded in

determining normal value only if the authorities determine that such sales are made within an extended period of time in substantial quantities and are at prices which do not provide for the recovery of all costs within a reasonable period of time. If prices which are below costs at the time of sale are above weighted average costs for the period of investigation, such prices shall be considered to provide for recovery of costs within a reasonable period of time.

65. It is seen that the while Article 2.2.1 of the Anti-Dumping Agreement itself provides for a method for determining whether sales below cost are 'in the ordinary course of trade', that provision does not purport to exhaust the range of methods for determining whether sales are 'in the ordinary course of trade'. The provision does not even provide the range of possible methods for determining whether sales are 'in the ordinary course of trade'. This reasoning is fully borne out from the Appellate Body ruling on the subject in the case of *US — Hot-Rolled Steel [WT/DS184/AB/R (Para 147)]*, wherein it was held that the said provision does not purport to exhaust the range of methods for determining whether sales are "in the ordinary course of trade":

"We note that Article 2.2.1 of the Anti-Dumping Agreement itself provides for a method for determining whether sales below cost are 'in the ordinary course of trade'. However, that provision does not purport to exhaust the range of methods for determining whether sales are 'in the ordinary course of trade', nor even the range of possible methods for determining whether low-priced sales are 'in the ordinary course of trade'. Article 2.2.1 sets forth a method for determining whether sales between any two parties are 'in the ordinary course of trade'; it does not address the more specific issue of transactions between affiliated parties. In transactions between such parties, the affiliation itself may signal that sales above cost, but below the usual market price, might not be in the ordinary course of trade. Such transactions may, therefore, be the subject of special scrutiny by the investigating authorities."

66. The above provisions clearly seek to address a situation arising as a result of the particular market situation which in turn may have an impact on the relevant costs and prices of the subject goods. In such situations, the Authorities can resort to other information which is unaffected by such distortions. The basic purpose of the said clause is to enable the Authority to arrive at the fair and proper "Normal Value".
67. Since the feedstock prices i.e. propane (the major raw material) prices are significantly lower as compared to their market value and further because this difference is on account of the policy decision of the Govt. of Saudi Arabia, a particular market condition can be said to exist in Saudi Arabia wherein the domestic costs and prices of the subject goods would always be significantly lower than the export price. Under the circumstances, the producers / exporters located in Saudi Arabia would always have an unfair advantage vis-à-vis the other producers situated overseas entirely on account of the Saudi Government intervention of maintaining dual prices for domestic consumption and exports. Thus, the facts and circumstances of this case are covered by the scope of "particular market situation". The term "a particular market situation" has also been interpreted by

authorities of some of the WTO Members in a similar manner. In particular, the Attention of the Authority has also been drawn to the following references on the issue:

- The Australian Guidelines on “Particular Market Situation” lays down that the term ‘particular market situation’ potentially covers a variety of situations including the situation where the domestic selling prices in the country of export have been materially affected by government influence rendering those prices unsuitable for use in establishing domestic normal values.
 - Designated Authority in the case of Rubber Chemicals from China and Korea (Case No.14/5/2007-DGAD) held that the prices of raw materials cannot be accepted as the same are not reflective of cost reasonably associated with the production.
 - The EC has amended the law to provide for such an eventuality, which indicates that such a methodology is WTO compliant. The EC has applied this rationale at least in a number of cases involving Russia and Kazakhstan wherein EC has rejected the procurement price of gas by the exporter from the local supplier on the ground that the cost for the purchase when compared to the export price of gas did not reasonably reflect the costs associated with the production.
 - In addition, the US authorities in their Chapter 8 of the AD Manual mentions that “a particular market situation might exist where there are such extensive government controls over pricing in a foreign market that prices in that market cannot be considered competitively set
68. The contentions of the Domestic Industry and the exporters regarding the determination of Normal values in respect of exporters/producers from Saudi Arabia have been examined. It is noted that there is no dispute about the fact that the feedstock prices in Saudi Arabia are priced considerably lower when they are sold for domestic consumption within Saudi Arabia as compared to the price at which they are exported from Saudi Arabia. Some of the producers/exporters have also admitted that prices of propane are lower than the prevailing international prices in their written submissions as well. However, it has been contended by some of them that the feedstock prices in Saudi Arabia are priced lower due to the inherent benefits such as cost savings in infrastructure; cost savings in marketing; commercial advantage associated with long-term contracts; commercial value of reduced volatility and commercial value of large-volume purchases. However, existence of the dual/differential pricing, and the fact that the domestic prices are considerably on lower side has remained undisputed. It has been vehemently argued by the Domestic Industry that any adjustments on account of the cost or price difference between the domestic and export markets have to be demonstrated with actual information in terms of paragraph 6(i) of Annexure I to the AD Rules or the Article 2.4 of the WTO Agreement on Anti-dumping. No adjustment can be allowed on the basis of mere statements and assertions. The Authority notes that none of the interested parties has provided any positive evidence to the Authority in support of their claim for such adjustments. Throughout the investigation as well as at the time of spot verification, the

exporters were given ample opportunity to identify reasons for such differences and quantify the same. However, the respondents concerned have not substantiated their submission regarding reasons of the price difference.

69. The Authority notes that none of the Saudi respondents have substantiated the claim with any evidence that the prices of propane in Saudi Arabia were determined on the basis of "negotiations between producer and consumers. Even a copy of the KSA Council of Ministers Resolution No.260 dated 7 January 2002 and Decision No.15 of the KSA Supreme Council for Petroleum Affairs has not been provided to enable the Authority to examine their claim. The Authority further notes that the prices of propane in the domestic market are significantly lower than its export prices. As mentioned earlier, the claims of the Saudi respondents that the price of propane in Saudi Arabia is lower on account of certain factors like transportation costs, infrastructure, marketing, long-term contracts, large volume purchases etc., have not been substantiated; despite opportunities provided. The Authority considers that any adjustment could have only been made, if the same was substantiated and quantified by the respondents from Saudi Arabia.
70. As regards the contention that it is no longer open to challenge the regulated pricing regime for NGLs, the Authority is of the view that there is no direct or even indirect suggestion in the Accession Protocol which restricts the powers or curtails the scope of investigation being conducted by the authorities under anti-dumping provisions. In any case, the Authority is required to give its findings in terms of the Indian laws having full regard to the WTO Agreement on Anti-dumping.
71. As regards the applicability and relevance of the practices and case laws, the Authority notes that the Australian Guidance on Market Situation lays down that the terms 'particular market situation' potentially cover a variety of situations including the situation where the domestic selling prices in the country of export have been materially affected by government influence rendering those prices unsuitable for use in establishing domestic normal values. As regards the contention that the Australian guidelines refer only to domestic prices and not to the costs, the Authority is of the view that such a reading is not borne out of the text of the said guidelines inasmuch as it is an admitted fact that the domestic prices of the subject goods are getting materially affected by the government administered prices of the major raw material.
72. It has further been submitted that the EC findings (Council Regulation No. 1050/2006 of 11th July 2006) in the case of Potassium Chloride from Belarus and Russia are in the context of countries which are not members of the WTO. The Authority notes that this argument is devoid of substance as there is no indication that the issues in question can be applied differentially between the WTO members and non-members. Moreover, the Indian laws do not make any such distinction in the context of the provisions in question.
73. With regard to the Authority's own decision in the case of Rubber Chemicals from China and Korea (Case No.14/5/2007-DGAD) it was held that the prices of raw materials cannot be accepted as the same are not reflective of cost reasonably associated with the production having been procured from non-market economy country and the Authority

instead used the market prices of the raw material for the determination of cost of production. The ratio of the above-cited decision is directly applicable to the facts and circumstances of this case as the basic rationale of the said decision was that if the cost in a market economy is not reflective of the true costs (for whatever reason), then the cost of such raw material prices can be rejected. The fact that the price has been rejected on account on the ground that the raw material was from a non-market economy country is of no consequence as the provision relating to NME treatment (para 7 of Annexure I of the AD Rules) is not applicable for a market economy like Korea RP.

74. In view of the aforesaid, the Authority is of the view that the above references have been correctly made in the context of 'particular Market situation'. Moreover, for the purposes of determining the Normal value, the Authority considers that it is obligated to examine whether the costs claimed to produce the product under consideration by the Saudi producers reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration. Axiomatically, the costs claimed to produce the product under consideration would include the prices of raw materials or other inputs used to produce the product under consideration. It is not disputed that prices of propane in Saudi Arabia are significantly lower than its export prices. No justification along with evidence has been provided by any Saudi respondent for such a difference. Thus, the Authority considers that a particular market situation exists in Saudi Arabia by virtue of which the prices of the subject goods cannot be stated to be competitively set, impacting the proper and fair determination of Normal values of the subject goods in Saudi Arabia.
75. It has been contended that the issue of dual pricing can be addressed only under the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. In this context, the Authority notes that the issue in the present case is not whether or not the price differential regime of KSA is a countervailable subsidy under the ASCM. The Authority is concerned with the scope of the express provisions of the WTO Agreement on Anti-dumping and the corresponding Rules under the Indian laws.
76. With regard to the scope of Article 2.2.1.1 (Para 1 of Annexure I of the AD Rules), it has been argued that there is no reason why records kept by the Saudi producers should be disregarded for the purpose of determining raw material cost actually incurred by the producers concerned for the production of polypropylene. In this context, the Authority is of the view that the limited and restricted interpretation proposed by the exporters and the Saudi Arabian government is not borne out from the plain reading as well as the jurisprudence on the subject. The relevant Articles and provisions of the Indian laws are reproduced below:

Article 2.2.1.1 of the Anti-dumping Agreement:

For the purpose of paragraph 2 of this Article, costs shall normally be calculated on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided that such records are in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country and reasonably reflect

the costs associated with the production and sale of the product under consideration.

Para 1 of Annexure I of the AD Rules :

The elements of costs referred to in the context of determination of normal value shall normally be determined on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided such records are in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country, and such records reasonably reflect the cost associated with production and sale of the article under consideration. (Emphasis added)

77. It is noted that the obligation under Article 2.2.1.1 or para 1 of Annexure I of the AD Rules is not absolute. The Panel on US — Lumber V [WT/DS264/R (Para 7.237)] took the following view:

"In our view, Article 2.2.1.1 imposes certain positive obligations on investigating authorities, including the obligation to calculate costs on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation and to consider all available evidence on the proper allocation of costs. Neither of these obligations is absolute, however, as in both cases the obligations apply only if ('provided') certain conditions are met. The role of these conditions is therefore not to impose positive obligations on Members, but to set forth the circumstances under which certain positive obligations do or do not apply. Thus, Article 2.2.1.1 does not in our view require that costs be calculated in accordance with GAAP nor that they reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration. Rather, it simply requires that costs be calculated on the basis of the exporter or producer's records, in so far as those records are in accordance with GAAP and reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration. Similarly, Article 2.2.1.1 does not require that all allocations made by an investigating authority have been historically utilised by the exporter or producer; rather it simply provides that investigating authorities must consider all available evidence on the proper allocation of costs, including that made available by respondents, insofar as such allocations have been historically utilised by the exporter or producer. Bearing this in mind, we shall examine Canada's arguments relating to Article 2.2.1.1."

78. The Panel on US — DRAMS [WT/DS99/R (Para 6.66)] addressed Korea's claim that the United States' authority had acted inconsistently with the first sentence of Article 2.2.1.1 by disregarding cost data which met with the two requirements set forth in the proviso of that Article, namely, "in accordance with generally accepted accounting principles" and "reasonably reflect costs".

79. In Egypt — Steel Rebar [WT/DS211/R (Para 7.393)] the Panel noted that both Articles 2.2.1.1 and 2.2.2 *"emphasize two elements, first, that cost of production is to be calculated based on the actual books and records maintained by the company in question so long as these are in keeping with generally accepted accounting principles but that second, the costs to be included are those that reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration"*. In view of the above, it is clear that the two requirements of the said Article have to be read in a disjunctive manner.
80. Because of existence of dual pricing policy prevailing in Saudi Arabia in respect of propane, the domestic selling prices of the subject goods cannot be considered as competitively set. It is seen that the cost of propane to the Saudi producers of the subject goods when compared to the export price of propane, does not reasonably reflect the costs associated with the production of the subject goods.
81. In respect of the claim of the domestic industry to treat Saudi Arabia as operating under Non-Market Economy conditions for the PUC, the authority is of the considered view that the claim of the domestic industry cannot be accepted as the ingredients of Para 7 and 8 of the Annex-1 of the Rules are not satisfied. However, in view of the above, the domestic costs and prices of the producers / exporters in Saudi Arabia cannot be accepted on their face value due to the 'particular market situation' prevailing there in the context of the Product under Consideration. And in view of the fact that the costs do not reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration. The Authority is of the considered view that any comparison based on such normal value would not be fair and proper.
82. Therefore, for conducting a fair and proper comparison, the Authority considered it appropriate to modify the cost of production in respect of Propane prices. After this modification, where the domestic selling prices are above the cost of production, the Normal value has been determined on the basis of the domestic selling price in the ordinary course of trade for the like article meant for consumption in the exporting country. However, where the domestic prices fall below the cost of production, the normal value has been determined in terms of the options provided under Section 9A (1) (c)(ii). In such cases, the Authority has resorted to its consistent practice to construct the Normal Value wherever the domestic prices were found not acceptable.

Methodology adopted for determination of Normal value

83. The Authority has determined individual dumping margin in respect of co-operative exporters / producers who have provided the requisite information. Besides the issue mentioned above regarding the determination of Normal value in respect of exporters/producers from Saudi Arabia, the general methodology adopted for determination of Normal value is as follows:

84. It was first seen, whether the domestic sales of the subject goods by the responding exporters/producers in their domestic markets were representative and viable for permitting determination of Normal values on the basis of their domestic selling prices and whether the ordinary course of trade test was satisfied as per the data provided by the respondents. Wherever the respondents have provided transaction-wise details of the sales of the like article in their home markets, the information so provided has been relied upon to determine the Normal value for the subject goods after carrying out the ordinary course of trade test and sufficiency test. Further, in view of the fact that there were significant fluctuations in the prices of the subject goods and raw materials within the POI; the Authority has computed the normal value on month-wise basis for each co-operative exporter/producer.
85. Wherever, there were no domestic sales or no sufficient domestic sales, the costs of production as claimed by the respondent and verified by the Authority have been accepted, subject to re-computation as stated in para 84 above. And where it was not feasible, the Normal value has been determined by the Authority on the basis of 'facts available' in terms of Rule 6(8) of the AD Rules.
86. Wherever the data in respect of homo-polymers and co-polymers was available on segregated basis, the analysis & determination of the dumping margins have been determined accordingly.

Normal Value

OMAN

M/s Oman Polypropylene LLC

87. OPP has contended that the Authority ought to reconsider its finding that loss making transactions are more than 20% of the total sales. It is submitted that the Authority is erring in thus determining normal value based on profitable sales and by excluding a large number of transactions as being loss-making. The Authority in so doing has failed to bear in mind that the changes in the cost of production in a given time period impact the question whether a transaction related to that time period is actually loss making or not. For example fluctuations in the cost of oil and related fluctuations in the cost of propylene from month to month during POI will have a bearing on the price of the product from month to month and whether the sales price of the product recovered the cost connected with it.
88. The issue raised has been examined and the Authority is of the view that considering fluctuations in the costs and prices of the subject goods during the POI, the normal value for the company has been correctly determined based on the monthly cost data provided by it.

89. The information/data filed by the respondent and verified has been relied upon for the determination of the Normal value. During the course of verification, the respondent claimed certain adjustments and the same were verified and accepted. The Authority has carried out the ordinary course of trade (OCT) test based on the month-wise cost details as provided in Appendix 8 of the response. It has been noted that the loss-making transactions in the POI were more than 20% of the total sales in the domestic market. Therefore, the Authority has proceeded to determine the Normal value based on the profitable sales in terms of the provisions of Annexure I of the AD Rules. The Normal value has been determined on a month-wise analysis of the data due to fluctuations in the prices of the subject goods during the POI.

Non-cooperative exporters/Producers

90. No other exporter and producer from Oman has responded to the Questionnaire. The Authority has determined their Normal value based on the facts available on record.

SAUDI ARABIA

M/s Advanced Polypropylene Co., Saudi Arabia

91. From the perusal of the response of the company it is seen that the subject goods produced by the company have been exported to India by M/s Vinmar International Limited and M/s Mitsubishi Corporation Singapore. However, only M/s Vinmar International Limited has filed the questionnaire's response and hence individual dumping margin has been determined only in respect of M/s Advanced Polypropylene Co., Saudi Arabia and M/s Vinmar International Limited.
92. During the course of the investigation, it was pointed out by the company that the name of the Company has been changed to Advanced Petrochemical Company in 2009, however, there was no accompanying change in ownership or management (Board of Directors) and no merger or acquisition was involved. The List of Shareholders and Directors was furnished. It was explained that SAGIA refers to the Industrial Investment License(s) of the Company, which also records the names of the major shareholders. The respective Articles/ Byelaws were also furnished with translation. The Company has separately filed an Attestation by its external Saudi Counsel, Dr. Waleed Al-Nuwaier, (with a copy of the License and its English translation), stating that the name change is in accordance with the provisions of Saudi Law and that the name change took place on 17th March 2009 and involved no accompanying changes in ownership or management. Supporting documents to this effect were also submitted and a copy of the same was placed in the public file. Accordingly, the Authority has taken the change in name of the company on record for the purposes of this investigation.
93. The information/data submitted by the company was examined and verified. A perusal of the company's response showed that the respondent had sold the off-spec material in the domestic market whereas the subject goods exported to India were of various grades. The details relating to off-spec material sold in the domestic market has been provided in

Appendix 1 of the response. Besides, it has been noted that the respondent has exported the subject goods to India during May 2008 till December 2008, whereas its domestic sales have been made only in November and December 2008 period. Considering the fact that the prices of petroleum products in general and as well as of the subject goods fell significantly during this period when the domestic sales were made; hence, the Authority considers that the domestic sale made by the respondent cannot be deemed as comparable and representative for the purposes of determination of the Normal value and dumping margin. It has been noted that the company has requested for monthly determination of the Normal Value due to high volatility in the POI. The same has been accepted and data has been analysed on a monthly basis.

94. In response to the Disclosure Statement, it has been contended by APPC that DGAD's decision not to use its domestic sales as a basis for normal value, that it has, throughout the investigation, underlined the fact that while "off-spec" products sold in the domestic market and the two grades exported to India have different chemical characteristics which would make them suitable for different types of applications, the production process for those different grades remains the same and the minor variations in the chemical composition of the product do not alter its fundamental nature, i.e. polypropylene. Thus, the Company maintains that the decision of DGAD to disregard the Company's domestic sales on that basis does not seem to be justified. Further, should the Authority confirm its methodology based on constructed normal value for APPC, the Company submits that, as a matter of fairness, additional adjustments should be operated to the normal value. Indeed, at the present, the Company's full cost of production used for the constructed normal value includes handling charges at the plant, which have been deducted from the export price. As a result, in order to operate a fair comparison between constructed normal value and export price, it is necessary to deduct the same from the constructed normal value. APPC has calculated that the amount of these handling charges, as reported in Appendix 1, represents 0.90% of the invoice value net of credit notes. The Company proposes to apply the same ratio as a deduction to the constructed normal value
95. The Authority is of the view that off spec material is priced lower than the standard material, which would not lead to a fair and proper comparison. Therefore, considering the facts of the case, the Authority is of the view that its decision to determine the normal value for the exporter on the basis of constructed cost is correct. However, as regards claim for the adjustment of 0.90% for handling the goods, the same has been accepted and the normal value and consequently the dumping margin have been re-computed accordingly.
96. The Authority has accordingly proceeded to construct the Normal value on the basis of the unit cost to make and sell as reported by them in Appendix 8 on a month-wise basis (subject to re-computation of the cost of production data as explained in para 84 of these findings) and has added profit margin @ 5%.

M/s Saudi Polyolefins Company (SPC)

97. M/s Saudi Polyolefins Company vide its letter dated 26.08.2009 has, inter alia, stated that due to an inadvertent mistake at their end, the name of one of the exporter of the subject goods manufactured by the SPC was wrongly mentioned and the same was also reflected in the preliminary finding. It has been pointed out that the correct name of the exporter is 'Basell International Trading FZE, Dubai' instead of 'Basell Polyolefins Company'. This claim has been substantiated by the Company by submitting a set of documents, a copy of which was also placed in the public file. Therefore, the Authority has rectified the name in these findings.
98. The questionnaire response submitted by SPC was perused and verified. It was found that the respondent has provided selling price details of the subject goods in relevant Appendixes of their response. The information/data filed by the company has been accepted subject to re-computation of the cost of production data as explained in para 84 of these findings. Accordingly, the Normal value has been determined after carrying out the OCT test. The adjustments as claimed by the exporter have been accepted. It is found that more than 20% of domestic transactions have been found to be loss making. Therefore, the normal value for the exporter has been determined on the basis of profit-making sales on a month-wise basis due to significant fluctuations in the prices of the subject goods during the POI. Wherever there were no profitable sales in a particular month, the normal value for that month has been constructed on the basis of the unit cost to make and sell and has added profit margin @ 5%.
99. It has been contended by Saudi Polyolefin Company that the Authority has not shared with them the price of Propane considered by the Authority for the purpose of computing cost of production for SPC. In the absence of the price of Propane, considered by the Authority for the purpose of construction of cost of production, they are not in a position to comment upon Normal Value considered by the Authority.
100. The Authority has given sufficient disclosure of the propane prices considered. The details relating to propane prices considered were also placed in the public file.
101. It has also been contended by Saudi Polyolefin Company that the data / submissions were based on the data as per the records of SPC. For instance, for a particular transaction if the Invoice was raised by SPC during the POI, the same was considered in the data even though the sale was executed by BIT or NPIMC after the POI. Similarly, if during the Period of Investigation, a particular transaction was executed for which an Invoice had been raised by SPC prior to Period of Investigation, such sales had been excluded from the submissions before the Authority. The Authority in the Disclosure Statement whilst computing dumping margin for SPC through BIT has excluded the transactions for which Invoice was raised by SPC in December, 2008 but the same were executed by BIT in January, 2009. It has been requested that these transactions be also considered for the purpose of computation of dumping margin for SPC through BIT.
102. The Authority is of the view that while computing dumping margin for SPC through BIT, it has correctly excluded the transactions for which Invoice was raised by SPC in December, 2008 but the same were executed by BIT in January, 2009, that is, post POI.

M/s Saudi European Petrochemical Company (IBN Zahr), Saudi Arabia through M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC)

103. It is seen that Ibn Zahr and Yanpet, the two manufacturers of polypropylene, are affiliates of SABIC. The polypropylene produced by both these producers is sold by SABIC, both in the domestic market and in the export market.
104. Both the producing companies transfer the polypropylene produced by them to SABIC and the transfer is recorded as sale at a provisional price. Since all the transfers are to SABIC within Kingdom of Saudi Arabia, the transaction is shown as one of domestic sales by these producing companies. From the actual final price charged by SABIC to the buyer, the expenses on account of logistic/distribution are deducted. The amount so arrived at is the FOB value. From the FOB value, 5%/6% is deducted as Marketing Fee of SABIC for marketing the goods. The FOB minus the marketing fee is called Net Back, which is then remitted to the producing affiliate.
105. It has been contended in response to the Disclosure statement that in arriving at the normal value for IBN Zahar, the Authority has ignored loss making sales for all those months even in the cases where the loss making sales of a month are lower than the 20% of the sales of that particular month and that such exclusion is contrary to para 2(i) of Annexure – I to the AD Rules. The sources of consumption norm and conversion cost from propylene to polypropylene have not been disclosed.
106. It has been further contended that the Authority has made double deductions towards logistics expenses for arriving at the normal value and requested for its correction. It is further contended by SABIC that for a fair comparison dumping margin is to be determined for those grades only which have been exported to India.
107. As regards the OCT test, the Authority notes that the same is required to be carried out in respect of total sales made in the POI. Therefore, wherever the loss making sales for the whole POI were more than 20% of the total sales, the normal value has been determined on the basis of the profit making sales. As regards the sources of the consumption norm and conversion cost from propylene to polypropylene, the same are based on the response of other cooperative producers. The Authority has re-computed normal value and the dumping margin, taking into account the submissions provided by the company in respect of logistic expenses. As regards the contention that for a fair comparison dumping margin is to be determined for those grades only which have been exported to India, it is noted that the producer has not submitted grade-wise costing data to carry out the OCT test and hence the Authority is constrained to determine the dumping margin on the basis of information/data provided.
108. The information/data filed by the respondents has accordingly been examined. The same has been accepted subject to re-computation of the cost of production data as explained in para 84 of these findings. The adjustments claimed by the exporter have been accepted and an adjustment for credit cost was also made as the sales in the domestic market were

on credit. Accordingly, the Normal value has been determined after carrying out the OCT test. It is found that more than 20% of domestic transactions have been found to be loss making. Therefore, the normal value for the exporter has been determined on the basis of profit making sales on a month-wise basis due to significant fluctuations in the prices of the subject goods during the POI. Wherever there were no profitable sales in a particular month, the normal value for that month has been constructed on the basis of the unit cost to make and sell (subject to re-computation of the cost of production data as explained in para 84 of these findings) and profit margin @ 5% has been added.

M/s Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet), Saudi Arabia through M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC)

109. SABIC's response was perused and it was noted that SABIC sells the subject goods produced by two related entities namely, M/s IBN ZAHR and M/s YANPET. Initially, the respondent had provided details only in the Appendixes 1 & 2, 3A and 3B and subsequently the other details have been provided in respect of other appendixes viz. Appendixes 4-9. It is also seen that M/s Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet) sells the subject goods in the domestic market only through M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC). However, the subject goods produced by it have been exported to India by M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC) and as well as by M/s Exxon Mobil Chemical Asia Pacific, Saudi Arabia.
110. It has been contended in response to the Disclosure statement that in arriving at the normal value for Yanpet, the Authority has ignored loss making sales for all those months even in the cases where the loss making sales of a month are lower than the 20% of the sales of that particular month and that such exclusion is contrary to para 2(i) of Annexure – I to the AD Rules. The sources of consumption norm and conversion cost from propylene to polypropylene have not been disclosed.
111. It has been further contended that the Authority has made double deductions towards logistics expenses for arriving at the normal value and requested for its correction. It is further contended by SABIC that for a fair comparison dumping margin is to be determined for those grades only which have been exported to India.
112. As regards the OCT test, the Authority notes that the same is required to be carried out in respect of total sales made in the POI. Therefore, wherever the loss making sales for the whole POI were more than 20% of the total sales, the normal value has been determined on the basis of the profit making sales. As regards the sources of the consumption norm and conversion cost from propylene to polypropylene, the same are based on the response of other cooperative producers. The Authority has re-computed normal value and the dumping margin, taking into account the submissions provided by the company in respect of logistic expenses. As regards the contention that for a fair comparison dumping margin is to be determined for those grades only which have been exported to India, it is noted that the producer has not submitted grade-wise costing data to carry out the OCT test and hence the Authority is constrained to determine the dumping margin on the basis of information/data provided.

113. The information/data filed by the respondents was accordingly examined and the same has been accepted subject to re-computation of the cost of production data as explained in para 84 of these findings. The adjustments claimed by the exporter have been accepted and an adjustment for credit cost was also made as the sales in the domestic market were on credit. Accordingly, the Normal value has been determined after carrying out the OCT test. It is found that more than 20% of domestic transactions have been found to be loss making. Therefore, the normal value for the exporter has been determined on the basis of profit-making sales on a month-wise basis due to significant fluctuations in the prices of the subject goods during the POI. Wherever there were no profitable sales in a particular month, the normal value for that month has been constructed on the basis of the unit cost to make and sell (subject to re-computation of the cost of production data as explained in para 84 of these findings) and profit margin @ 5% has been added.

M/s Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet), Saudi Arabia through M/s Exxon Mobil Chemical Asia Pacific, Saudi Arabia.

114. It is seen that M/s Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet) sells the subject goods in the domestic market only through M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC). However, the subject goods produced by it have been exported to India by M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC) and as well as by M/s Exxon Mobil Chemical Asia Pacific, Saudi Arabia.
115. As the domestic sales have been effected only by SABIC, the same Normal value has been adopted for comparing the Export price of M/s Exxon Mobil Chemical Asia Pacific, Saudi Arabia for the purposes of determination of the dumping margin.

Non-cooperative exporters/Producers

116. No other exporter and producer from Saudi Arabia has responded to the Questionnaire. The Authority has determined their Normal value based on the facts available on record.

SINGAPORE

M/s The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. (TPC)

117. The information/data provided by the company was examined and verified. It is noted that the company has not directly exported the subject goods to India during the POI. However, the subject goods produced by the company have been exported to India during the POI by the following companies:
1. M/s Itochu Plastics Pte. Ltd., Singapore
 2. M/s Marubeni Chemical Asia Pacific PTE Ltd., Singapore
 3. M/s Sumitomo Corporation Asia Pte Ltd., Singapore
 4. M/s Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd., Singapore
 5. M/s Toyota Tsusho (Singapore) Pte Ltd., Singapore

6. M/s Inabata Singapore Private Limited

118. All these exporters have provided information in the exporter's questionnaire except M/s Inabata which has provided the information very late. Despite the delayed response, the information/data filed by the exporter was examined. It was noted in the Disclosure statement that M/s Inabata has not exported the subject goods in commercial quantities and that M/s Inabata has not made any domestic sales of the particular grades of the subject goods exported by them. It was further understood that M/s Inabata further processes the goods after obtaining the same from TPC. TPC has also not provided the data in respect of the relevant grades in their Appendix 8B of the response.
119. It has been contended by Inabata that export of non-commercial quantity during the POI is no ground for discarding the issues raised by Inabata as the levy of anti-dumping duty (if levied at all) would not just affect the previous export but also the future exports of Inabata as well. Therefore, it is relevant and important to show, if Inabata has dumped their products and as a result requires any anti-dumping duty. To further substantiate the stand taken by Inabata, their supplier TPC has issued a testimony, whereby they have categorically mentioned that Inabata has not done any further processing on the goods supplied by TPC for trading purposed.
120. The Authority notes that as per the export details provided by TPC in Appendix 2, there are only 3 transactions which have been exported through Inabata whereas there are 5 transactions reflected in the Appendix 2 provided by Inabata. The two shipments reportedly made by Inabata in September 2008 and November 2008 are not reflected in TPC's data; thus the exports to India as reported by TPC and Inabata do not reconcile. In the absence of reconciliation between the exports to India reported by them, the Authority cannot also determine a separate export price for Inabata and dumping margin.
121. Besides, it is also noted that though TPC had sold the subject goods to M/s Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd. in Singapore but M/s Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd. in turn has exported some of the quantity of the subject goods so procured from TPC to India without the prior knowledge of TPC.
122. A perusal of the data of TPC shows that no grade-wise costing details have been provided by the company, however the same has been provided on a month-wise basis. Therefore, for carrying out the OCT test, the data as provided by the company in respect of homo-polymers and co-polymers have been adopted. It is seen from the data that the loss-making sales for homo-polymers and co-polymers are ***% and ***% respectively and for the PUC as a whole the loss-making sales are about ***%. Therefore, only profitable domestic sales have been considered for determining the normal value.
123. It is also noted that TPC has also stated in its response that it sells to unrelated parties except M/s Sumitomo Chemical Asia Pte. Ltd. Therefore, the sales prices to M/s Sumitomo Chemical were examined vis a vis the sales prices to unrelated parties. No significant difference is found between such sales and sales made to unrelated parties.

Therefore, all profitable sales made by TPC in its domestic market have been considered for the purpose of determination of normal value.

124. The adjustments have been made for freight, commission and bank charges as claimed and verified by the Authority. As stated above, the normal value has been determined on a month-wise basis due to significant fluctuations in the prices of the subject goods during the POI.

M/s ExxonMobil Chemical Asia Pacific, Singapore

125. It is noted that the company besides directly exporting the PUC to India exports the subject goods through M/s Mitsubishi Chemical Thailand (Co.) Ltd. as well.
126. The data provided by the company was examined and verified. It is noted that the company has not provided the details for the domestic sales in Appendix 1, inter alia, stating that it sells less than 5% of the export sales to India. Therefore, it claimed that its normal value should be determined based on third country information. It is, however, noted that the discretion regarding the option to choose the method for determination of normal value does not lie with the producer/exporter, in case the Normal value's determination cannot be made on the basis of domestic sales transactions. Under such a situation, the choice lies with the Authority as to how the normal value is to be determined. Therefore, it is considered appropriate to construct the Normal value for the exporter on the basis of construction method viz. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits.
127. It is seen that the company has also not provided any separate cost details for homo-polymers and co-polymers. Therefore, the normal value for the exporter has been constructed based on the cost of production details as provided in Appendix 8B after adding 5% profit to it. The normal value has been determined on a month-wise basis due to significant fluctuations in the prices of the subject goods during the POI.

Non-cooperative exporters/Producers

128. No other exporter and producer from Singapore has responded to the Questionnaire. The Authority has determined their Normal value based on the facts available on record.

Export Price:

OMAN

M/s Oman Polypropylene LLC

129. The information/data filed by the company was verified and has been accepted for determination of the export price. The exporter has claimed adjustments on account of

commission, service charge and transportation and the same have been accepted. The Export price has been so determined on a month-wise analysis of the data.

Non-cooperative exporters/Producers

130. No other exporter and producer from Oman has responded to the Questionnaire. The Authority has determined their Export price based on the facts available on record.

SAUDIA ARABIA

M/s Advanced Polypropylene Co., Saudi Arabia through M/s Vinmar International Ltd., USA

131. The information/data filed by the respondents was verified in Saudi Arabia and has been accepted for determination of the export price. The adjustments have been claimed on account of ocean freight, insurance, finance charges and marketing fee and the same have been accepted. The Export price has been so determined on a month-wise analysis of the data.

M/s Saudi Polyolefins Company through M/s National Petrochemical Industrialization Marketing Company, Saudi Arabia

132. The information/data filed by the respondents was verified and has been accepted for determination of the export price. The respondents have claimed adjustments on account of inland freight, overseas freight, clearance & handling charges and Credit Cost and the same have been accepted. The Export price has been so determined on a month-wise analysis of the data.

M/s Saudi Polyolefins Company through M/s Basell International Trading FZE,

133. The information/data filed by the respondents was verified and has been accepted for determination of the export price. The respondents have claimed adjustments on account of inland freight, overseas freight, clearance & handling charges and credit cost and the same have been accepted. The Export price has been so determined on a month-wise analysis of the data.

M/s Saudi European Petrochemical Company (IBN Zahr), Saudi Arabia through M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC)

134. A perusal of SABIC response shows that sales to Bhutan and Nepal were also indicated against India, since all these consignments were routed through the Haldia / Kolkata Port. The bills of lading in respect of export to Bhutan and Nepal clearly showed that the goods were meant for these countries as the final destination and were in transit to these

countries through Haldia /Kolkata Port. Hence, the transactions in respect of export to Bhutan and Nepal have not been considered for determination of the export price.

135. It has been contended by SABIC in response to the Disclosure statement that the Authority has made double deductions towards logistics expenses for arriving at the export price and requested for its correction. It is further contended by SABIC that for a fair comparison dumping margin is to be determined for those grades only which have been exported to India.
136. The Authority has re-computed export price and the dumping margin, taking into account the submissions provided by the company in respect of logistic expenses. As regards the contention that for a fair comparison dumping margin is to be determined for those grades only which have been exported to India, it is noted that the two producers of SABIC have not submitted grade-wise costing data to carry out the Ordinary Course of Trade test and hence the Authority is constrained to determine the dumping margin on the basis of information/data provided.
137. Thus, the information/data filed by the respondents as verified, has been accepted for determination of the export price. The adjustments for expenses such as ocean freight, insurance, bank charges, clearance expenses etc. have been allowed. It was noted that even though the payment terms were on credit basis, no deduction had been made for the cost of credit in Appendix-2. Thus, in order to make this deduction, the rate of interest on short-term borrowing as obtained during the verification in Saudi Riyal and US\$, for the period of investigation has been used to make necessary amendments to Appendix-2. The Export price has been so determined on a month-wise analysis of the data.

M/s Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet), Saudi Arabia through M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC).

138. A perusal of SABIC response shows that sales to Bhutan and Nepal were also indicated against India, since all these consignments were routed through the Haldia / Kolkata Port. The bills of lading in respect of export to Bhutan and Nepal clearly showed that the goods were meant for these countries as the final destination and were in transit to these countries through Haldia /Kolkata Port. Hence, the transactions in respect of export to Bhutan and Nepal have not been considered for determination of the export price.
139. The information/data filed by the respondents was verified and has been accepted for determination of the export price. The adjustments for expenses such as ocean freight, insurance, bank charges, clearance expenses etc. have been allowed. It was noted that even though the payment terms were on credit basis, no deduction had been made for the cost of credit in Appendix-2. Thus, in order to make this deduction, the rate of interest on short-term borrowing as obtained during the verification in Saudi Riyal and US\$, for the period of investigation has been used to make necessary amendments to Appendix-2. The Export price has been so determined on a month-wise analysis of the data.

M/s Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet), Saudi Arabia through M/s Exxon Mobil Chemical Asia Pacific, Saudi Arabia

140. The information/data filed by the respondents has been accepted for determination of the export price. The Export price has been so determined on a month-wise analysis of the data.

Non-cooperative exporters/Producers

141. No other exporter and producer from Saudi Arabia has responded to the Questionnaire. The Authority has determined their Export price based on the facts available on record.

SINGAPORE

M/s The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. (TPC) through M/s Itochu Plastics Pte. Ltd.

142. The information/data filed by the company was verified and has been accepted for determination of the export price. The adjustments for commission and interest as claimed by the exporter in Appendix 2 and verified by the Authority have been allowed. The other adjustments for packing, inland freight, insurance, storage, handling, overseas freight, overseas insurance and shipping charges verified from TPC response have also been made. The Export price has been so determined on a month-wise analysis of the data.

M/s The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. (TPC) through M/s Marubeni Chemical Asia Pacific PTE Ltd., Singapore

143. The information/data filed by the company was verified and has been accepted for determination of the export price. The adjustments for packing, inland freight, insurance, storage, handling, overseas freight, overseas insurance and shipping charges verified from TPC response have been made. The Export price has been so determined on a month-wise analysis of the data.

M/s The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. (TPC) through M/s Sumitomo Corporation Asia Pte Ltd., Singapore

144. The submissions regarding exclusion of Ter-polymer from the analysis have been accepted. Accordingly, the information/data filed by the company has been accepted for determination of the export price. The adjustments for commission, interest and bank charges have been claimed by the exporter in Appendix 2 and the same are allowed. The other adjustments for packing, inland freight, insurance, storage, handling, overseas freight, overseas insurance and shipping charges verified from TPC response have also been made. The Export price has been so determined on a month-wise analysis of the data.

M/s The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. (TPC) through M/s Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd., Singapore

145. It has been stated by the exporter that, it appears from the confidential disclosure statement that certain homo-polymers have been wrongly considered as co-polymers and that grades such as FS3011E, FS2011E, FY2011ER, and Y101E, have been considered to be co-polymers, whereas these grades are homo-polymers. The Authority has accepted the claims made by the exporter and recomputed the export price accordingly.
146. The information/data filed by the company has been accepted for determination of the export price. The adjustments for inland freight, storage, documentation, overseas freight, and overseas insurance have been claimed by the exporter and the same have been allowed. The Export price has been so determined on a month-wise analysis of the data.

M/s The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. (TPC) through M/s Toyota Tsusho (Singapore) Pte. Ltd. (TTSPL)

147. It has been contended by TTSPL that the sales of TTSPL for export to India, were against long term contracts, whereas sales of TPC in the domestic Singapore Market were on spot prices and that during the period of investigation, for April to September 2008, the prices were fixed based on the prevailing prices in the previous 6 months, as per the Platt's Price List. Similarly, for the period October to March, 2008, they were fixed on the basis of prevailing prices, in July to September, 2008. By undertaking a weighted month to month comparison, artificial margins of dumping and injury, are created. The comparison at best can be done either with the weighted averages for the entire period, as has been done in many cases by the Authority, and also in the preliminary findings, or on the basis of the weighted averages for the period April – September 2008 and October – December, 2008, respectively. TTSPL submits that there is no justification, for the proposed change in the methodology adopted for determination of the dumping and injury margin in the preliminary finding.
148. The Authority has taken note of the submissions of the TTSPL that the sales of TTSPL for export to India, were against long term contracts, whereas sales of TPC in the domestic Singapore Market were on spot prices.
149. In view of the above, the Export price has been determined on the basis of claims of long term contracts while exporting the subject goods to India during the POI. The information/data filed by the company has been accepted for determination of the export price. The adjustments for packing, inland freight, insurance, storage, handling, overseas freight, overseas insurance and shipping charges verified from TPC response have also been made to arrive at the net adjusted export price.

M/s ExxonMobil Chemical Asia Pacific, Singapore

150. It has been contended by EMCAP Singapore that for the calculation of the export price, the transactions have been grouped based on the order date, instead of the date of shipment. EMCAP believes that for a fair comparison, the monthly export price should be determined with regard to the date of export or date of shipment and not the order date.
151. The Authority notes that in terms of the anti-dumping provisions; normally, the date of sale would be the date of contract, purchase order, order confirmation, or invoice, whichever establishes the material terms of sale. During the verification also, the date of invoice was considered as establishing the material terms of sale. Besides, the company has not established and substantiated that the date of the shipment establishes the material terms of sale. Thus, Authority is of the view that the export price and the dumping margin calculations have been correctly determined.
152. The information/data filed by the company was verified and has been accepted for determination of the export price. The adjustments for expenses such as packing, commission and overseas freight claimed have been allowed. The Export price has been so determined on a month-wise analysis of the data.

M/s ExxonMobil Chemical Asia Pacific, Singapore through M/s Mitsubishi Chemical Thailand (Co.) Ltd.

153. The response filed by the company was examined. The response of the exporter could not be fully verified due to turmoil in Thailand. Therefore, the information filed and to the extent verified has been considered. The adjustments for expenses such as packing, commission and overseas freight from the response of ExxonMobil have been considered. The Export price has been so determined on a month-wise analysis of the data.

Non-cooperative exporters/Producers

154. No other exporter and producer from Singapore has responded to the Questionnaire. The Authority has determined their Export price based on the facts available on record.

H. DUMPING MARGIN

155. Considering the Normal values and Export prices as determined above, the dumping margins have been determined as follows:

Name	Country	Dumping Margin	
		USD / MT	%
M/s Oman Polypropylene LLC	Oman	***	21.49%

Non-cooperative Producers and Exporters	Oman	***	36.90%
M/s The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. (TPC) through M/s Sumitomo Corporation Asia Pte. Ltd.	Singapore	***	14.42%
M/s The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. (TPC) through M/s Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd., Singapore	Singapore	***	17.33%
M/s The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. (TPC) through M/s Toyota Tsusho (Singapore) Pte. Ltd.	Singapore	***	22.79%
M/s The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. (TPC) through M/s Marubeni Chemical Asia Pacific Pte. Ltd.	Singapore	***	9.93%
M/s The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. (TPC) through M/s Itochu Plastics Pte. Ltd.	Singapore	***	24.56%
M/s Exxon Mobil Chemical Asia Pacific, Singapore	Singapore	***	13.39%
M/s Exxon Mobil Chemical Asia Pacific, Singapore through M/s Mitsubishi Chemical Thailand (Co.) Ltd.	Singapore	***	9.00%
Non-cooperative Producers and Exporters	Singapore	***	43.06%
M/s Advanced Polypropylene Co.Saudi Arabia through M/s Vinmar International Ltd., USA	Saudi Arabia	***	20.92%
M/s Saudi European Petrochemical Company (IBN Zahr), Saudi Arabia through M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC)	Saudi Arabia	***	20.45%
M/S Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet) through M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC)	Saudi Arabia	***	6.37%
M/S Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet) through M/s Exxon Mobil Chemical Asia Pacific, Saudi Arabia	Saudi Arabia	***	16.30%
M/s Saudi Polyolefins Company through M/s National Petrochemical Industrialization Marketing Company, Saudi Arabia	Saudi Arabia	***	7.01%
M/s Saudi Polyolefins Company through Basell International Trading FZE, Dubai	Saudi Arabia	***	4.00%

Non-cooperative Producers and Exporters	Saudi Arabia	***	39.42%
-----------------------------------------	--------------	-----	--------

I. Injury

Submissions made by the interested parties

156. The submissions made by the exporters/importers and other interested parties are summarized as follows to the extent they have been found to be relevant. It has been, inter alia, stated that:

- (i) The market share of the Indian industry has increased from 91.34% in 2005-06 to 92.16% during POI. Hence, it cannot be said that the imports from the subject countries have taken over the entire increase in demand and the fall in domestic industry market share is due to the increase in imports.
- (ii) Domestic industry has claimed that the capacity utilization has come down over the injury investigation period due to the severely dumped imports from subject countries. In this regard, it should be noted that the Reliance Industries Ltd. has informed BSE India that it has closed some of its polyester plants for routine maintenance and enhancing product capabilities during the month of Nov'08 and repair for approximately four weeks. Due to this, the capacity utilization has come down during the period of investigation.
- (iii) The domestic industry has claimed that it has suffered loss during the Oct-Dec'08 as compared to the April-June '08 due to the increase in the imports. In this regard, it should be noted that the Reliance Industries has informed that its Patalganga site had announced a voluntary retirement scheme on October 05, 2008 as part of its normal cost optimization exercise and over 400 people had opted for the same.
- (iv) There is no fall in the sales value as well as volume during the period of investigation as sales volume has increased from 100 indexed units in 2005-06 to 131 indexed annualized units in 2008-09. An analysis of the increase in the sales quantity and sales value indicates that the sales realization per MT has also increased as increase in sales value is more than the increase in sales volume.

- (v) The Applicant admits that there is no negative impact on the number of employees and wages paid to them over the injury investigation period. Thus, there is no adverse impact on this factor also.
- (vi) The Hon'ble Authority has itself, in the preliminary finding, concluded that during the period of investigation the demand of the subject goods has increased and despite the same, the market share of the imports have fallen vis-à-vis the previous years i.e. from 6.4% to 5.8%. Further, the Hon'ble Authority in its finding has come to the conclusion that sales volume, cash flow, employment and wages, productivity of the Domestic Industry has improved during the period of investigation.
- (vii) Injury, if any, to the domestic industry is self-inflicted and is not caused due to import of the subject goods from the subject countries. It is pertinent to note that for one month during the POI (9 months) the Domestic Industry resorted to planned shutdown. This shut down was to increase the capacity to meet the difference between total demand and total domestic production. Any loss of business caused to the domestic industry as a result of the planned shut down is solely due to the acts of the domestic industry and the imports of the alleged dumped goods cannot be held responsible for the same.
- (viii) Injury, if any to the domestic industry during the period of investigation was temporary in nature which does not justify imposition of definitive anti-dumping duty against the import. During the period of investigation due to global slowdown and due to variation in the prices of crude, the producers and marketers of the subject goods were adversely affected world over.
- (ix) Imports of the subject goods are inevitable to meet the entire demand. It is submitted that even at 100% capacity utilization, the domestic industry would fail to cater to the total demand in the market. Therefore, imposition of anti dumping duty is not in the interest of domestic consumers.

Submissions made by the domestic industry

157. The domestic industry has stated the following:

- (i) As regards the issue of Market Share, the interested parties have failed to appreciate that the Domestic Industry has filed the application exactly in the prescribed format and the submissions with regard to the injury are also in line with the legal provisions with regard to injury analysis. The

Domestic Industry has submitted that its market share has declined. It has not been their claim that the share has declined after taking into account the sales of the other producer. The allegation of making false and misleading claims is, therefore, baseless. Besides, the market share movement in either case (i.e., after or before including the entire domestic producers) is not very significant on the basis of the data available to the Domestic Industry in public domain.

- (ii) As regards the submission of the interested parties that the output and capacity utilization has come down due to the planned shutdown at RIL, it has been submitted that:
- a) The shutdown was only at the Jamnagar complex whereas RIL has as many as five production facilities.
 - b) The month-wise inventory position of the product under consideration shows that the inventories had gone up from *** MT in April 2008 to *** MT at the end of September 2008, which further rose to *** MT at the end of October 2008. Thus, there was an increase in the closing stocks of more than two times from April to October 2008.
 - c) The rise in the inventories led to serious practical problems in storing their goods in as much as there was a paucity of physical space for storage of goods on account of the increased imports on dumped prices. It was in this context that a planned shutdown was advanced as RIL was unable to sell the product in the domestic market due to surge in imports at dumped prices.
 - d) As regards the contention of the interested parties that the loss was on account of the "planned" shutdown, it is submitted that the number of days which can be attributed to a maintenance shutdown is less than one day. As explained above, the shutdown for the rest of the period was necessitated due to a huge and unmanageable build-up of inventories at Jamnagar complex. In support of their contention that the number of days of shutdown attributable to planned maintenance, the details of the planned maintenance shut down over the years needs to be seen.
 - e) The typical maintenance shut down over the years has been less than 7 days spread over the full year which can be easily verified by the Authority from the detailed daily records being maintained in their plants. Therefore, the contention that the production and capacity utilization has suffered on account of the planned shutdown is completely misplaced. It is apparent from the records that the shutdown was on account of the burgeoning inventories and the dumped imports.
- (iii) As regards the Voluntary Retirement Scheme at Patalganga, it is submitted that the contention of the interested parties is baseless as no Polypropylene is produced in the Patalganga complex and the costs associated with the

voluntary retirement scheme, howsoever small, are also not connected with the production of the subject goods i.e., Polypropylene.

- (iv) As regards the sales volume and sales value, price effect and the claim of the Domestic Industry that prices have not increased commensurate to the increase in the costs, the Domestic Industry has submitted that the interested parties have analyzed the indexed numbers to arrive at some self-serving conclusions. The actual numbers given by the Domestic Industry in their application clearly prove the point of the Domestic Industry that the increase in costs has not been covered by the increase in prices during the period of investigation.
- (v) As regards the inventories, it has been submitted that they have provided the basic information in Proforma IVA as per the prescribed format which calls for the point to point information on stocks. The monthly stocks position of the Domestic Industry given along with the Part VI information clearly demonstrates that the inventories of the Domestic Industry rose to an unprecedented level during the months of September and October and thereafter the stock level came down after the Domestic Industry had no option but to liquidate their stocks at loss. This fact is clearly reflected in the financial performance of the Domestic Industry which shows that the Domestic Industry had suffered losses during October-December 2008 as compared to the period April-September 2008.
- (vi) The information on the profitability provided in the table on page 14 is consistent with the Proforma IV A.

Submissions made by Interested parties in response to the Disclosure Statement

- 158. It has been contended that the adoption of 22% Threshold ROCE would be unreasonable, inconsistent with market realities, and would unfairly place the domestic industry in a position better than if there was no dumping. It is further submitted that the threshold ROCE should be fixed based on industry norms and / or on historical levels of return on capital employed taking into consideration the economic peculiarities prevailing during the POI.
- 159. It has been contended that there is no injury caused to the domestic industry. The same is evident from the fact that the Authority has itself concluded that during the period of investigation the demand of the product under consideration has increased significantly (32%) and despite the said increase in the demand, the market share of the imports remains almost the same and the majority of the market share is controlled by the Domestic Industry (73%). Market share of the other domestic producers has increased significantly i.e. from 39% to 92%, which makes it evident that injury, if any, to the domestic industry is not on account of imports of the subject goods but is on account of increasing competition from other domestic producers. Further, the sales volume (increase by 20%), employment and wages (increase of 8%), productivity per employee

(increase by 27%), Inventory (decreased by 27%) of the Domestic Industry has improved during the period of Investigation. All these clearly establish that there is no injury caused to the Domestic Industry as alleged or at all.

160. Injury, if any, caused to the domestic industry is not because of any alleged dumped imports of the subject goods from the subject countries but is self inflicted. There is no causal link. It is pertinent to note that for one month during the POI (9 months) the Domestic Industry resorted to planned shutdown. This shut down was to increase the capacity to meet the difference between total demand and total domestic production. Any loss of business caused to the domestic injury as a result of the planned shut-down and solely due to the acts of the Domestic Industry and the imports of the alleged dumped goods cannot be held responsible for the same.
161. During the period of investigation, due to global slowdown variation in the prices of crude; the producers and marketers of the subject goods were adversely affected world over. Crude prices have ranged from US \$ 147/ barrel to US \$ 40/barrel in 2008. Crude derivative, Propylene makes up more than 3/4th of the cost of production. Hence, manufacturers had to first dispose off the higher value raw material. The cost of production was higher despite the reduction in the crude prices. Further, the price realizable from the market also went down for some time. However, the same has shown an upward trend once crude prices have settled. The said adverse impact on the sales and price of the subject goods was not restricted solely to the domestic industry. This clearly established that injury, if any, to the domestic industry was temporary in nature and would not justify imposition of the definitive anti dumping duty for a period of five years on the imports of the subject goods. This would adversely affect the other domestic producers and marketers of the subject goods in India. The domestic industry has willfully chosen the period of investigation for the purposes of the present investigation to mislead the Authority.
162. The imports of the subject goods are inevitable to meet the entire domestic demand. It is submitted that even at 100% capacity utilization, the domestic industry would fail to cater to the total demand in the market for the product under consideration. The incapability of the Domestic Industry to cater to the total domestic demand is further aggravated by the fact that M/s Reliance Industries Ltd., a significant component of the DI, being an EOU during the POI, was mandated to export substantial quantity and had been actually exporting substantial quantity of the subject goods.
163. An end point to end point comparison in determination of injury parameters is not only unreasonable but is also inconsistent with WTO law.

Examination by the Authority

164. The Authority has taken note of submissions made by various interested parties and have undertaken the injury analysis as under:
165. As regards the issue of adoption of 22% Threshold ROCE, the Authority notes that the return of 22% on capital employed (considering net fixed assets) is appropriate and has consistently been followed by the Authority. The Authority further notes that the domestic industry had earned as high as 35% return on capital employed. However, the Authority to be fair has restricted the return on capital employed to 22%.
166. Considering wide fluctuations in the raw material prices and the prices of the subject goods, the Authority has carried out month-wise analysis.
167. The Authority is of the view that the purpose of the levy of the anti-dumping duty is not to thwart imports but to restore conditions of fair trade. Besides, the Authority does not find any merit in the concerns expressed by the interested parties as regards inability of the domestic industry to meet the demand of the subject goods in the country as the same is not mandated under the law. Further, the Authority notes that the exports made by the domestic industry are of no consequence as the injury analysis in the present investigation has been restricted to the domestic operations.
168. A careful perusal of the findings would show that the analysis has been undertaken for the injury investigation period and the Authority also examined the changes in the POI in comparison to recent years.

Cumulative assessment

169. Attention is invited to Annexure II para (iii) of the AD Rules which provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -
- a. the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively accounts for more than seven percent of the import of like article and
 - b. cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

170. The Authority observes that

- i. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the limits prescribed above;
 - ii. The volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;
 - iii. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. This is evident from the fact that the domestic product and imported product are like Article; imports from each of the subject countries are above the prescribed *de-minimis* limits ; the goods produced by the Indian Producers and the subject goods imported from the subject countries are in direct competition; common parties are resorting to use of imported material and domestic material; Indian Producers' customers are using the domestic material and imported material interchangeably; the exporters from the subject countries and the applicant have sold the same product in the same periods to the same set of customers, etc.
171. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from the subject countries.
172. Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such product. While examining the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
173. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows.

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments."

Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic industry

174. The details relating to imports from all the subject countries and other countries are given below in the following table:

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	POI- Annuali zed
Imports from Subject Countries (MT)	61493	70164	110227	103677
Imports (Other Countries) MT	40242	42718	66966	35033
Total Imports (MT)	101735	112882	177193	138711
% Share of Subject countries	60%	62%	62%	75%
Trend in imports from subject countries	100	114	179	169
Year-by-Year change (%)		14	57	-6
Trend in Imports from other countries	100	106	166	87
Year-by-Year change (%)		6	57	-48
Trend in total Imports	100	111	174	136
Year-by-Year change (%)		11	57	(22)
Total Demand (MT)	1327308	1525077	1745061	1766985
% Share of Subject Countries in demand	5%	5%	6%	6%

175. It is noted that the imports from the subject countries in absolute terms have increased from 100 (2005-06) to 169 in POI over the injury investigation period. At the same time, the imports from other countries have declined from 100 in the base year to 87 in the period of investigation. The imports in relation to total demand in India have also increased over the injury investigation period particularly during POI from 5% in the base year to 6% in POI.

Demand and Market share

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	POI- Annualized
Domestic Industry Sales (MT)	983572	1163196	1310868	1285607

Sales of Other Domestic Producer	242000	249000	257000	342667
Total Domestic Sales in India (MT)	1225572	1412196	1567868	1628274
Imports from Subject Countries (MT)	61493	70164	110227	103677
Imports from Other Countries (MT)	40242	42718	66966	35033
Total Imports (MT)	101735	112882	177193	138711
Total Demand (MT)	1327308	1525077	1745061	1766985
Domestic Industry's Market Share in demand	74%	76%	75%	73%
Market Share of Total Domestic Sales in demand	92%	93%	90%	92%
% Share of Subject Countries in demand	5%	5%	6%	6%

176. The Authority notes that there are only two known producers of the like articles in the country, one of whom is the applicant (the domestic industry). The trends in the sales of the domestic industry were rising till 2007-08 but fell during the POI. However, the demand for product under consideration went up nearly by 33% over the base year. The market share of the imports from the subject countries in total demand has gradually increased from 5% to 6%.

Capacity, production & capacity utilization

177. The details for the capacity and production for the injury investigation period are given in the following table

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	POI- Annualized
Capacity (MT)	1400000	1700000	1700000	1725000
Production (MT)	1285511	1639199	1710002	1517688
Capacity Utilization%	92%	96%	101%	88%

178. It is noted that the capacity utilization of the domestic industry was rising till 2007-08 when it was able to use full capacity but it fell drastically during POI i.e. from 101% (2007-08) to 88%. In short, capacity utilization of the domestic industry during POI has come down as compared to both the base year (2005-06) and as well as previous year primarily due to the plant shut down at Jamnagar.

179. However, the domestic industry has claimed that the plant was primarily shut down on account of burgeoning inventory levels during the months of September and October 2008 and thereafter the stock level came down because the Domestic Industry liquidated their stocks at a loss.

Sales

180. As noted earlier, the product under consideration has witnessed rising demand in the country and domestic industry was able to enhance its sales volume in tandem with increase in demand. In fact, domestic industry enhanced its capacity during 2006-07 by over 20%.

	2005 – 2006	2006 – 2007	2007 – 2008	POI- Annualized
Total Sales Volume (MT) – Domestic	983572	1163196	1310868	1285607
Sales Value (Rs Lacs) – Domestic	***	***	***	***
Indexed	100	135	155	166

Effect of Dumped Imports on domestic prices

	2005 – 2006	2006 – 2007	2007 – 2008	POI- Annualized
Landed Value Rs. / MT	51163	58897	59565	67940
Indexed	100	115	116	133
Domestic Selling Price Rs. / MT	***	***	***	***
Indexed	100	114	117	127
Cost Rs. / MT	***	***	***	***
Indexed	100	109	112	151

181. The Authority notes that the landed value from the subject countries over the injury investigation period has increased from 100 (Base year 2005-06) to 133 during POI. The trends in the selling price of the domestic industry show similar rising trends. The landed prices of the imports from the subject countries have always been higher than the domestic selling prices of the domestic industry and hence imports were not undercutting the prices of the domestic industry. Negative price undercutting is seen throughout the injury period. In this context the domestic industry has contended that the comparison of the weighted average landed price with the weighted average selling price does not reflect the true

picture in view of the fact that the domestic prices have been pegged on the basis of the consignments coming to India at a lower price. Further, there is a time difference between orders booked by the exporter/producers from the subject countries and the time when these shipments landed into India. Considering that the prices of the subject goods significantly fluctuated during the course of the POI, any comparison on a weighted average basis is likely to give misleading picture. Domestic industry has further claimed that increase in the selling prices of the domestic industry could not be commensurate with the increase in costs. However, the trends in increase in the costs vis-à-vis corresponding increase in the selling prices show that the domestic industry has suffered price-suppression.

Price Underselling

182. The Authority notes that there is a positive price underselling for each of the subject countries. The price underselling for each of the subject countries has been carried out month-wise. The details relating to the price underselling are given in the following table:

Country	Month	MT	NIP-Rs. / MT	Landed Value (Rs. /MT)	Price Underselling-Rs. / MT	Price Underselling-(%)
Subject Countries	Apr-08	***	***	***	***	-1% - 4%
	May-08	***	***	***	***	3% - 8%
	Jun-08	***	***	***	***	9% - 13%
	Jul-08	***	***	***	***	14% - 18%
	Aug-08	***	***	***	***	7% - 11%
	Sep-08	***	***	***	***	0% - 5%
	Oct-08	***	***	***	***	1% - 6%
	Nov-08	***	***	***	***	-23% - -18%
	Dec-08	***	***	***	***	-8% - -2%
Subject Countries-Total		***	***	***	***	8% - 13%
Oman	Apr-08	***	***	***	***	-4% - 1%
	May-08	***	***	***	***	1% - 6%
	Jun-08	***	***	***	***	30% - 35%
	Jul-08	***	***	***	***	10% - 15%
	Aug-08	***	***	***	***	3% - 8%
	Sep-08	***	***	***	***	-6% - -1%
	Oct-08	***	***	***	***	-14% - 9%
	Nov-08	***	***	***	***	100% - 105%
	Dec-08	***	***	***	***	3% - 5%

Oman Total		***	***	***	***	9% - 14%
S. Arabia	Apr-08	***	***	***	***	-1% - 4%
	May-08	***	***	***	***	3% - 8%
	Jun-08	***	***	***	***	9% - 14%
	Jul-08	***	***	***	***	14% - 19%
	Aug-08	***	***	***	***	8% - 13%
	Sep-08	***	***	***	***	1% - 6%
	Oct-08	***	***	***	***	-7% - 1%
	Nov-08	***	***	***	***	-21% - -15%
	Dec-08	***	***	***	***	-6% - -1%
S. Arabia Total		***	***	***	***	10% - 15%
Singapore	Apr-08	***	***	***	***	-3% - 2%
	May-08	***	***	***	***	1% - 6%
	Jun-08	***	***	***	***	7% - 12%
	Jul-08	***	***	***	***	12% - 17%
	Aug-08	***	***	***	***	4% - 9%
	Sep-08	***	***	***	***	-3% - 2%
	Oct-08	***	***	***	***	3% - 8%
	Nov-08	***	***	***	***	-30% - -24%
	Dec-08	***	***	***	***	-19% - -12%
Singapore Total		***	***	***	***	5% - 10%

Profitability

183. The details relating to profitability are given in the following table.

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	POI- Annualized
Total Sales (MT)	983572	1163196	1310868	1285607
Indexed	100	118	133	131
Sales Value (Rs Lacs)	***	***	***	***
Indexed	100	135	155	166
Selling Price/Unit	***	***	***	***
Indexed	100	114	117	127
Cost (Rs. Lacs)	***	***	***	***
Cost /Unit	***	***	***	***
Indexed	100	109	112	151
Profit (Rs. Lacs)	***	***	***	***

Indexed	100	167	188	5
Profit/MT	***	***	***	***
Indexed	100	142	141	4
Profit/Loss (%)	***	***	***	***
Indexed	100	124	121	3

184. The Authority notes that the profitability of the domestic industry has been adversely affected during the period of investigation. During the Period of investigation, while the cost of Sales was 151 (indexed) as compared to 100 in the period 2005-06 but the selling prices could rise only from 100 to 127 during the corresponding period. In short, the domestic industry could not raise the prices commensurate with the increase in the costs during the period of investigation; as a consequence thereof there was a sharp decline in the profitability. The decline in profitability of the domestic industry is more severe as compared to immediately preceding year. The trend analysis demonstrates significant price suppression during the period of investigation.

Return on capital employed

185. It is noted that the ROCE of the domestic industry has also drastically come down over the injury investigation period.

	2005 – 2006	2006 – 2007	2007 – 2008	POI- Annualized
Capital Employed	***	***	***	***
Profit Before Interest	***	***	***	***
ROCE (%)	***	***	***	***
Indexed	100	151	170	7

Cash Flow

186. The Authority notes that the cash flow position of the domestic industry deteriorated during the period of investigation and followed the same trend as that of profitability and ROCE.

	2005 – 2006	2006 – 2007	2007 – 2008	POI- Annualized
Profit/ Loss (Rs. Lacs)	***	***	***	***
Add: Depreciation (Rs. Lacs)	***	***	***	***

Cash Flow (In Rs. Lacs)	***	***	***	***
Indexed	100	156	170	27
Cash Flow/Unit	***	***	***	***
Indexed	100	132	128	21

Employment and Wages

187. It is noted that the number of employees have marginally declined. However, the wages paid to them have increased over the injury investigation period.

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	POI- Annualized
No of Employees	***	***	***	***
Indexed	100	97	97	93
Wages Total (Rs. Lacs)	***	***	***	***
Indexed	100	108	105	108

Productivity

188. The productivity per employee has also increased over the injury investigation period. It is noted that productivity is not a cause of injury to the domestic industry.

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	POI- Annualized
Production (MT)	1285511	1639199	1710002	1517688
Employees	***	***	***	***
Production per Employee (MT)	***	***	***	***
Indexed	100	131	137	127

Growth

Growth as compared to the base year	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	POI- Annualized
Capacity Utilization	100	105	110	96
Market Share	100	103	101	98

Profitability	100	167	188	5
Cash Profit	100	156	170	27
Return on capital employed	100	151	170	7

189. It is noted that the demand in the country has increased during the injury investigation period whereas the market share of the domestic industry has not increased in tandem with the increase in demand. The market share of the domestic industry has remained stagnant as compared to the base year and has marginally come down as compared to the immediately preceding year. The capacity utilization, profitability, ROCE and cash flow have also deteriorated over the injury investigation period. It indicates that the growth the domestic industry has been affected.

Inventory	100	73	100	73
-----------	-----	----	-----	----

190. Based on the data contained in the application, the Authority notes that average inventories have declined from 100 (Base year 2005-06) to 73 in POI showing an improved off-take.

	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	POI
Opening Stock (MT)	***	***	***	***
Indexed	100	136	153	132
Closing Stock (MT)	***	***	***	***
Indexed	100	112	97	29
Average Stock (MT)	***	***	***	***
Indexed	100	122	121	73

191. The domestic industry has subsequently submitted month-wise stock position, which clearly demonstrates their claim that inventories had piled up significantly during the months of September and October 2008 and thereafter the stock level came down because the Domestic Industry liquidated their stocks at loss.

Months	Closing Stocks	Indexed
April-2008	***	100
May 2008	***	83
June 2008	***	61

July 2008	****	100
August 2008	****	142
September 2008	***	158
October 2008	****	204
November 2008	****	7
December 2008	****	28

Ability to raise capital / investment

192. The Authority notes that the domestic industry has increased its capacity. The capacity increase was last effected in the year 2006-07. The Authority also notes that since the demand of the subject goods in India is rising and is more than the capacity of the domestic industry, the imports are inevitable when domestic industry is also exporting the subject goods. But that does not mean that such imports should be at dumped prices.

193. In a scenario of demand outstripping the domestic capacity, the domestic industry would be keen to increase its capacity. However, the profitability parameters do not favourably support that the domestic industry would be able to raise capital from market for investments.

J. CAUSAL LINK

194. It was examined whether other parameters listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry. It was found as follows:

a. Imports from Third Countries: - The imports of subject goods from sources other than the subject countries except Korea RP are *de-minimis* during the period of investigation. However, the prices from Korea RP are more than the prices offered by the subject countries.

b. Contraction in Demand: - It is noted that there is no contraction in the demand during the period under consideration. On the contrary, the overall demand has increased by 32% over the injury investigation period.

c. Pattern of consumption: - No significant change in the pattern of consumption has been observed.

d. Conditions of competition: - The applicant has claimed that conditions of competition or trade restrictive practices are not responsible for the claimed injury to the domestic industry. No interested party has refuted this claim.

- e. Developments in technology: - The applicant has claimed that there is no significant change in technology, which could have caused injury to the domestic industry. No interested party has disputed this claim.
 - f. Export performance of the domestic industry: - The export performance of the domestic industry in no way has affected the financial and economic situation of the applicant in the domestic market. The injury analysis in the preceding paragraphs does not include the figures for export.
195. The Authority notes that while listed known other factors do not show injury to the domestic industry, following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports:
- a. Imports from subject countries have increased in absolute terms as well as in relation to total imports, total demand and domestic production in India.
 - b. Market share of the domestic industry has come down over the period of investigation while the demand has increased.
 - c. The prices of the domestic industry have been suppressed despite increase in demand.
 - d. There is a significant dumping margin from each of the subject countries and also there is a significant price underselling from each of the subject countries.

K. Conclusions:

196. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- (a) The product under consideration has been exported to India from the subject countries below their associated normal values.
 - (b) The domestic industry has suffered material injury in respect of the product under consideration.
 - (c) The material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries.

L. Indian industry's interest & other issues

197. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate 'injury' caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the

Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

198. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the antidumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. With a view to minimize the impact on the downstream industry, the Authority has considered it appropriate to recommend anti-dumping duty based on the lower of the dumping and injury margins. The Authority notes that the imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

M. Recommendations

199. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the Act and the AD Rules and having established definitively positive dumping margins concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries and as well as material injury thereof to the domestic industry caused by such dumped imports; the Authority is of the view that imposition of definitive duty is required to offset the dumping and 'injury' in the instant matter. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duties concerning imports of the subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.
200. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the antidumping duty equal to the amount indicated in Col 8 of the table below is recommended to be imposed concerning all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Sl. No	Heading / Subheading	Description of goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Oman	Oman	M/s Oman Polypropylene LLC	M/s Oman Polypropylene LLC	67.68	MT	US\$
2	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Oman	Oman	'Any combination other than as specified at Sr. No. 1		241.82	MT	US\$
3	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Oman	'Any other than Oman'	'Any'	'Any'	241.82	MT	US\$
4	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Any country other than countries attracting Anti-dumping duty	Oman	Any	Any	241.82	MT	US\$
5	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Advanced Polypropylene	Vinmar International Ltd.	166.20	MT	US\$
6	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Polyolefins Company	National Petrochemical Industrialization Marketing company	189.23	MT	US\$
7	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Polyolefins Company	Basell International Trading FZE	51.16	MT	US\$

indicated in Col 8 of the table below is recommended to be imposed concerning all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

8	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi European Petrochemical Company	Saudi Basic Industries Corporation	171.97	MT	US\$
9	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Yanbu Petrochemical Company	Saudi Basic Industries Corporation	87.86	MT	US\$
10	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Yanbu Petrochemical Company	M/s Exxon Mobil Chemical Asia Pacific	177.56	MT	US\$
11	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Any combination other than as specified at Sr. No.5 to 10		322.57	MT	US\$
12	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Saudi Arabia	Any other than Saudi Arabia	Any	Any	322.57	MT	US\$
13	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Any country other than countries attracting Anti-dumping duty	Saudi Arabia	Any	Any	322.57	MT	US\$
14	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Singapore	Singapore	The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd.	Sumitomo Corporation Asia Pte. Ltd.	121.28	MT	US\$
15	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Singapore	Singapore	The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd.	Toyota Tsusho (Singapore) Pte. Ltd.	295.09	MT	US\$
16	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Singapore	Singapore	The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd.	Marubeni Chemical Asia Pacific Pte. Ltd.	Nil	MT	US\$

17	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Singapore	Singapore	The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd.	Itochu Plastics Pte. Ltd.	Nil	MT	US\$
18	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Singapore	Singapore	The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd.	Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd.	28.49	MT	US\$
19	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Singapore	Singapore	Exxon Mobil Chemical Asia Pacific	Exxon Mobil Chemical Asia Pacific	38.77	MT	US\$
20	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Singapore	Singapore	Exxon Mobil Chemical Asia Pacific, Singapore	Mitsubishi Chemical Thailand (Co.) Ltd.	Nil	MT	US\$
21	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Singapore	Singapore	Any combination other than as specified at Sr. nos.14-20.		323.50	MT	US\$
22	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Singapore	Any other than Singapore	Any	Any	323.50	MT	US\$
23	39021000 and 39023000	'Polypropylene* (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene)'	Any country other than countries attracting Anti- dumping duty	Singapore	Any	Any	323.50	MT	US\$

*EPP beads (Expanded Polypropylene) is excluded from the ambit and scope of these recommendations.

205. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under Sections 3, 3A, 8B, 8C, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

206. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority